R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2024-26

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 23 । अंक : 03
01 से 15 नवम्बर 2024
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी कहानी

अकेले दम पर सत्ता नहीं...!

महाराष्ट्र में 40 और झारखंड में 24 साल से किसी दल को बहुमत नहीं

इस बार दोनों राज्यों में गठबंधन की पार्टियों में ही दिख रहा घमासान

धार्मिक स्थलों की
यात्रा अब सुखद और आसान

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

इस प्रदेश में धार्मिक पर्यटन और अन्य पर्यटन केंद्रों तक हवाई सुविधा से आवागमन को और अधिक सुलभ बना रहे हैं। पीएमश्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा अभी कुछ धार्मिक स्थलों पर प्रारंभ की जा रही है। यह सुविधा भविष्य में प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों के लिए प्रारंभ होगी।

- डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

पीएमश्री
धार्मिक पर्यटन हेली सेवा
संचालन आरंभ

इन स्थलों के लिए सेवा प्रारंभ

महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, पचमढ़ी, खजुराहो, कान्हा, इंदौर, भोपाल

बुकिंग के लिए सम्पर्क करें -

8076807095, 8076819774, Website : www.irctc.co.in, www.serbaviation.in

मध्यप्रदेश शासन

इस अंक में

डायरी

8 | बदलेगा अफसरों का वर्क कल्चर

मुख्य सचिव की कुर्सी संभालते ही अनुराग जैन ने अफसरों के वर्क कल्चर को बदलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में प्रशासनिक कसावट के लिए मुख्य सचिव कलेक्टरों को रिजल्ट ओरिएंटेड काम के...

राजपथ

10-11 | उपचुनाव में बागी...

मप्र की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का घमासान चरम पर पहुंच गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन इनके दावे को बागी और भितरघात से खतरा है। गौरतलब है कि बुधनी...

मप्र कांग्रेस

13 | कांग्रेस को मझधार...

मप्र में पिछले दो दशक से राजनीति के मझधार में फंसी कांग्रेस को अब युवा नेता निकालेंगे। इसके लिए आलाकमान ने युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष, महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अब इन युवा नेताओं को संभाग और जिलों का प्रभार...

योजना

16-17 | एक्सप्रेस-वे से आत्मनिर्भर...

देश का दिल कहलाने वाला मप्र तरक्की और समृद्धि के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में एक समान विकास की रणनीति पर काम हो रहा है। इसके लिए प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है।

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के बाद अब भाजपानीत एनडीए और कांग्रेसनीत इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र और झारखंड में अग्निपरीक्षा है। अगर पुराने चुनावों के परिणाम देखें तो महाराष्ट्र में 40 और झारखंड में 24 साल से किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यानि दोनों राज्यों में गठबंधन की सरकार बनती आ रही है और इस बार भी बनने की संभावना है। लेकिन इस बार दोनों गठबंधनों की पार्टियों में टिकट को लेकर जिस तरह का घमासान दिखा उससे तो एक बात तय है कि ये चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं।

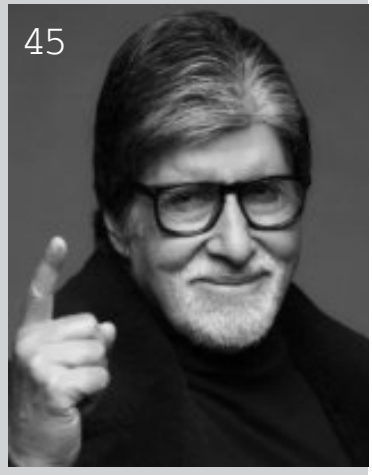

राजनीति

30-31 | मोदी युग में भाजपा...

भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इस उपलब्धि के पीछे पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कोई भी संगठन, संस्था अथवा राजनीतिक दल प्रगति के सर्वोच्च शिखर को तभी छू सकते हैं, जब उनके सामने लक्ष्य और दिशा सुस्पष्ट हो।

महाराष्ट्र

35 | पार्टियों में बंटा परिवार

महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों अपने पूरे सियासी उफान पर है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए (महायुति) और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन (महा विकास अघाड़ी) के बीच शह-मात का खेल जारी है। टिकट न मिलने पर कोई बागी हो रहा है...

झारखंड

38 | झारखंड में न्यू परिवारवाद

चुनाव के वक्त आमतौर पर नेता अपने बेटे या बेटी को सियासी विरासत सौंप देते हैं, लेकिन झारखंड में परिवारवाद का ट्रेंड बदल गया है। यहां बहुएं सियासी विरासत संभालने मैदान में उतर गई हैं। करीब आधा दर्जन सीटों पर नेताओं ने अपनी बहुओं को आगे किया है।

6-7 अंदर की बात
39 पड़ोस
41 विदेश
42 अध्यात्म
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

पाक्षिक अक्स

वर्ष-23, अंक-03, पृष्ठ-48
1 से 15 नवंबर, 2024

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788

email : akshmagazine@gmail.com
W ebsite : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

प्रमुख संवाददाता

भावना सक्सेना-भोपाल, जय मतानी-भोपाल,
हर्ष सक्सेना-भोपाल,
दक्ष दवे-इंदौर, संदीप वर्मा-इंदौर,
विपिन कंधारी-इंदौर, गौरव तिवारी-विदिशा,
ज्योत्सना यादव-गंजबासौदा, राजेश तिवारी-उज्जैन,
टोनी छाबड़ा-धार, आशीष नेमा-नरसिंहपुर,
अनिल सोडानी-नई दिल्ली, हसमुख जैन-मुंबई,
इंद्र कुमार बिन्नानी-पुणे।

प्रदेश संवाददाता

पारस सरावगी (इंदौर)
09329586555
नवीन रघुवंशी (इंदौर)
09827227000 (इंदौर)
धर्मेन्द्र कथूरिया (जबलपुर)
098276 18400
श्यामसिंह सिकरवार (उज्जैन)
094259 85070
सुभाष सोमानी (रतलाम)
089823 27267
मोहित बंसल (विदिशा)
075666 71111

क्षेत्रीय कार्यालय

नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी, फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

अपनी बात

...ताकि हर घर में उजियारा और खुशहाली रहे

गो पालदास नीरज की एक कविता की पक्तियां हैं....

जलाओ दीये पर रहे ध्यान इतना
अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए।

दशकों पुरानी इन पक्तियों पर इस बार मप्र में अमल होता दिख रहा है। मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा देने की घोषणा करते हुए लोगों से अपील की थी कि दिवाली पर वे स्थानीय निर्माताओं और विक्रेताओं से दीये सहित अन्य सामग्री खरीदें। इसके पीछे सरकार की मंशा यह थी कि इस दिवाली हर घर में उजियारा और खुशहाली रहे। खुद मुख्यमंत्री ने पहल करते हुए धनतेरस पर रेहड़ी वालों से दीये खरीदे। यही नहीं मुख्यमंत्री की पहल पर दीये, फूल-पत्ती बेचने वालों से शुल्क वसूली पर भी रोक लगा दी गई है। यानि मप्र में इस दिवाली पर दीये, दीपमालाएं, फूल-पत्ती, प्रसाद, फुलझड़ी, रंगोली, सजावट के अन्य सामान बेचने वालों से कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ने सभी जिला पंचायत सीईओ को किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लेने के आदेश दिए हैं। साथ ही कारोबार के लिए पंचायत की ओर से इंतजाम कराने को कहा है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के आदेश में कहा गया है दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में 29 अक्टूबर से 11 नवंबर (ग्यारस पर्व) तक यह आदेश प्रभावशील रहेगा। प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतें पथ विक्रेताओं और आम नागरिकों की सुविधा के लिए बाजारों की साफ-सफाई, पेयजल, शौचालय सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी। इसमें रेहड़ी पर व्यवसाय करने वाले, फुटपाथ पर बिक्री करने वाले, छोटे व्यवसायियों, ग्रामीण कारीगरों एवं गरीब महिलाओं को अपना सामान बेचने में आसानी होगी। सरकार के इस निर्देश के बाद स्थानीय सामग्री बनाने वालों की दीप पर्व पर खुशियां दोगुनी हो गई हैं। आज भी कई कुम्हार परिवार हैं, जो अपने इस पुस्तैनी काम को कर रहे हैं, जो बाजारों में रंग-बिरंगे मिट्टी के मटके, रंगोली, मूर्तियां, गुल्लक, करबे, दीये बनाकर इसे जिंदा रखे हुए हैं। खास बात यह है कि यह सारी चीजें कम दाम पर मिल जाती हैं। अब इस बार प्रशासन ने उनकी सुविधा का ख्याल रखा है। मिट्टी के बर्तन आदि बाजार के मुख्य स्थानों में बेचने के लिए जगह उपलब्ध कराई गई है। साथ ही किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जा रहा है। गौरतलब है कि मिट्टी का सामान बेचने के लिए कारीगरों द्वारा अपनी मोटर साईकिल, हाठ-ठेले एवं साईकिल से जाकर दूर हाट बाजारों तक जाना पड़ता है। बाजारों में आने वाली चाइनीज लाईटों, दीयों ने मिट्टी के दीयों का स्थान लिया है। लेकिन स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जो अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने की है वह प्रशंसनीय है। उन्होंने इन स्थानीय उत्पादों को स्थानीय लोगों से खरीदने का आव्हान भी किया है। इससे पुस्तैनी विरासत एवं स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कुम्हारों को उनकी मेहनत का सही दाम मिलेगा। मिट्टी के दीये, बर्तन प्रकृति संरक्षण की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। मप्र सरकार की इस पहल की सर्वत्र सराहना हो रही है। आलम यह है कि सरकार के आव्हान के बाद बाजारों में लोगों ने स्थानीय उत्पादों की जमकर खरीदारी की है। स्थानीय व्यवसायियों का कहना है कि सरकार अगर इसी तरह सुविधाएं और संरक्षण देती रहेगी, तो वोकल फॉर लोकल का सपना जल्द साकार होगा। गौरतलब है कि मप्र सहित देशभर में पिछले एक दशक से चाइनीज उत्पादों के विरोध का नारा दिया जा रहा है। लेकिन पहली बार मप्र में सरकार ने ऐसी पहल की है कि लोग स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को खरीद रहे हैं। मप्र सरकार ने तहबाजारी पर जो प्रतिबंध लगाया है, उस संदर्भ में व्यवसायियों का कहना है कि अगर इसे सरकार हमेशा के लिए लागू करती है तो पुस्तैनी विरासत और स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा मिलेगा।

- राजेन्द्र आगाल

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

बजट की आस

मप्र की सरकार पर भारी कर्ज है। वहीं सरकार हर साल कर्ज लेकर विकास कार्यों पर खर्च कर रही है। ऐसे में सरकार का फोकस इस बात पर है कि केंद्र सरकार से मिलने वाले बजट को समय पर लाया जाए। इसके लिए अब मंत्रियों के साथ विभागीय अफसर भी जाएंगे।

● **अखिलेश सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

कड़ी कार्रवाई हो

भोपाल ड्रग्स मामले में एक के बाद एक बड़ा खुलासा हो रहा है। बताया जा रहा है कि ड्रग्स 1800 नहीं बल्कि करीब 4 हजार करोड़ की थी। ड्रग्स मामले के तार राजस्थान से जुड़े बताए जा रहे हैं। प्रदेश की मोहन सरकार को इस ओर कठोरता से कार्रवाई करनी चाहिए।

● **निधि ठाकुर,** जबलपुर (म.प्र.)

नाराज हुए पदाधिकारी

सत्ता और संगठन ने निगम-मंडल, बोर्ड और प्राधिकरणों में इस साल इन सार्वजनिक उपक्रमों में राजनीतिक नियुक्तियां ना करने का फैसला किया है। यह फैसला भाजपा के दिल्ली में बैठे आला नेताओं से चर्चा करने के बाद लिया गया है। इससे संगठन के कई पदाधिकारी नाराज हैं।

● **प्रवेश शर्मा,** ग्वालियर (म.प्र.)

हरियाणा चुनाव में दिखा भाजपा का दम

हरियाणा में विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा ने ऐसी कोई बड़ी रेवड़ी भी नहीं बांटी, जैसे कि मप्र में बांटी थी। भाजपा की रणनीति साफ थी कि प्रभावशाली जाट वोटों का बंटवारा करो और एंटी जाट वोटों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करो। वही होता दिख भी रहा है। पार्टी ने न केवल अपना वोट बैंक बचाया बल्कि उस जाट लैंड में भी सेंध लगा दी, जहां से कांग्रेस बंपर समर्थन की उम्मीद लगाए हुए थी। हरियाणा के यादव बहुल अहीरवाल अंचल में भाजपा की भारी जीत के पीछे भाजपा द्वारा मप्र में एक यादव डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन, अग्निवीर जैसे मुद्दे जोर-शोर से उठाए, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी।

● **महेंद्र सिंह,** राजगढ़ (म.प्र.)

बढ़ेगा पर्यटन

सातपानी अभयारण्य के टाइगर रिजर्व बनने से पर्यटन बढ़ेगा। स्थानीय लोगों के लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। इस अभयारण्य में वर्ष 2022 की गणना के अनुसार कुल 3 हजार 123 वन्यप्राणी हैं। इनमें 56 बाघ, 70 तेंदुए, 8 भेडिया, 321 चिंकारा, 1433 नीलगाय, 568 सांभर और 667 चीतल हैं। सातपानी टाइगर रिजर्व के कोर क्षेत्र में केवल 3 वन ग्राम ही शामिल किए जाएंगे। कोर में कोई भी राजस्व ग्राम नहीं होगा।

● **नितेश साहू,** रायसेन (म.प्र.)

संवरेगा वल्लभ भवन...

वल्लभ भवन (मंत्रालय) में आगजनी की घटना दोबारा न हो, इसके लिए बड़े स्तर पर इसको सुरक्षित बनाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने 71 करोड़ 35 लाख रुपए का टेंडर जारी किया गया है। इसमें कुल राशि का बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वर्क पर खर्च किया जाएगा। इसी वर्ष 9 मार्च को वल्लभ भवन की पुरानी बिल्डिंग के पांचवें फ्लोर पर अचानक आग लगने की घटना हुई थी। इस घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया। एक महीने बाद इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट भी आ गई।

● **बिस्मिल पुरोहित,** भोपाल (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

गले की फांस बने शक्तिमान गणेश

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों बड़े धर्म संकट में बताए जा रहे हैं। उनका धर्म संकट मंत्री गणेश जोशी को लेकर है। देहरादून की एक अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मंत्री गणेश जोशी पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मुकदमा चलाने अथवा न चलाने की बाबत वह तीन माह के भीतर फैसला लेकर अदालत को अवगत कराएं। यह तीन माह की मियाद 8 अक्टूबर को पूरी हो चुकी है। लेकिन धामी मंत्रिमंडल ने इस मुद्दे पर अभी तक चर्चा नहीं की है। अब विपक्षी दल कांग्रेस मुख्यमंत्री पर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति को लेकर जमकर निशाना साध रही है। बेचारे धामी करें तो क्या करें? केदारनाथ का उपचुनाव घोषित हो चुका है। ऐसे में यदि सरकार अपने मंत्री पर मुकदमा चलाने की सहमति देती है तो मंत्री के पास इस्तीफा देने के सिवा कोई रास्ता बचेगा नहीं और यह इस्तीफा केदारनाथ उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बन उभरेगा। यदि स्वीकृति नहीं देते हैं तो भी विपक्ष इसे उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने से पीछे नहीं हटेगा। धामी के लिए उनके शक्तिमान फेम मंत्री गले की ऐसी फांस बन चुके हैं जिसको न तो मुख्यमंत्री उगल पा रहे हैं, न निगल पा रहे हैं।

हरियाणा कांग्रेस के खलनायक हुड्डा

विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद हरियाणा कांग्रेस में घमासान की शुरुआत हो चुकी है। ज्यादातर नेता इस हार को हुड्डा की हठधर्मिता और ठीक चुनाव प्रचार के समय कुमारी शैलजा के कोपभवन में चले जाने से जोड़ रहे हैं। 24 अकबर रोड में इन दिनों चर्चा इस बात को लेकर गर्म है कि पार्टी आलाकमान भूपिंदर सिंह हुड्डा की बातों और उनके दबाव में आखिर क्यों आ जाता है? कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल की भूमिका पर भी अब सवाल उठने लगे हैं। कहा-सुना जा रहा है कि वेणुगोपाल ने भी कई ऐसों को टिकट दिलाने का काम किया जो जमीनी स्तर पर निलबट्टे सन्नाटा थे और इसी के चलते ऐसे सभी चुनाव हार गए। हुड्डा के प्रति नाराजगी का आलम यह है कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कैप्टन अजय सिंह ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से तो इस्तीफा दिया ही, पार्टी भी छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर डाला है। खबर यह भी जोरों पर है कि यदि हुड्डा को पार्टी आलाकमान अब साइडलाइन नहीं करता है तो कुमारी शैलजा समेत कई बड़े नेता पार्टी छोड़ने का मन बना रहे हैं।

इंडिया गठबंधन में पड़ती दरार

गत लोकसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्षी दलों ने एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन बनाने का ऐलान किया था। इस गठबंधन में कांग्रेस के साथ 27 विपक्षी दल शामिल हैं। उप्र की समाजवादी पार्टी भी इसका हिस्सा है। लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन ने 80 सीटों में से 43 सीटें जीतकर इतिहास रचने का काम कर दिखाया। अब लेकिन प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के लिए जल्द ही होने जा रहे उपचुनाव इस गठबंधन में दरार पड़ने की तरफ इशारा कर रहे हैं। लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में चर्चा गर्म है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मात्र दो सीटें देने की बात कर रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस मुस्लिम बाहुल्य पांच सीटों पर अपनी दावेदारी से पीछे हटने को तैयार नहीं है। जानकारों का कहना है कि सपा गाजियाबाद और खैर विधानसभा सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने को तैयार है लेकिन कांग्रेस तीन अन्य सीटों पर भी अपना प्रत्याशी खड़ा करने पर अड़ी है। इन दो दलों की लड़ाई मानो काफी नहीं थी कि सीपीआई ने भी चार सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर इंडिया गठबंधन में शामिल दलों की रार को सामने ला दिया है। सीपीआई ने दलित नेता आरपी सिंह को तो मीरापुर विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी तक घोषित कर डाला है। खबर यह भी गर्म है कि भाजपा के भीतर भी इन 10 सीटों में प्रत्याशी चयन को लेकर भारी घमासान चल रहा है। कहा-सुना जा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस दफे केंद्र द्वारा थोपे गए प्रत्याशियों को आंख बंद कर टिकट के लिए कतई तैयार नहीं हैं। कुल मिलाकर ये उपचुनाव देश की राजनीति को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं।

अजित को गुस्सा क्यों आया?

11 अक्टूबर के दिन महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने उपमुख्यमंत्री अजित पवार का पारा गर्म कर दिया। अब देश की आर्थिक राजधानी में अफवाहों का बाजार गर्म है। कहा-सुना जा रहा है कि अजित पवार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के मध्य इस बैठक में तीखी तकरार हुई। इतनी तीखी कि पवार कैबिनेट मीटिंग छोड़ बाहर आ गए। तकरार का असल कारण तो सामने नहीं आया है लेकिन सत्ता के गलियारों में बड़ी कानाफूसी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट के सामने कई नई जनकल्याणकारी योजनाएं रखी थीं। शिंदे चाहते थे कि इन योजनाओं को तत्काल मंजूरी मिल सके ताकि चुनाव से पहले राज्य सरकार इनकी घोषणा कर सके। इन योजनाओं में एक योजना अजित पवार के गृहक्षेत्र बारामती से जुड़ी थी। जानकारों का दावा है कि अजित पवार के चाचा शरद पवार इस योजना को लागू कराना चाह रहे हैं और उन्होंने ही एकनाथ शिंदे पर इसे लागू करने का दबाव बनाया लेकिन अपने बागी भतीजे अजित को इसकी भनक तक नहीं लगने दी।

संकट में नौकरशाह

झारखंड में 24 जिले हैं। प्रदेश में जिलाधिकारियों को उपायुक्त कहकर पुकारा जाता है। गत दिवस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जारी किया गया एक आदेश राज्य के 24 उपायुक्तों के गले की फांस बनने लगा है। सोरेन ने उपायुक्तों को जारी आदेश में कहा है कि वे ऐसे भाजपा नेताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज करें जो चुनाव आयोग के मानदंडों का खुला उल्लंघन करते हुए वोटरों को आर्थिक लालच देकर उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। दरअसल, भाजपा इन दिनों राज्यभर में महिला वोटरों से एक फार्म भरवा रही है जिसमें यह कहा गया है कि प्रदेश में भाजपा सरकार बनते ही महिलाओं के बैंक खातों में प्रतिमाह 2100 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इसे भाजपा ने गोगो दीदी योजना नाम दिया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि जब तक आचार संहिता लागू नहीं हो जाती है तब तक चुनाव आयोग के निर्देशों के उल्लंघन का प्रश्न ही नहीं उठता है। मुख्यमंत्री सोरेन ने पूरे मसले पर कड़ा रुख अख्तियार कर अधिकारियों को बड़े धर्मसंकट में डाल दिया है।

10 लाख मिलने पर ही ब्रश

शीर्षक पढ़कर आपको आश्चर्य लग रहा होगा, लेकिन प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा जोरों पर चल रही है कि 2018 बैच के एक आईएएस अधिकारी ऐसे हैं, जो हर दिन सुबह 10 लाख रुपए कमाने के बाद ही ब्रश करते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये साहब वर्तमान में ग्वालियर-चंबल अंचल के एक जिले में नगर निगम कमिश्नर की कुर्सी पर बैठे हैं। साहब का पूरा फोकस लक्ष्मीजी से अपनी तिजोरी भरने पर है। बताया जा रहा है कि कुर्सी पर बैठने के साथ ही उन्होंने कमीशन का रेट इस कदर बढ़ा दिया है कि उसकी शिकायत ऊपर तक पहुंच गई है। बताया जाता है कि उक्त अधिकारी जिस जगह पदस्थ है, वहां पहले आधा फीसदी कमीशन चलता था, जिसे बढ़ाकर साहब ने 3 फीसदी कर दिया है। सूत्र बताते हैं कि साहब लक्ष्मीजी को बटोरने में इस कदर मशगूल हैं कि वे वरिष्ठों को भी भाव नहीं दे रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि अभी हाल ही में एक वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें फोन करके एक ठेकेदार का पेमेंट करने को कहा। इस पर साहब ने आव देखा न ताव और उनसे साफ-साफ शब्दों में कह दिया कि सारा माल भोपाल में बैठे अफसर खा जाएंगे तो हम क्या करेंगे। बताया जाता है कि साहब के ये शब्द सुनकर वरिष्ठ अधिकारी भी सुन्न हो गए। लेकिन इससे साहब पर कोई असर नहीं पड़ा है और वे दोनों हाथ से कमाई करने में पूरी शिद्दत के साथ जुटे हुए हैं।

मंत्रीजी को भाए बड़े साहब

प्रदेश की राजनीति में कद्दावर हैसियत वाले एक नेताजी जब से मंत्री बने हैं, उनकी कार्यप्रणाली लगातार चर्चा में है। वैसे माननीय पूर्व में भी वर्षों पहले मंत्री रह चुके हैं। लेकिन इस बार वे कुछ अजब-गजब कारणों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। साहब के पास बड़ा विभाग है। यह विभाग नगरों के विकास का जिम्मा संभालता है। इसके तहत विभागीय मंत्री को नगरीय विकास के अध्ययन के लिए विदेश यात्रा पर जाना है। बताया जाता है कि मंत्रीजी की इस यात्रा में उनके साथ विभागाध्यक्ष और मंत्रीजी के गृह जिले के एक अफसर का भी नाम है। लेकिन सूत्रों का कहना है कि मंत्रीजी इन दोनों अफसरों के साथ विदेश यात्रा पर जाने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर मैं विदेश यात्रा पर जाऊंगा तो विभाग के बड़े साहब यानि एसीएस के साथ जाऊंगा। मंत्रीजी का यह रुख देखकर हर कोई हैरान है। इसकी वजह यह है कि अगर किसी विभाग के मंत्री और सबसे बड़े अधिकारी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो विभाग की गतिविधियां प्रभावित होने की संभावना रहती है। लेकिन मंत्रीजी की इच्छा है कि अगर वे विदेश जाएंगे तो बड़े साहब के साथ ही। अब देखना यह है कि मंत्रीजी स्पेन जा पाते हैं या नहीं।

रिचार्ज में मिली जोन की कुर्सी

प्रदेश में हाल ही में 1997 बैच के एक आईपीएस अधिकारी को एक रेंज का आईजी बनाकर भेजा गया है। साहब के बारे में कहा जा रहा है कि पूर्व में साहब ने जिस जगह पदस्थापना के लिए पैसा दिया था, वहां वे पदस्थ तो कर दिए गए, लेकिन चल नहीं पाए। ऐसे में उनके कूपन के रिचार्ज में उन्हें जोन की कुर्सी मिली है। गौरतलब है कि कहने को तो पुलिस में चुस्त-दुरुस्त और हल्के-फुल्के लोगों की भर्ती होती है। लेकिन ये साहब भारी-भरकम कद-काठी वाले हैं। ऐसे में साहब को सरकार की प्राथमिकता वाले बड़े जिले की कमान मिलने पर हर कोई आश्चर्यचकित है। साहब के करीबी यह बात कहने में तनिक भी हिचक नहीं कर रहे हैं कि भारी-भरकम शरीर के साथ साहब पूरे रेंज में कैसे घूम पाएंगे। साहब की इस नई पदस्थापना को लेकर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। ऐसे ही लोगों का कहना है कि साहब ने एक कमाऊ विभाग में पदस्थ होने के लिए बड़ी कीमत चुकाई थी। साहब को जब वहां पदस्थ किया गया तो साहब भी खुशी से नहीं समाए। लेकिन कुछ दिन बाद ही साहब की सारी खुशी हवा होने लगी क्योंकि वे उस विभाग में चल नहीं पा रहे थे। ऐसे में साहब ने फिर जुगाड़ लगाई और अपना तबादला दूसरी जगह करने की गुहार लगाई। सूत्रों का कहना है कि पहली बारी में साहब ने बड़ी रकम चुकाई थी, इसलिए उसी के एवज में उन्हें आईजी की कुर्सी दी गई है। अब देखना यह है कि साहब वहां टिक पाते हैं कि नहीं।

पाड़े से दूध निकाल रहे

पाड़े से दूध निकालने वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, यानि असंभव को संभव करने का प्रयास। यह प्रयास ग्वालियर-चंबल अंचल से आने वाले एक मंत्रीजी कर रहे हैं। मंत्रीजी ने जबसे खेती किसानी के विकास वाले एक विभाग की कमान संभाली है, तबसे उन्होंने अति मचा रखी है। मंत्रीजी की करतूतों की कथा कई बार अखबारों में छप चुकी है, लेकिन उसके बाद भी वे शांत नहीं हैं। सूत्र बताते हैं कि मंत्रीजी के पास विभाग से संबंधित एक निगम की भी कमान है। घाटे से उबरे निगम में मंत्रीजी जमकर मनमानी कर रहे हैं। मंत्रीजी की मनमानी का आंकलन इसी से लगाया जा सकता है कि उन्होंने विभाग में एक तथाकथित पत्रकार से एक ठेकेदार के खिलाफ शिकायत करवा दी, ताकि उसका पेमेंट रोक दिया जाए। लेकिन जब इस संदर्भ में पड़ताल की गई तो पता लगा कि शिकायत करने वाला पत्रकार नहीं है। यह तो महज कुछ उदाहरण हैं। मंत्रीजी के ऐसे कारनामों से विभाग हालाकान है। विभाग के अधिकारियों के साथ ही ठेकेदार भी मंत्रीजी की मंशा पूरी करने में परेशान हो रहे हैं।

पावती देना बंद

प्रदेश में एक माननीय सरकारी विभागों के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। माननीय से आजीज आकर कई विभागों ने उन पर नकेल कसने की कोशिश भी शुरू कर दी है। माननीय मालवा-निमाड़ क्षेत्र के एक जिले की सुरक्षित सीट से इस बार विधायक चुने गए हैं। अपनी पार्टी के इकलौते विधायक ये माननीय सरकार और प्रशासन को परेशान करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल, साहब छोटी-छोटी बातों पर विभागों में आवेदन लगाते रहते हैं। आलम यह है कि साहब जिस विभाग की तरफ रुख करते हैं, वहां के अधिकारी-कर्मचारी परेशान हो जाते हैं। सूत्रों का कहना है कि साहब की मनमानी की बात जब एक विभाग के अपर मुख्य सचिव के पास पहुंची तो उन्होंने अपने अधीनस्थों को निर्देशित कर दिया है कि अगर माननीय आवेदन देते हैं तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग उनसे आवेदन ले लो, लेकिन पावती देने की कोई जरूरत नहीं है। साहब के निर्देश के बाद उक्त विभाग के अधिकारी-कर्मचारी राहत महसूस कर रहे हैं, लेकिन अन्य विभागों के लोग अभी भी परेशान हैं।

बदलेगा अफसरों का वर्क कल्चर

मुख्य सचिव की कुर्सी संभालते ही अनुराग जैन ने अफसरों के वर्क कल्चर को बदलने की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश में प्रशासनिक कसावट के लिए मुख्य सचिव कलेक्टरों को रिजल्ट ओरिएंटेड काम के कल्चर का पाठ पढ़ाएंगे। इसके पीछे अनुराग जैन की सोच है कि कलेक्टर जब तक जनता के बीच नहीं जाएंगे, तब तक उन्हें जनसमस्याओं की पूरी जानकारी नहीं होगी। जैन ने अफसरों को निर्देश दिए कि वो इन योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों का ई-केवाईसी कराने के लिए अभियान चलाने को भी कहा। मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों का जल्द निपटारा करने पर भी जोर दिया। बैठक में सुशासन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व बढ़ाने और मानव संसाधन प्रबंधन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। इस दौरान वरिष्ठ अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों से जुड़ी समस्याएं, नए तरीके और योजनाओं को लागू करने के बारे में जानकारी साझा की।

विभागाध्यक्षों की बैठक में दिखाया आईना

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कामकाज संभालते ही अपनी काम करने की शैली को स्पष्ट कर दिया है। वे प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था में कसावट के लिए काम करने का प्लान बना चुके हैं। विभागाध्यक्षों की बैठक में मुख्य सचिव ने कईयों को आईना दिखाया। इस दौरान धारा-16 की विकास अनुमति देने वाले साहब पूरे समय मुंह लटकाकर बैठे रहे। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने ये पूरी तरह से जाहिर कर दिया कि अफसरों को अपनी वर्किंग में क्या बदलाव करने होंगे। अनुराग जैन ने अफसरों से कहा अब फाइल और पर्ची के जमाने लद गए हैं। अफसर अब टेक्नोफ्रेंडली बनें। अफसरों का पूरा जोर कॉर्डिनेशन पर होना चाहिए। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्किंग होनी चाहिए कि जो प्रपोजल आप लाए हैं, उसके बेनिफिट मालूम हों। टेक्नीक का बेहतर से बेहतर इस्तेमाल करके अफसर खुद को समय के साथ अपग्रेड करें। उन्होने सलाह भी दी कि भारत सरकार के अफसरों से अच्छा संपर्क और समन्वय होना चाहिए।

खुद को सर्वज्ञानी समझने की भूल न करें

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को समझाइश भी दी है कि हमेशा खुद को पूर्ण जानकार समझने के भाव से बचें। जो अलग-अलग क्षेत्रों के लोग आ रहे हैं, वे भी जानकारियों से लैस होते हैं। उनके अनुभव से हमें सीखना चाहिए। उनसे कॉर्डिनेशन करना चाहिए। अनुराग जैन ने कागज दौड़ाने से ज्यादा संवाद पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जरूरी ये है कि अधिकारियों का बेहतर संवाद हो। एक दूसरे से हर विषय में कागज चलाने से बेहतर है एक-दूसरे से सुलभ संवाद हो।

अधिकारियों से बेबाक अंदाज में सवाल-जवाब

मुख्य सचिव ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कामकाज पर सवाल उठाए। उन्होंने मातृ वंदन योजना सहित अन्य विभाग की योजनाओं पर अधिकारियों से खुलकर बात की। इस दौरान उन्होंने बेबाक अंदाज में अधिकारियों से सवाल-जवाब भी किए। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि आपके यहां शार्क बैठे हैं। हम काम कर रहे हैं, पैसा उनकी जेब में जा रहा है। पारदर्शिता लाने की सख्त जरूरत है। जनता के प्रति जिम्मेदारी से गंभीर और जवाबदेह होना होगा।

बिना नेमप्लेट वाली मैडम

प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में एक डिप्टी सेक्रेटरी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। दरअसल, हेल्थ विभाग में पदस्थ उक्त डिप्टी सेक्रेटरी ऐसी हैं जो अपने कमरे के बाहर नेमप्लेट नहीं लगाती हैं। ऐसे में उनसे मिलने अगर कोई आता है तो उसे इधर-उधर भटकना पड़ता है। लेकिन मैडम पर इसका तनिक भी असर नहीं पड़ता है। वे अपनी डफली-अपना राग अलापने में मस्त रहती हैं।

एक से भले दो

प्रदेश सरकार ने संभाग और जिलों के परिसीमन के लिए जिस परिसीमन आयोग का गठन किया है, उसमें एक और आईएएस अधिकारी को पदस्थ किया गया है। गौरतलब है कि आयोग का अध्यक्ष रिटायर्ड आईएएस अधिकारी मनोज श्रीवास्तव को बनाया गया है, जो मुख्य सचिव अनुराग जैन के काफी करीबी रहे हैं। वहीं अब उनके सहयोगी के रूप में रिटायर्ड प्रमोटी आईएएस अधिकारी मुकेश शुक्ला को पदस्थ किया गया है।

सीएम के पांचवें ओएसडी नियुक्त

संघ की विचारधारा वाले आईपीएस राजेश

हिंगणकर को मुख्यमंत्री का पांचवां ओएसडी नियुक्त किया गया है। हिंगणकर 2006 के आईपीएस अधिकारी हैं। देश के सबसे बड़े और मजबूत मुख्यमंत्री सचिवालय में एक और अफसर की आमद होने वाली है। सूत्रों का कहना है कि 2008 बैच के आईएएस अधिकारी गोपाल चंद्र डाड मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के ओएसडी बनाए जाएंगे।

पहले नियुक्ति फिर हटाया

ग्वालियर-चंबल अंचल के एक प्रमुख जिले के कलेक्टर ने सरकार के दिशा-निर्देशों को दरकिनार कर एक संविदा वाले अधिकारी को जिला पंचायत सीईओ का काम सौंप दिया। हालांकि मामला विवादित होने के बाद उन्हें तत्काल हटा दिया गया। गौरतलब है कि 9 मई 2023 को सरकार ने सर्कुलर जारी किया था कि जिला पंचायत सीईओ का चार्ज एसडीएम स्तर के अधिकारियों को दिया जाए। लेकिन कलेक्टर साहब ने संविदा वाले को चार्ज दे दिया। मामला संज्ञान में आते ही कलेक्टर ने अपना ही आदेश निरस्त कर दिया। उधर, सरकार ने एक एसडीएम को सीईओ बनाने का आदेश तत्काल निकाल दिया।

● राजेंद्र आगाल

कौन बनेगा मप्र का नया डीजीपी

मप्र में पुलिस के नए मुखिया की तलाश तेज हो गई है। दरअसल, 30 नवंबर 2024 को वर्तमान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लिहाजा, मप्र सरकार ने नए डीजीपी की तलाश शुरू कर दी है। इसके साथ ही सरकार में कई अधिकारियों के नामों को लेकर मंथन का दौर चला। इस संबंध में राज्य सरकार ने केंद्र में डीओपीटी को 9 नामों का पैनल भेज दिया है। गाइडलाइन के अनुसार 3 महीने पहले पैनल भेजा जाना था। हालांकि, 40 दिन पहले राज्य सरकार ने 9 नामों का पैनल भेजा। इनमें उन अधिकारियों के नाम शामिल हैं, जिन अधिकारियों की सेवा को 30 साल पूरा हो चुका है। इसके साथ ही इन सबका रिकॉर्ड और पूरा ब्यौरा भी भेजा गया है। पीएचक्यू की ओर से बताया गया है कि रिकॉर्ड तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया गया है। इसके साथ ही गृह विभाग ने तमाम अधिकारियों के नाम का पैनल केंद्र सरकार को भेज दिया है। माना जा रहा है कि इस पैनल में से जिन तीन नामों का आखिरी पैनल बनेगा, उसमें अरविंद कुमार, कैलाश चंद्र मकवाना और अजय कुमार शर्मा का नाम होगा। क्योंकि मप्र में अभी तक नियमानुसार ही डीजीपी का चयन होता आया है।

30 नवंबर को वर्तमान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसलिए शासन का लक्ष्य है कि इससे पहले ही नए अफसर का चयन किया जाए। जिन 9 अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए हैं, वे सभी 30 से अधिक साल प्रशासनिक सेवा कर चुके हैं। उनमें डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैलाश चंद्र मकवाना, डीजी ईओडब्ल्यू अजय कुमार शर्मा, डीजी जेल जीपी सिंह, स्पेशल डीजी आरएपीटीसी इंदौर वरुण कपूर, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी उपेंद्र कुमार जैन, स्पेशल डीजी प्रोविजन आलोक रंजन, स्पेशल डीजी महिला सेल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव और स्पेशल डीजी योगेश मुद्गल का नाम शामिल है। देश में पुलिस सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिशा-निर्देश हैं कि वह किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर नियुक्त न करें। डीजीपी या पुलिस कमिश्नर के पद पर नियुक्ति के लिए सरकार जिन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के नाम पर विचार कर रही होगी, उनके नाम यूपीएससी को भेजे जाएंगे। इन्हें शॉर्टलिस्ट कर यूपीएससी तीन सबसे उपयुक्त अधिकारियों की सूची राज्य को सौंपेगा। राज्य सरकार इनमें से किसी को भी पुलिस प्रमुख नियुक्त कर सकेगी। पुलिस प्रमुख के रिटायरमेंट से तीन महीने पहले यह सिफारिश यूपीएससी को भेजनी होगी। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने 14 अक्टूबर को अस्थायी पुलिस प्रमुखों की नियुक्ति के मामले में आठ राज्यों को अवमानना नोटिस जारी किया। झारखंड, उप्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, बिहार, राजस्थान और पश्चिम बंगाल सरकार ने नियमों को दरकिनार कर अस्थाई या कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति की है।

मप्र में नए नियमों के तहत, डीजीपी पद के लिए उन्हीं अधिकारियों के नाम यूपीएससी को भेजे गए हैं, जिनकी सेवा अवधि कम से कम छह माह शेष हो। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पैनल को भेजी गई वरिष्ठता सूची में शामिल होने के बावजूद भी तीन सीनियर आईपीएस अफसरों का नाम शामिल नहीं किया गया है। यह अफसर हैं स्पेशल डीजी पुलिस सुधार शैलेश सिंह, स्पेशल डीजी रेल सुधीर कुमार साही और स्पेशल डीजी प्रशासन विजय कटारिया। दरअसल यह तीनों अधिकारी अगले 6 महीने के भीतर रिटायर हो रहे हैं। नियम यह है कि जिन अधिकारियों का कार्यकाल 6 महीने से कम होता है उनका नाम पैनल में शामिल नहीं किया जाता है।

माना जा रहा है कि पैनल को लेकर यूपीएससी द्वारा नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की जाएगी। जिसमें यूपीएससी के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित कोई सदस्य, केंद्रीय गृह मंत्रालय का एक प्रतिनिधि, राज्य के मुख्य सचिव, वर्तमान डीजीपी सदस्य और अपर मुख्य सचिव के रूप में भाग लेंगे। पैनल मिलने के बाद अब यह बैठक कभी भी आयोजित की जा सकती है। यूपीएससी की बैठक में 9 नाम में से तीन नाम का पैनल तैयार किया जाएगा। जिसे राज्य सरकार को भेजा जाएगा। राज्य सरकार उन तीन नाम में से ही एक नाम का चयन कर आदेश जारी करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक इन तीन नामों में से ही एक नाम को फाइनल करना होगा।

● **अरविंद नारद**

अजय कुमार और कैलाश दावेदारों में सबसे आगे

पैनल में भेजे गए 9 नाम पर नजर डाली जाए तो पहले तीन नाम वरिष्ठता के आधार पर यूपीएससी चयन कर सकता है। चयन की प्रक्रिया के तहत स्पेशल डीजी के जो नाम यूपीएससी को भेजे गए हैं, इनमें 1988 बैच के अरविंद कुमार और कैलाश मकवाना, 1989 बैच के अजय कुमार शर्मा प्रमुख हैं। बताया जा रहा है कि अरविंद कुमार सबसे पहले मई 2025 में, कैलाश मकवाना दिसंबर 2025 में और अजय कुमार शर्मा अगस्त 2026 में रिटायर होंगे। ऐसी स्थिति में अजय कुमार शर्मा या कैलाश मकवाना की डीजीपी बनने की संभावना सबसे अधिक है। अरविंद कुमार की सेवानिवृत्ति को केवल 6 महीने बचेंगे इसलिए शायद सरकार उनके नाम पर विचार ना करे। हालांकि यह भी नियम है कि राज्य सरकार जब इन तीनों नाम में से एक नाम फाइनल करेगी तो उस अधिकारी को डीजीपी का कार्यभार की तिथि से 2 साल की अवधि के लिए डीजीपी के रूप में पूरा कार्यकाल मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अनुसार, राज्य सरकार को इन तीन नामों में से ही एक नाम को चुनकर आदेश जारी करना अनिवार्य होगा।

मप्र की दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का घमासान चरम पर पहुंच गया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं। लेकिन इनके दावे को बागी और भितरघात से खतरा है। गौरतलब है कि बुधनी सीट पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने और श्योपुर जिले की विजयपुर सीट कांग्रेस विधायक रामनिवास रावत के भाजपा में शामिल होने से खाली हुई है। ऐसे में यह उपचुनाव दोनों पार्टियों के लिए चुनौती बना हुआ है।

उपचुनाव में बागी-भितरघात बड़ी चुनौती

मप्र में बुधनी और विजयपुर दो विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में इस बार भाजपा और कांग्रेस दोनों को भितरघात और बगावती तेवरों का सामना करना पड़ा है। बुधनी से भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव का जहां पार्टी के कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं तो कांग्रेस के बागी और समाजवादी पार्टी से नामांकन भरने वाले अर्जुन आर्य कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार राजकुमार पटेल के लिए बड़ा चैलेंज बन गया है। बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है। रमाकांत भार्गव की उम्मीदवारी का ऐलान होते हुए बुधनी के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह राजपूत ने बागी तेवर अपना लिए हैं, वह पार्टी की बैठकों से लगातार दूरी बनाए हुए हैं। 20 साल तक बुधनी विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के भोपाल आवास पर बुधनी उपचुनाव को लेकर हुई बैठक में भी सुरेंद्र सिंह राजपूत नहीं पहुंचे।

बुधनी में भाजपा कार्यकर्ता भी रमांकात भार्गव की उम्मीदवारी का खुला विरोध कर रहे हैं और वह खुले तौर पर प्रत्याशी बदलने की मांग कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बुधनी उपचुनाव के सह प्रभारी बनाए गए शिवराज के करीबी पूर्व विधायक रामपाल सिंह के भैरूंदा दौरे के दौरान खुला विरोध कर दिया। रामपाल सिंह ने जब कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की तो कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कह दिया कि उन्हें रमाकांत भार्गव जैसा प्रत्याशी मंजूर नहीं है और कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण रामपाल सिंह को अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। बुधनी में भाजपा उम्मीदवार रमाकांत भार्गव के बढ़ते विरोध के बाद अब शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान खुद डैमेज कंट्रोल में जुट गए। गत दिनों भैरूंदा पहुंचे कार्तिकेय सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी ने बुधनी से रमाकांत भार्गव को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और पार्टी का यह निर्णय उचित है। हम सभी कार्यकर्ता पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रचार के काम में जुट जाएं और जीत के पिछले रिकॉर्ड को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को यहां से प्रचंड जीत दिलाएं।

वहीं कार्तिकेय सिंह ने बुधनी से खुद की दावेदारी पर कहा कि बुधनी के मेरे वरिष्ठों, कार्यकर्ताओं और साथियों ने केंद्रीय नेतृत्व तक मेरा नाम पहुंचाया है, मेरे लिए इतना ही काफी है, आपके इस प्यार और स्नेह के आगे मुझे स्वर्ग का सिंहासन भी फीका लगता है। मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व और आप सभी को प्रणाम करता हूं। उन्होंने कहा कि, मैं राजनीतिक परिवार से हूं और आपके बीच लंबे समय से आ रहा हूं, मुझे पता है कि पिता पद पर हैं तो ये शोभा नहीं देता कि मैं भी चुनाव लड़ूं। मुझे टिकट मिलना उचित नहीं है और मैं टिकट की लालसा के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम नहीं करता हूं। कार्तिकेय ने कहा कि क्षेत्र में भाजपा का विधायक होगा तो ही हम सभी का अस्तित्व होगा।

विजयपुर में आदिवासी वोटर बिगाड़ सकते हैं गणित

प्रदेश में 13 नवंबर को श्योपुर जिले की विजयपुर और सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा सीटों के उपचुनावों में मतदान होने वाला है। भाजपा-कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का चयन करते समय जातीय समीकरणों पर विशेष ध्यान दिया है। भाजपा ने कांग्रेस से आए छह बार के विधायक रामनिवास रावत को मैदान में उतारा है। वहीं, कांग्रेस ने इस सीट पर आदिवासी नेता मुकेश मल्होत्रा को टिकट दिया है। इस सीट पर आदिवासी वोटर निर्णायक हो सकते हैं। कांग्रेस ने इसी वजह से एक आदिवासी नेता पर भरोसा जताया है। विजयपुर विधानसभा सीट के लिए दोनों ही प्रमुख पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा चुनावों से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए रामनिवास रावत अब प्रदेश सरकार में वन मंत्री हैं। उनके भाजपा में आने का फायदा पार्टी को लोकसभा चुनावों में मिला भी था। ऐसे में अब कांग्रेस ने आदिवासी नेता के तौर पर मल्होत्रा को टिकट देकर भाजपा के सामने एक चुनौती पेश की है। भाजपा इस सीट को अपने पास रखने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने खुद ही चुनाव प्रचार की बागडोर अपने हाथ में ली। वह खुद विजयपुर गए और रावत का नामांकन भरवाया। विजयपुर विधानसभा में 2 लाख 55 हजार मतदाता हैं। इनमें से करीब 65 हजार यानी 20 प्रतिशत से अधिक मतदाता आदिवासी समुदाय से आते हैं। जाटव मतदाता भी 40 हजार के करीब हैं। कुशवाह और धाकड़ समाज से 25-25 हजार वोटर हैं। इन चार समाजों के करीब डेढ़ लाख मतदाता ही किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करते हैं। विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का परिणाम प्रमुख रूप से आदिवासी, जाटव, कुशवाह और धाकड़ समाज के वोटरों पर ही तय होगा।

हाईप्रोफाइल बुधनी विधानसभा सीट से कांग्रेस की ओर किरार समाज से आने वाले पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है। बुधनी में किरार समाज के वोटरों की संख्या 50 हजार से अधिक है। राजकुमार पटेल 1993 में बुधनी से विधायक रह चुके हैं और उनकी किरार समाज में गहरी पैठ मानी जाती है। कांग्रेस की ओर से राजकुमार पटेल की उम्मीदवारी का ऐलान होते हुए कांग्रेस में खुलकर बगावत हो गई है। कांग्रेस नेता अर्जुन आर्य अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। अर्जुन आर्य काफी लंबे समय से बुधनी में सक्रिय रहे हैं और वह चुनाव के समय बुधनी में पदयात्रा कर रहे हैं। ऐसे में अर्जुन आर्य राजकुमार पटेल के लिए चुनाव में एक चुनौती बन गए हैं।

श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा सीट पर हो रहा उपचुनाव एक हाईप्रोफाइल मुकाबला है। भाजपा ने विजयपुर विधानसभा सीट से कैबिनेट मंत्री रामनिवास रावत को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं कांग्रेस ने भाजपा से कांग्रेस में आए सहारिया जाति के बड़े नेता मुकेश मल्होत्रा को मैदान में उतारा है। 2023 विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने पर भाजपा से बगावत करने वाले मुकेश मल्होत्रा निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे थे और 44 हजार वोट हासिल कर तीसरे नंबर थे। ऐसे में अब जब भाजपा ने कांग्रेस से पार्टी में आए रामनिवास रावत को और कांग्रेस ने भाजपा से आए मुकेश मल्होत्रा को चुनावी मैदान में उतारा है तो पूरी सियासी लड़ाई कांटे की हो गई है। मुकेश मल्होत्रा जिस सहारिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे हैं उसकी आबादी 70 हजार है और सहारिया जाति के वोटर्स का रूख जीत-हार तय करता है। हालांकि भाजपा ने अपने पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी को सहारिया विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है।

विजयपुर में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवारों का विरोध उनकी ही पार्टी के मूल कार्यकर्ता कर रहे हैं। रामनिवास रावत लंबे समय तक कांग्रेस के दिग्गज चेहरे रहे और अब उनके भाजपा में आने से, भाजपा के मूल कार्यकर्ता खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और चुनाव में बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने लिए आज भाजपा रामनिवास रावत के नामांकन के जरिए एकजुटता का शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। विजयपुर में भाजपा की असली चुनौती पार्टी को एकजुट करना है। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस बुधनी विधानसभा सीट का लगभग 20 साल तक नेतृत्व किया है, उस पर हो रहे उपचुनाव में इस बार मुकाबला दो पुराने दिग्गज नेताओं के बीच है। बुधनी विधानसभा सीट से भाजपा ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने अपने दिग्गज नेता राजकुमार पटेल को मैदान में उतारा है। कांग्रेस की ओर किरार समाज से आने वाले पूर्व विधायक राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया गया है, बुधनी में किरार समाज के वोटरों की संख्या 50 हजार से अधिक है। राजकुमार पटेल 1993 में बुधनी से विधायक रहे चुके हैं और उनकी किरार समाज में गहरी पैठ मानी जाती है। वहीं पिछले 20 साल से बुधनी सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे शिवराज सिंह चौहान भी किरार समाज से ही आते हैं। वहीं भाजपा ने विदिशा के पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया है। शिवराज सिंह चौहान के विदिशा से लोकसभा चुनाव में उतरने से भाजपा ने रमाकांत भार्गव का टिकट काट दिया था, ऐसे में रमाकांत भार्गव को बुधनी से टिकट मिलना शिवराज सिंह चौहान की पंसद बताया जा रहा है और बुधनी में अब फिर शिवराज सिंह चौहान की ही प्रतिष्ठा दांव पर है।

● **सुनील सिंह**

उपचुनाव जीतू पटवारी के लिए अग्निपरीक्षा

मप्र में लगातार चुनाव हार रही कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष पद पर युवा चेहरे पर दांव लगाया लेकिन कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है। जीतू पटवारी को अध्यक्ष बने लगभग 1 साल पूरा होने जा रहा है, इस दौरान लोकसभा के बाद छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा उपचुनाव में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अपने 15 वर्ष के राजनीतिक सफर में जीतू पटवारी फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं, लेकिन हार की हैट्रिक पटवारी के लिए खतरे की घंटी हो सकती है। जीतू पटवारी बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंककर हार को जीत में बदलने की कोशिश करने में लगे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि पटवारी के लिए यह किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है। अगर दोनों सीट हारे तो अध्यक्ष की कुर्सी छोड़नी पड़ सकती है। मप्र में कांग्रेस पार्टी पहले विधानसभा 2023 में सत्ता से बाहर हुई। 2024 लोकसभा चुनाव मप्र के 29 की 29 लोकसभा सीट गंवा बैठी। इसके बाद अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा की सीट गंवा बैठी। अब एक बार फिर से कांग्रेस जीतू पटवारी को आजमा रही है। 13 नवंबर को बुधनी और विजयपुर विधानसभा उपचुनाव होना है। यहां भी हार का सिलसिला कायम रहा तो पटवारी की कुर्सी खतरे में आनी तय है। मप्र कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष महज 47 वर्ष के जीतू पटवारी को अध्यक्ष की कुर्सी मिलने का मुख्य कारण राहुल गांधी का करीबी और ओबीसी वर्ग से होना माना जाता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का उन्हें क्षेत्र में प्रभारी बनाया गया था। पटवारी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के भी प्रभारी रहे हैं। कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को हटाकर जीतू पटवारी को अध्यक्ष बनाने वाली कांग्रेस पार्टी प्रदेश में होने वाले दो सीटों के उपचुनाव में जीत की आस लगाए बैठी है। हालांकि जीतू पटवारी भी इन दोनों सीटों पर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर रहे हैं। चुनाव की तारीख की घोषणा होने से पहले ही दोनों ही सीटों पर पूरी जोर आजमाइश लगा रहे थे। अब तारीख की घोषणा होने के बाद पटवारी दोनों ही सीटों पर लगातार दौरा कर रहे हैं और एक-एक बूथ पर फोकस कर रहे हैं। अब उपचुनाव में क्या गुल खिलाते हैं, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रदेश युवा कांग्रेस से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचने का सफर तेजी से तय करने वाले जीतू पटवारी का कांग्रेस में राजनीतिक भविष्य आगामी उपचुनाव के परिणाम पर निर्भर करेगा।

दो दशक बाद भी अधर में मास्टर प्लान!

मप्र की राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान लंबे समय से फाइलों में ही बंद है। मास्टर प्लान का ड्राफ्ट कई बार जारी तो हुआ, लेकिन लागू होने से पहले कई बाधाएं सामने आती रहीं। बिना मास्टर प्लान के भोपाल का बेतरतीब विकास हो रहा है। लगभग यही हाल इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर का भी है। शहरों का अनियोजित विकास लोगों के लिए समस्या बनता जा रहा है। देश की सबसे साफ राजधानी प्लानिंग में 20 साल पीछे है, क्योंकि 1995 के बाद से भोपाल में मास्टर प्लान लागू ही नहीं हुआ। कई बार ड्राफ्ट बना, सरकारें बदलीं, लेकिन मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जमीन पर नहीं उतरा।

उधर, मास्टर प्लान भले ही अधर में लटका हुआ है, लेकिन धारा-16 की दुकान खूब चल रही है। धारा-16 की छूट से जमकर लूट की जा रही है। हालांकि मुख्य सचिव अनुराग जैन के संज्ञान में जैसे ही यह बात आई है, उन्होंने अफसरों की जमकर क्लास लगाई। उन्होंने नगरीय निकाय के एसीएस को बुलाकर इस संदर्भ में जवाब तलब किया। फिर अन्य अफसरों की भी क्लास लगाई। उन्होंने कहा कि धारा-16 का दुरुपयोग हो रहा है। इस दौरान टीएंडसीपी के डायरेक्टर सिर नीचे किए बैठे रहे। गौरतलब है कि अनुराग जैन ने 2018 में भी धारा-16 का विरोध किया था। गौरतलब है कि धारा-16 इमरजेंसी कोटा है। जब जरूरत पड़ती है, तो इसका इस्तेमाल होता है। लेकिन अफसरों को इससे क्या लेना-देना। वे दनादन धारा-16 की अनुमतियां दे रहे हैं। इससे जनता पर आर्थिक बोझ आ जाता है। यानि भोपाल में भले ही मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ है, लेकिन टेबल के नीचे से सारे काम हो रहे हैं। बताया जाता है कि इस मामले में 15 प्रतिशत का कमीशन चल रहा है। इस 15 प्रतिशत में से 8 प्रतिशत बड़े साहब, 3 प्रतिशत छोटे साहब, 2 प्रतिशत जेडी लेवल, 1 प्रतिशत जांच एजेंसियों को और 1 प्रतिशत पत्रकारों को दिया जा रहा है। यानि मास्टर प्लान की आड़ में जमकर खेल हो रहा है।

गौरतलब है कि अब तक चार बार भोपाल के मास्टर प्लान का ड्राफ्ट जारी हुआ, लेकिन अमलीजामा पहनाने से पहले ही इतने अड़ंगे आए कि सरकार को न चाहते हुए भी इसे रद्द करना पड़ा। मास्टर प्लान लागू न हो पाने की वजह से भोपाल में मनमाने तरीके से विकास हो रहा है। भोपाल के स्थानीय निवासी शमीम अजहर का कहना है कि विकास हर एक इंसान चाहता है। भोपाल में सड़कों पर निकलना मुश्किल है। भयंकर किस्म का क्राउड है। हर जगह जाम लगा हुआ है। मास्टर प्लान जब लागू होगा तो सुधार होगा, इसलिए मास्टर प्लान जरूरी है। भोपाल से कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि बिना मास्टर प्लान और विकास योजना के कैसे शहर का विकास होगा? कैसे लोग इसमें कारोबार करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है, यह सब डिपेंड करता है मास्टर प्लान पर। सरकार से पूछा जाए कि मप्र के कितने जिलों में कब-कब मास्टर प्लान लागू किया तो यह कुछ सही जवाब नहीं दे पाएंगे। सरकार का काम सिर्फ नफरत फैलाना है। बता दें कि भोपाल की जनसंख्या वर्तमान में 23 लाख से अधिक है, लेकिन शहर का डेवलपमेंट प्लान 2005 की आबादी के मुताबिक हो रहा है। पिछले साल मास्टर प्लान का ड्राफ्ट करीब 3000 आपत्तियों में उलझ गया। विपक्ष सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहा है तो आपत्ति दर्ज कराने वाले विधायक जल्द मास्टर प्लान लागू होने का हवाला दे रहे हैं। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहते हैं कि मास्टर प्लान को लेकर सरकारी स्तर पर हमारी तैयारी जारी है बहुत जल्दी ही मास्टर प्लान आएगा। मुख्यमंत्री ने उसकी समीक्षा एक बार कर ली है जो कुछ बिंदु हैं औद्योगिक क्षेत्र, रोजगार और भोपाल के डेवलपमेंट के हिसाब से जरूरी है। मुख्यमंत्री उस पर निगाह रखे हुए हैं। मैं समझता हूं बहुत जल्दी मास्टर पर लागू हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स और नेता दोनों इसके लिए जिम्मेदार हैं। सरकार के लिए टेढ़ी खीर बनता जा रहा भोपाल का मास्टर प्लान आखिर कब लागू होगा यह अब भी सवाल बना हुआ है। तारीख पर तारीख मिलती गई आगे बढ़ीं, ड्राफ्ट भी बना, लेकिन जमीन पर मास्टर प्लान लागू नहीं हुआ। भोपाल के लोगों को आज भी इंतजार है राजधानी का सुनियोजित विकास कब होगा। भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान में मेट्रोपोलिटिन रीजन प्लान को भी शामिल किया जाएगा। इसके तहत भोपाल में सीहोर, मंडीदीप, औबेदुल्लागंज, बंगरसिया को मास्टर प्लान में शामिल किया जाएगा। जबकि इंदौर के मास्टर प्लान में पीथमपुर, देवास और उज्जैन को भी शामिल किया जाएगा। सड़कों को जोड़ने पर विशेष फोकस किया जाएगा।

● **जितेंद्र तिवारी**

तय होता है आगामी विकास का ढांचा

मास्टर प्लान किसी भी बड़े या मध्यम शहर के लिए जरूरी है। भोपाल तो फिर भी राजधानी है। शहर में कहां व्यापार होगा, कहां आबादी रहेगी, कहां खेती होगी, यह मास्टर प्लान में तय होता है। आज नहीं 30 साल बाद भी विकास कैसे होगा यह भी मास्टर प्लान में तय होता है। इसके लिए मुख्य रूप से शासन जिम्मेदार है, लोगों का हित स्वार्थ इसमें आड़े आता है। मास्टर प्लान लागू न होने से राजधानी में अवैध कॉलोनियां भी तेजी से बढ़ीं हैं, जिसे खुद सरकार भी मानती है। ब्यूरोक्रेट्स को मास्टर प्लान की सारी जानकारी रहती है। नेता और अधिकारी मिलकर मास्टर प्लान को प्रभावित करने के लिए प्रस्तावित मास्टर प्लान के अनुसार, आसपास जमीन खरीद लेते हैं। मास्टर प्लान के देरी होने की वजह यह है कि नेताओं में दूरदृष्टि की कमी है, अपने हित के लिए मास्टर प्लान को डीले किया जाता है। नगरीय विकास व आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि अवैध कॉलोनियां मास्टर प्लान के सपने को साकार नहीं होने देती हैं, मास्टर प्लान के क्रियान्वयन में अवैध कॉलोनी बहुत बड़ा अवरोध है। जल्द मास्टर प्लान लागू करेंगे और अब कड़े नियम बनाएंगे। मास्टर प्लान नहीं बनने के कारण ट्रांसपोर्ट की योजना सही से नहीं बन पाई। हाल ही में बीआरटीएस टूटा, बनने में करोड़ों लगे और तोड़ने में भी करोड़ों रुपए डूबे। 2005 के बाद से लैंड यूज में बदलाव न होने से रियल एस्टेट बूम और जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगीं।

कांग्रेस को मझधार से निकालेंगे युवा

मप्र में पिछले दो दशक से राजनीति के मझधार में फंसी कांग्रेस को अब युवा नेता निकालेंगे। इसके लिए आलाकमान ने युवा नेताओं को प्रदेश संगठन में उपाध्यक्ष, महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। साथ ही अब इन युवा नेताओं को संभाग और जिलों का प्रभार देकर उन्हें सक्रिय किया जाएगा। ये नेता कांग्रेस संगठन को मजबूत करेंगे। युवा नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष व महासचिव इसलिए बनाया गया है, ताकि वे भागदौड़ और परिश्रम कर पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत कर सकें। इसके अलावा कुछ पदाधिकारियों को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में काम सौंपा जाएगा और कुछ को फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का प्रभार दिया जाएगा। वहीं पार्टी ने वरिष्ठ नेताओं को भी संगठन में जिम्मेदारी दी है, ताकि वे युवाओं को सहयोग दे सकें।

गौरतलब है कि जीतू पटवारी के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनने के करीब 10 महीने बाद अब उनकी टीम बनकर तैयार हो गई। प्रदेश कार्यकारिणी में युवा और वरिष्ठ नेताओं के बीच संतुलन बैठाने की कोशिश की गई है। पार्टी ने युवा नेताओं को जहां प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है, वहीं 55 साल से अधिक उम्र के नेताओं और दिग्गजों को कार्यकारिणी सदस्य, स्थाई आमंत्रित सदस्य और विशेष आमंत्रित सदस्य बनाकर उनका मान-सम्मान बरकरार रखने की कोशिश की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष और महासचिवों की औसत उम्र 40 से 55 साल है। पार्टी को आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में सगठन का विस्तार करना है। जिलों से लेकर गांवों तक जनता के बीच पार्टी की पैठ बनानी है।

संगठन के गठन के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पार्टी नेताओं के साथ बैठक कर जल्द ही इसकी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने अभी प्रदेश सचिव, अनुशासन समिति और राजनीतिक मामलों की सलाहकार समिति की घोषणा नहीं की है। जीतू पटवारी ने कहा कि जल्द ही इनकी घोषणा की जाएगी। इनमें वर्तमान सूची में शेष रहे कई साथियों को भी जिम्मदारी मिलेगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस की कार्यकारिणी बनाने के बाद अब विभागों के अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष भी बदले जाएंगे। पार्टी ने अन्य पिछड़ा वर्ग और आदिवासी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्षों को महासचिव बना दिया है। इनके स्थान पर नई नियुक्तियां बुधनी और विजयपुर, विधानसभा के उपचुनाव के बाद होंगी। वहीं, जिला इकाइयों में भी परिवर्तन प्रस्तावित हैं। जिन नेताओं को कार्यकारिणी में स्थान नहीं मिल पाया है, उन्हें सचिव, सह-सचिव बनाकर संगठन में समायोजित किया जाएगा। वरिष्ठ नेताओं की भूमिका अब मार्गदर्शक की रहेगी। वैसे तो इसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के समर्थकों को स्थान देकर संतुलन बनाने का प्रयास किया है। पिछड़ा वर्ग विभाग के अध्यक्ष सिद्धार्थ कुशवाहा को उपाध्यक्ष तो आदिवासी कांग्रेस अध्यक्ष रामू टेकाम और किसान कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुर्जर को महासचिव बनाया है। इन तीनों के स्थान पर नई नियुक्ति की जाएंगी। सिद्धार्थ कुशवाहा और दिनेश गुर्जर विधायक हैं। वहीं, रामू टेकाम को दूसरी बार बैतूल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया था पर वे हार गए।

प्रदेश संगठन के गठन के बाद अब पटवारी का फोकस संगठन की मजबूती पर रहेगा। संगठन की सक्रियता भी कम है, जबकि पार्टी का फोकस आदिवासियों पर रहता है। पार्टी करीब 50 ब्लॉक अध्यक्षों को 10 माह में हटा चुकी है। अब कुछ जिला अध्यक्षों को भी बदलने की तैयारी है। दरअसल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पहले ही कह चुके हैं कि जो पदाधिकारी संगठन के कामकाज के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या निष्क्रिय हैं, उनके स्थान पर सक्रिय कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्टी के मंथन में इसे लेकर सहमति भी बन चुकी है। इनमें वे अध्यक्ष भी शामिल होंगे, जिन्हें तीन वर्ष से अधिक समय पदस्थ रह चुके हैं। साथ ही उन जिलों में भी नई नियुक्ति की जाएगी, जहां समन्वय बनाने को लेकर समस्या आ रही है। उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सबको साथ लेकर चलने के साथ अंचल और जातिगत संतुलन बनाने का प्रयास किया है। पार्टी में काम करने वाले कई वरिष्ठ और युवा नेता हैं। सबकी उपयोगिता है और जो रह गए हैं, उन्हें आगे समायोजित करेंगे। पार्टी ने सभी वरिष्ठ नेताओं को जीतू पटवारी की टीम में शामिल तो किया है पर इनकी भूमिका मार्गदर्शक की होगी। इन्हें प्रदेश स्तरीय हर बैठक में बुलाया जाएगा और अनुभव का लाभ लिया जाएगा। ऐसे नेताओं में डा. गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, रामेश्वर नीखरा, राजा पटेरिया, नरेंद्र नाहटा, चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी, कैलाश कुंडल, मुजीब कुरैशी, रामसेवक गुर्जर, साजिद अली सहित अन्य शामिल हैं।

● **कुमार विनोद**

जिलों में आयोजित होंगे प्रशिक्षण शिविर

प्रदेश संगठन की मजबूरी के लिए कांग्रेस कुछ जिलों में तीन दिन तो कुछ में एक दिन के प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने जा रही है। इसमें बूथ, सेक्टर, मंडलम और जिला स्तर के कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसमें बताया जाएगा कि भाजपा सरकार की नीतियों, विकास के वादों के बीच कांग्रेस को कौन से मुद्दे उठाने चाहिए, कहां पर उठाना चाहिए, इसके लिए जनता को अपने भरोसे में कैसे लें, संगठन को कैसे मजबूत बनाएं। प्रशिक्षण आयोजित करने की जिम्मेदारी सेवादल को दी गई है। इसमें जिला, प्रदेश व कुछ जगह राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी प्रशिक्षण देंगे। दिसंबर में महासम्मेलन होगा। सेवादल के प्रदेश अध्यक्ष योगेश यादव ने बताया कि कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और संगठन की मजबूती के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाने का निर्णय लिया गया है। दीपावली के बाद यह प्रारंभ हो जाएंगे। नीमच, राघौगढ़, रीवा सहित अन्य जगहों पर ये आयोजन तीन-तीन दिन के होंगे। जबकि, अन्य जिलों में एक-एक दिन के शिविर रखे जाएंगे। इनमें बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति-नीति के साथ भावी योजनाओं के बारे में बताने के साथ भाजपा द्वारा लगाए जाने वाले आरोपों का उत्तर देने के तरीके, संगठन को मजबूत करने समन्वय बनाने और बूथ प्रबंधन के बारे में बताएंगे।

मप्र को मिलेंगे 68 सांसद

भारतीय संसद के लिए लोकसभा और राज्यसभा सीटों का परिसीमन होने की चर्चाएं हैं जिसकी एक प्रारंभिक तस्वीर सामने आई है। सबकुछ ठीक रहा तो लोकसभा-राज्यसभा की जनसंख्या 2011 के आधार पर परिसीमन के बाद अनुमानित की गईं लोकसभा-राज्यसभा सीटों की संख्या के अनुसार भारतीय संसद भवन में 1132 सांसद बैठेंगे जो अभी 788 है। मप्र में लोकसभा की 20 सीटें तो राज्यसभा की 8 सीटें बढ़ जाएंगी। ऐसे में नए परिसीमन में मप्र को 68 सांसद मिलेंगे।

एक देश एक चुनाव के साथ लोकसभा-राज्यसभा और विधानसभाओं की सीटों के परिसीमन को लेकर कवायद चल रही है। राजनीतिकों में इस परिसीमन को लेकर काफी उत्सुकता है और इस वजह से परिसीमन के अनुमानित आंकड़े अब चर्चा में आने लगे हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा जनसंख्या 2011 के आधार पर हाल ही में लोकसभा-राज्यसभा सीटों को लेकर सामने आया है जिसमें नए संसद भवन में 1132 सांसदों के पहुंचने की बात बताई गई है। इसमें 800 सीटें लोकसभा की बताई गई हैं तो 332 राज्यसभा की बताई गई हैं। वर्तमान स्थिति से तुलना की जाए तो अभी लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 सांसद होते हैं। मतलब लोकसभा में आज की तुलना में 257 और राज्यसभा में 87 सीटों का इजाफा हो जाएगा। नए संसद भवन में लोकसभा के सदस्यों के लिए 888 तो राज्यसभा सदस्यों के लिए 384 सीटें हैं यानी परिसीमन के बाद भी लोकसभा में 88 व राज्यसभा में 52 सीटें खाली रहेंगी।

केंद्रीय स्तर पर 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन की जो कवायद चल रही है। इसे लेकर राजनीतिक दलों में उत्सुकता है। इस कारण ही परिसीमन के अनुमानित आंकड़े सामने आने लगे हैं। ऐसा ही एक आंकड़ा लोकसभा-राज्यसभा सीटों को लेकर सामने आया है। आने वाले समय में परिसीमन के बाद जो स्थिति एक आंकड़े में सामने आई है, उसके मुताबिक मप्र से 49 लोकसभा सदस्य चुनाव जीतकर पहुंचेंगे तो 19 राज्यसभा सदस्य राज्य का संसद में प्रतिनिधित्व करेंगे। अभी मप्र में लोकसभा की 29 और राज्यसभा की 11 सीटें हैं। परिसीमन में मप्र को 20 लोकसभा सीटें अतिरिक्त मिलने की स्थितियां बताई जा रही हैं तो राज्यसभा में राजनीतिक दलों को 8 अतिरिक्त सीटों का लाभ मिलेगा।

संविधान के अनुच्छेद-82 के अंतर्गत 2001 की जनगणना से पहले के आंकड़ों के आधार पर ही लोकसभा-विधानसभा की सीटें बढ़ाने की व्यवस्था की गई। यानी परिसीमन मौजूदा व्यवस्था के हिसाब से 2026 से पहले नहीं कराया जा सकता और जब तक ये नहीं कराया जाता, तब तक सीटों की लोकसभा और विधानसभा सीटों की भी बढ़ोत्तरी नहीं होगी। पहली बात यह है कि 2026 के बाद ही परिसीमन होगा तब कहीं जाकर सीटों का इजाफा होगा, लेकिन क्या लोकसभा और विधानसभा की तरह राज्यसभा और विधान परिषद की सीटें भी बढ़ जाएंगी? 2025 के बाद देश में नया परिसीमन लागू होगा। नए परिसीमन के बाद माना जा रहा है कि 543 सीट से 800 सीटें जो बढ़ेगी उसमें 80 फीसदी से अधिक बिहार, उप्र, पश्चिम बंगाल, मप्र और राजस्थान जैसे राज्यों में बढ़ेगी और दक्षिण का प्रतिनिधित्व उस अनुरूप नहीं बढ़ेगा। इसका बड़ा असर राष्ट्रीय राजनीति पर हो जाएगा। हालांकि, इससे उत्तर बनाम दक्षिण का विवाद भी बढ़ सकता है। परिसीमन का आधार राज्यों की जनसंख्या होती है।

जानकार बताते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद की सीटों के लिए जिस तरह वोटिंग का फॉर्मूला लागू होता है। उसी तरह से उनकी सीटों को बढ़ाने का भी प्रवाधान है। ऐसे में जाहिर है कि परिसीमन से देश में लोकसभा और राज्य में विधानसभा की सीटें बढ़ेंगी तो दोनों ही जगह उच्च सदन की सीटों में भी बढ़ोत्तरी होगी। मौजूदा समय सिर्फ देश के छह राज्यों में विधान परिषद हैं। उप्र, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और तेलंगाना। पहले जम्मू-कश्मीर समेत सात राज्यों में विधान परिषद थे, लेकिन जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक-2019 के जरिए इसे समाप्त कर दिया गया और राज्य का दर्जा जम्मू-कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील हो गया। अगर तत्काल सीटों को बढ़ाना है तो उसके लिए केंद्र सरकार को लोकसभा और विधानसभा में सीटें बढ़ाने का संविधान संशोधन करना होगा, उसके बाद ही यह संभव है।

मान लीजिए कोई राज्य सरकार सर्वे कराकर केंद्र के पास रिपोर्ट भेजे और विधानसभा सीटें बढ़ाने की सिफारिश करे, जिस पर केंद्र भी सहमति दे दे तो ऐसे में सिर्फ संबंधित राज्य में सीटें बढ़ाने के लिए भी सरकार को संविधान संशोधन लाना होगा। जानकार बताते हैं कि परिसीमन 2026 की सीमा को समाप्त करने के लिए 84वें संशोधन को शिथिल करके संसद 1991 या 2001 की जनगणना के आधार पर सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव लाना होगा। इसके अलावा तीसरा रास्ता यह भी है कि 84वें संशोधन को सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट में चुनौती दी जाए और याचिका में 84वें संशोधन को संविधान की मूल भावना के खिलाफ बताया जाए, आगे कोर्ट पर निर्भर करता है कि वह उस संशोधन को निरस्त करे या फिर नहीं।

● **डॉ. जय सिंह सेंधव**

महिला आरक्षण का लागू होना

मोदी सरकार ने अपने दूसरे टर्म के अंतिम दिनों में संसद और विधानसभा में एक तिहाई महिला आरक्षण देने वाला कानून पास किया। इसके लागू होने की संभावना 2019 आम चुनाव से है, क्योंकि इसके पीछे शर्त रखी गई कि परिसीमन के लागू होने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। ऐसे में अगले आम चुनाव में कम से कम एक तिहाई सीटों पर महिला उम्मीदवारों को खड़ा करना सभी राजनीतिक दलों के लिए बाध्यता हो जाएगी। इससे मौजूदा राजनीति पूरी तरह बदल जाएगी। देश में अगले आम चुनाव में एक देश, एक चुनाव भी लागू होना तय माना जा रहा है। नरेंद्र मोदी इसके सबसे बड़े हिमायती माने जाते हैं। भाजपा के घोषणा पत्र का भी यह अहम बिंदु है। आम चुनाव से पहले सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में कमेटी बनाई थी, जिसे इसके लिए रोडमैप देना था। कमेटी रिपोर्ट दे चुकी है। खुद नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में अपना संकल्प दोहराया कि वे इसे लागू करेंगे। अब जबकि गठबंधन की सरकार बनने वाली है तो क्या इस दिशा में नई सराकर आगे बढ़ेगी, अब यह देखना दिलचस्प होगा।

ब्यूरोक्रेट्स का टोटा

गड़बड़ाया आईपीएस कैडर मैनेजमेंट

मप्र में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की पदस्थापना का मैनेजमेंट बिगड़ गया है। राज्य में अलग-अलग स्तर पर निर्धारित पदों के हिसाब से कहीं ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं तो कहीं कम तैनात किए गए हैं। इस मैनेजमेंट के बिगड़ने के पीछे की वजह किसी साल ज्यादा तो कभी मात्र एक-दो पद का मिलना बताया जा रहा है। वहीं हर 5 वर्ष में कैडर रिव्यू नहीं हो रहा है। इसके कारण भी ठीक प्रकार से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के कुल 319 पद हैं। इनमें 37 खाली है। सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व के लिए आरक्षित 68 पदों से 27 अधिकारी ही पदस्थ हैं, बाकी पद खाली पड़े हैं। इस तरह में अभी प्रदेश में 282 आईपीएस अधिकारी ही पदस्थ हैं। संभावना है कि प्रदेश को 6 नए अधिकारी भी इस वर्ष के अंत तक मिल सकते हैं। पुलिस के सुपरिटेंडेंट स्तर के पदों को देखें तो सीनियर ड्यूटी पोस्ट के कुल 173 पदों में निर्धारित 50 प्रतिशत के हिसाब से इनकी संख्या 87 होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इन्हें अपने विवेकाधिकार से बढ़ाकर 95 कर लिया है। इसके विपरीत 120 अधिकारी एसपी पद पर पदस्थ हैं।

मप्र की आबादी लगातार बढ़ रही है और जिलों की संख्या भी 55 हो गई है। लेकिन आबादी और जिलों को संभालने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। कार्मिक मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार मप्र में 1060 अफसरों की जरूरत है, लेकिन सिर्फ 891 ही काम कर रहे हैं। इनमें आईएएस के 459 में 391, आईपीएस के 305 में से 249 और आईएफएस के 296 में से 251 अफसर हैं। अभी भी 169 अफसरों की दरकार मप्र को है। समस्या यह है कि मप्र में जो 891 अफसर हैं, इनमें से करीब 190 अधिकारी मुख्यालय में हैं। यह सेंक्शन पोस्ट से भी अधिक हो गए हैं, जबकि फील्ड में महज 20 फीसदी ही हैं। ऐसे में प्रदेश में तैनात अफसर काम के बोझ से दबे हुए हैं। इनमें से कई के पास एक से चार तक अतिरिक्त प्रभार हैं। जिसकी वजह से लोगों के जनहित के रोजमर्रा के कामकाज प्रभावित हो रहे हैं और मौजूदा कर्मियों पर भारी दबाव पड़ रहा है। हालांकि राज्य सरकार लगातार जमीन स्तर पर नीतियों के कड़े क्रियान्वयन पर जोर दे रही है, लेकिन जिन अधिकारियों पर इसका जिम्मा है, वे काम के भारी बोझ के कारण इसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर पा रहे हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश की आबादी बढ़ रही है। जिलों की संख्या भी बढ़कर 55 हो गई, पर जिलों और प्रदेश में प्रशासनिक नियंत्रण रखने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अफसरों की संख्या बढ़ने के बजाय घट रही है। आलम यह है कि प्रदेश में तैनात 350 आईएएस 50 प्रतिशत काम के बोझ से दबे हैं। उनके पास एक से चार तक अतिरिक्त प्रभार हैं। मप्र आईएएस कैडर में 459 पद स्वीकृत हैं। इनमें 391 पद भरे हैं, जबकि 68 खाली हैं। इनमें भी कार्यरत 391 में से 41 केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। देखा जाए तो मप्र में रोज नए ऐलान हो रहे हैं। राज्य सरकार भी जमीनी स्तर पर कसावट की बात कर रही है। लेकिन इन ऐलानों और उसके क्रियान्वयन और कसाहट में एक पेंच फंसा है। वो ये है कि जिन अधिकारियों पर इसका जिम्मा है वो ही काम के बोझ तले दबे हैं। उस पर तुर्रा ये कि राज्य में तैनात कई अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाना चाहते हैं। इसी बीच दूसरा डाटा ये बताता है कि 89 अफसर अगले पांच साल में रिटायर हो जाएंगे। अहम ये भी है कि केंद्र सरकार ने अगस्त 2022 में मप्र आईएएस कैडर की समीक्षा की थी। तब राज्य में आईएएस कैडर संख्या 459 थी। दो साल गुजर जाने के बाद भी इस संख्या को बढ़ाने पर विचार नहीं किया गया। अफसरों की इस कमी को लेकर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का कहना है कि सरकार प्रमोटी अफसरों को अपने फायदे के लिए तवज्जो दे रही है। कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल का आरोप है कि सरकार जानबूझकर आईएएस अधिकारियों की कमी को दूर नहीं कर रही है क्योंकि उन्हें पता है कि प्रमोटी अधिकारियों से अपने एजेंडे को पूरा किया जा सकता है और भ्रष्टाचार किया जा सकता है। अब सच क्या है ये तो सरकार ही बता सकती है कि लेकिन इस स्थिति में, मप्र का प्रशासनिक ढांचा दबाव में है इसका पता तो चल ही जाता है। राज्य में प्रभावी शासन क्षमता के लिए इस मसले का समाधान तत्काल किए जाने की जरूरत है। प्रदेश में डीजी और डीजीपी बनने की दौड़ में शामिल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एडीजी) इस बात से दुखी हैं कि दूसरे राज्यों में उनके बैच के अधिकारी पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) बन चुके हैं, पर वह डीजी तक नहीं बन पाए हैं। जानकारी के अनुसार आंध्रप्रदेश, मेघालय, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कुछ राज्यों में 1992 बैच तक के पुलिस अधिकारियों को डीजीपी या डीजी बनने का अवसर मिल चुका है, पर मप्र में डीजी बनने में ही अभी उन्हें लगभग डेढ़ वर्ष लग जाएंगे। कुछ तो इसके पहले रिटायर भी हो जाएंगे। भारत के अन्य राज्यों की मप्र से तुलना करें तो मप्र पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के प्रमोशन में सबसे ज्यादा फिसड्डी साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ में जहां 1998 तक, जम्मू-कश्मीर में 1999, हिमाचल प्रदेश में 2000, दिल्ली में 2001, गोवा में 2001, तमिलनाडु में 2002, हरियाणा में 2004, महाराष्ट्र में 2004, मेघालय में 2004, बिहार में 2005, उत्तराखंड में 2005, वेस्ट बंगाल में 2009, गुजरात में 2010, आंध्र प्रदेश में 2010, तेलंगाना में 2010 और कर्नाटक में 2012 बेच के राजपत्रित अधिकारियों के प्रमोशन हो चुके हैं। मप्र में 1997 बैच के राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रमोशन यानी की डीपीसी नहीं हुई है।

केंद्र ने अगस्त 2022 में मप्र आईएएस कैडर की समीक्षा की। तब आईएएस कैडर संख्या 459 थी। उसके बाद से संख्या नहीं बढ़ी। जानकारों की मानें तो जनता को बेहतर सेवाएं देने और प्रदेश को विकास की ओर ले जाने वाली पहली प्रशासनिक धुरी आईएएस होते हैं। इनकी कमी से जनता को मिलने वाली सेवाएं प्रभावित होंगी। प्रदेश में 55 जिले, 55 जिला पंचायतें, 16 नगर निगम, 10 संभाग के लिए 136 आईएएस चाहिए। 56 विभाग हैं, एक विभाग में (अपवाद छोड़कर) 8 आईएएस के हिसाब से 448 आईएएस की जरूरत है। मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव कार्यालय को मिलाकर प्रदेश को 594 आईएएस की जरूरत है।

● **प्रवीण सक्सेना**

देश का दिल कहलाने वाला मप्र तरक्की और समृद्धि के साथ विकास की नई इबारत लिख रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में एक समान विकास की रणनीति पर काम हो रहा है। इसके लिए प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, हाईवे का जाल बिछाया जा रहा है। इससे प्रदेश में निवेश के मौके बढ़ेंगे, जिससे मप्र आत्मनिर्भर बनेगा।

एक्सप्रेस-वे से आत्मनिर्भर बनेगा मप्र

मप्र उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम सड़कों के नेटवर्क के जरिए पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। मप्र से कई ऐसे नेशनल हाईवे, एक्सप्रेस-वे और कॉरिडोर गुजरते हैं या बनाए जा रहे हैं, जो मप्र की तस्वीर को बदलने का काम करेंगे। भारतमाला परियोजना के तहत मप्र में 5 एक्सप्रेस-वे प्रस्तावित हैं। जो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट सुविधा और कनेक्टिविटी बेहतर करेंगे, बल्कि मप्र के औद्योगिक विकास में गति लाएंगे। सरकार इन एक्सप्रेस-वे के किनारे मल्टी लॉजिस्टिक वेयर हाउस और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने जा रही है। इसके लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है। मुंबई-दिल्ली और नागपुर-लखनऊ जैसे बड़े शहरों को जोड़ने 6 लेन और 8 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे बनाए जाने हैं। राज्य सरकार ने इन सड़कों के किनारे इंडस्ट्रियल रीजन तैयार करने का प्लान बनाया है। ताकि, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां डाली जा सकें। इंडस्ट्रियल रीजन में निवेशकों के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे स्थानीय किसानों को भी फायदा होगा। मोटी कमाई का रास्ता खुलेगा। मप्र सरकार ने इंडस्ट्रियल रीजन के लिए 5 एक्सप्रेस-वे और हाईवे चिन्हित किए हैं। जहां 24 हजार एकड़ क्षेत्र में औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

प्रदेश के एक्सप्रेस-वे और हाईवे के किनारे इंडस्ट्रियल रीजन तैयार किए जाएंगे। प्रारंभिक चरण में दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर के साथ पांच एक्सप्रेस-वे और हाईवे का चयन किया गया है। इनके आसपास करीब 24 हजार एकड़ शासकीय भूमि चिन्हित की गई है। वहीं किसानों और निवेशकों के साथ पीपीपी मॉडल पर औद्योगिक क्षेत्र तैयार करने के लिए भी काम होगा। प्रदेश से होकर और प्रदेश की सीमा के आसपास से गुजरने वाले एक्सप्रेस-वे के पास 1,500 एकड़ से 4,000 एकड़ तक के औद्योगिक क्लस्टर बनाए जाएंगे। इनमें सड़क, बिजली, पानी, सीवेज लाइन, ट्रांसपोर्ट, एयरपोर्ट और रेलवे लाइन से सीधे कनेक्टिविटी की सुविधा के साथ टाउनशिप भी तैयार की जाएंगी। यहां से गुजरने वाले जिला मार्गों और पीएम ग्रामीण सड़कों को भी टू और फोर लेन किया जाएगा। हर एरिया के लिए एक अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी जाएगी कि वह उद्योगों का सहयोग करे। बड़े उद्योगों की मॉनीटरिंग पीएस, सचिव तथा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के एमडी करेंगे। प्रदेश के आधा दर्जन से अधिक इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपति रूचि नहीं ले रहे हैं। उद्योगों को रिझाने के लिए सरकार विशेष पैकेज दे रही है, जिसमें वे एकमुश्त राशि की जगह 18 किस्तों में भूखंड की राशि जमा कर सकेंगे। ऐसे क्षेत्रों में उज्जैन का ताजपुर, विदिशा का जंबारबागरी, इटारसी का कीरतपुर, जबलपुर का मनेरी शामिल हैं। डॉ. मोहन यादव की सरकार ने इंडस्ट्री प्रोजेक्ट के विस्तार से रोजगार के अवसर बढ़ाने के रोडमैप पर नए सिरे से काम शुरू कर दिया है। सरकार अगले 5 वर्षों में 8,28,050 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इससे इंडस्ट्रीज का विस्तार होगा और 72 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। इंडस्ट्रीज का विस्तार कर प्रदेश की माली हालत सुधारने मुख्यमंत्री ने इस विभाग को अपने हाथों में रखा है। उनकी प्राथमिकता को देखते हुए प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने अफसरों ने भी केंद्रीय स्वीकृति के लिए दौड़-भाग तेज कर दी है।

लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि प्रदेश में 3401 किलोमीटर लंबे 6 एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। इन सभी एक्सप्रेस-वे के बनने से प्रदेश में विकास की गति तेज हो जाएगी। साथ ही रोजगार और व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस-वे है। देश की राष्ट्रीय

10 लाख करोड़ का निवेश

छत्तीसगढ़ से गुजरात को जोड़ने वाले एक्सप्रेस-वे नर्मदा प्रगति पथ का 867 किलोमीटर का हिस्सा मप्र से होकर गुजर रहा है। इसका कुछ हिस्सा 4 लेन होगा तो कुछ हिस्सा 6 लेन का रहेगा। इसे 2027 तक बनाने की डेडलाइन तय की गई है। केवल नर्मदा प्रगति पथ नहीं बल्कि मप्र में ऐसे 5 और एक्सप्रेस-वे बनने वाले हैं। डॉ. मोहन सरकार ने अपने पहले बजट में इन 6 एक्सप्रेस-वे को प्राथमिकता से पूरा करने का ऐलान किया है। सभी प्रोजेक्ट्स पर अगले 5 साल में 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। जानकार कहते हैं कि यदि सरकार इस मेगा प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने में कामयाब हो जाती है तो 36 जिलों को फायदा होगा। एक्सप्रेस-वे के दोनों तरफ इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक पार्क डेवलप होंगे। दूसरे राज्यों से प्रदेश की कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इससे 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का रास्ता खुलेगा और करीब 25 लाख रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अटल प्रगति पथ को पहले चंबल एक्सप्रेस-वे से शुरू किया गया था। यह मप्र, उप्र और राजस्थान राज्यों से होकर गुजरता है। 415 किमी लंबे इस एक्सप्रेस-वे का 296 किलोमीटर का हिस्सा मप्र, 47 किमी उप्र और 72 किमी का हिस्सा राजस्थान में होगा।

राजधानी और आर्थिक राजधानी मुंबई को जोड़ने वाले इस एक्सप्रेस-वे से रतलाम, झाबुआ और इंदौर को सीधा फायदा होगा। सरकार ने इस एक्सप्रेस-वे के किनारे 4 से 5 औद्योगिक जोन विकसित करने 4 हजार एकड़ जमीन चिन्हित की है। निवेशकों को यहां हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी। रतलाम में बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा। दिल्ली-नागपुर एक्सप्रेस-वे के किनारे भी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की तैयारी है। इसके लिए सागर जिले में 2 हजार एकड़, सिवनी में 1200 एकड़ और होशंगाबाद में 2600 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। जहां बड़ा औद्योगिक हब तैयार किया जाएगा। दिल्ली-नागपुर एक्सप्रेस-वे मप्र के मुरैना, ग्वालियर, भोपाल, नर्मदापुरम और बैतूल जिलों से होकर गुजरेगा। मुंबई-वाराणसी एक्सप्रेस-वे बड़ा औद्योगिक हब बनेगा। बुरहानपुर से सिंगरौली तक इसमें 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाने हैं। राजधानी भोपाल के पास मंडीदीप और आष्टा में 4-4 हजार, जबलपुर और कटनी में 1400-1400 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। सतना, रीवा और सिंगरौली जिले में भी 4 हजार एरिया चिन्हित किया गया है। औद्योगिक विकास से रोजगार और निवेश के मौके भी बढ़ेंगे।

मप्र की राजधानी भोपाल को इंदौर को जोड़ने वाले इस हाईवे के किनारे इंडस्ट्रियल टाउन विकसित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए देवास और शाजापुर और आष्टा में 2 हजार एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से किसानों व बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। वहीं राजधानी भोपाल और उप्र की राजधानी लखनऊ को जोड़ने फोरलेन सड़क बनाई जानी है। जो उप्र के कानपुर, झांसी समेत बुंदेलखड़ के कई जिलों को कनेक्ट करेगा। राज्य सरकार कानपुर-सागर फोरलेन को भोपाल तक बढ़ाकर इसके किनारे नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने का प्लान तैयार किया है। उद्योग-धंधों के लिहाज से यह कॉरिडोर भी बेहतर साबित होगा। मप्र के भोपाल, इंदौर सहित दूसरे शहरों को उप्र के कानपुर, वाराणसी और लखनऊ जैसे शहरों से जोड़ने के लिए भोपाल-लखनऊ इकोनॉमिक

कॉरिडोर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यदि तय समय पर निर्माण कार्य पूरा हो गया, तो 2026 में शहरों के बीच आपसी कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ परियोजना में सेतु का काम कर रहे उप्र और मप्र के बुंदेलखंड की तरक्की के द्वार खुलेंगे। ये कॉरिडोर बुंदेलखंड के खनन व्यवसाय में पंख लगाएगा। बल्कि पर्यटन को बढ़ावा देगा। इसके अलावा माल परिवहन के क्षेत्र में क्रांति लाने का काम करेगा। उप्र और मप्र के बुंदेलखंड से खासकर रेत और मुरम का व्यवसाय बड़े पैमाने पर होता है। मप्र के बुंदेलखंड के ओरछा, खजुराहो जैसे धार्मिक पर्यटन केंद्र के अलावा पन्ना और नौरादेही टाइगर रिजर्व उप्र के पर्यटकों के लिए आकर्षण का काम करेगा। देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे एनएच-44 भारत को कश्मीर से कन्याकुमारी और एक तरह देश के सभी राज्यों से जोड़ने का काम करता है। नेशनल हाईवे-44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जो मप्र में 504 किमी से गुजरता है। मप्र से होकर गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यही है। इसकी कुल लंबाई 3,806 किमी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 को पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के रूप में जाना जाता था। ये पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उप्र, राजस्थान, मप्र, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के अलावा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर से होकर गुजरता है। ये मप्र लखनादौन, सिवनी, नरसिंहपुर, सागर और ग्वालियर शहरों से गुजरता है। जो लोग हाईवे के नेटवर्क के जरिए रियल एस्टेट, लॉजिस्टिक पार्क, पर्यटन और कई तरह के उद्योगों में पैसा निवेश करना चाहते हैं उनके लिए मप्र के ये राजमार्ग किसी वरदान से कम नहीं हैं। अगर इन हाईवे और एक्सप्रेस-वे के पास आप जमीन या व्यापार में निवेश करते हैं, तो आने वाले 10 सालों में आप मालामाल हो सकते हैं।

प्रदेश में जितने एक्सप्रेस-वे बन रहे हैं, वे विकास का मजबूत आधार बनेंगे। नर्मदा एक्सप्रेस-वे 906 किमी लंबा है, जो कबीर चबूतरा (अमरकंटक) से झाबुआ मप्र-गुजरात की सीमा तक बन रहा है। एक्सप्रेस-वे रीवा, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, खंडवा, हरसूद, खरगोन, बड़वानी, रतलाम, उज्जैन, देवास की सड़कों को भी जोड़ेगा। नर्मदा एक्सप्रेस-वे से इन जिलों में औद्योगिक और पर्यटन विकास होगा। नर्मदा एक्सप्रेस-वे मप्र को पूर्वी सीमा में छत्तीसगढ़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 45-ई (बिलासपुर-रायपुर) तक और पश्चिम में गुजरात में दिल्ली-मुंबई इंटर कॉरिडोर तक जोड़ेगा।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

क्षेत्रीय संतुलन बनाने में अहम भूमिका

टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के रिटायर्ड जॉइंट डायरेक्टर संजय मिश्रा कहते हैं कि सड़कों और रेलवे का नेटवर्क किसी भी देश के आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सड़कों की कनेक्टिविटी क्षेत्रीय और आर्थिक संतुलन बनाने में अहम भूमिका निभाती है। वे कहते हैं कि एक्सप्रेस-वे बनेंगे तो मप्र की दूसरे राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। ऐसा होने पर मप्र आर्थिक हब के रूप में उभरेगा। वैसे भी मप्र देश के मध्य में स्थित है तो यहां से सभी राज्यों की कनेक्टिविटी हो सकती है। लॉजिस्टिक हब के तौर पर मप्र में बहुत संभावनाएं हैं। उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि अभी केवल इंदौर की कनेक्टिविटी दूसरे राज्यों से अच्छी है तो बाकी शहरों की तुलना में इंदौर बेहद तेजी से विकसित हो रहा है। एक्सप्रेस-वे बनने के बाद इंदौर जैसी विकास की रफ्तार बाकी शहरों को भी मिलेगी। नागरिकों के लिए यातायात सुगम होगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश में 3401 किलोमीटर लंबे 6 एक्सप्रेस-वे बनाए जा रहे हैं। इनमें कई करोड़ की लागत आ रही है। इनके बन जाने के बाद मप्र का हर कोना बड़ी सड़कों से जुड़ जाएगा। जबलपुर में मप्र के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि इनमें से कई सड़कों पर काम शुरू हो गया है और कई पर तैयारी शुरू हो गई है।

शून्य आधार पर बनेगा मप्र का बजट

मप्र की डॉ. मोहन यादव की सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट की तैयारियां शुरू कर दी है। इसे लेकर तिथि भी तय हो गई है। 5 दिसंबर तक विभागों को ऑनलाइन प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। मप्र का बजट पहली बार शून्य आधार पर बनेगा। जिसमें एक-एक योजना का मूल्यांकन होगा। विभागों को योजनाओं का लाभ, खर्च और फायदा बताना होगा। 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक प्रमुख सचिव स्तरीय चर्चा होगी। 27 से 30 जनवरी तक मंत्री और वित्त मंत्री चर्चा करेंगे। इस बजट प्रक्रिया के अंतर्गत सभी विभागों को अपने बजट प्रस्ताव को लेकर यह भी बताना होगा कि उनका बजट अनुमान किस आधार पर किया गया है। विभागों को पिछले साल के खर्च को ध्यान में रखकर प्रस्ताव तैयार करना होगा। इससे वर्तमान योजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों के वित्त पोषण और प्रदर्शन स्तरों की व्यवस्थित समीक्षा और औचित्य पर ध्यान केंद्रित करके संसाधनों को पुन: वंटित किया जा सकेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ऐसी योजनाओं जो वर्तमान में अपनी उपयोगिता खो चुकी है और जिन्हें समाप्त किया जा सकता हो उन्हें चिंहित कर उनका आंकलन किया जा सकेगा।

जीरो बेस बजटिंग के लिए वित्त विभाग के अधिकारियों की ओर से विभिन्न विभागों के अधिकारियों को इस संबंध में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों की ओर से जीरो बेस बजटिंग के संबंध में जिज्ञासाओं का प्रमुखता से समाधान किया गया। वित्त अधिकारियों ने कहा कि जीरो बेस बजटिंग की प्रक्रिया में निश्चित ही समय ज्यादा लगेगा, इसलिए विभाग समय रहते एक्सरसाइज पूरी कर लें, ताकि बाद में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। वित्त विभाग ने बजट निर्माण के संबंध में सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश जारी कर विभागों को वर्तमान में चल रही सभी योजनाओं, नई योजनाओं के मूल्यांकन एवं विश्लेषण सूक्ष्मता से करने के लिए कहा है। साथ ही बजट निर्माण से संबंधित विभिन्न गतिविधियों की टाइम लाइन तय कर दी है। इसके अनुसार ही सभी विभागों को बजट निर्माण संबंधी एक्सरसाइज करनी होगी। विभिन्न विभाग नई योजनाओं के संबंध में वित्त विभाग को 5 दिसंबर तक प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसके बाद वित्त विभाग नई योजनाओं के प्रस्ताव स्वीकार नहीं करेगा। अमूमन वित्त विभाग हर साल बजट की तैयारियां नवंबर से शुरू करता है, पर इस बार जीरो बेस बजटिंग के कारण बजट की तैयारियां करीब एक महीने पहले शुरू कर दी गई हैं, ताकि विभागों के सामने आने वाली परेशानियों का समय रहते समाधान किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2024-25 की बजट गतिविधियों एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान की तैयारी का बजट कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट अनुमान के प्रस्ताव को आईएफएमआईएस में भरा जाकर वित्त विभाग 31 अक्टूबर तक प्राप्त करे। वित्तीय वर्ष 2025-26 में नई योजना के प्रस्ताव वित्त विभाग 5 दिसंबर तक प्राप्त किए जाएं। प्राप्तियों एवं व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (विभागाध्यक्ष एवं उप सचिव) के साथ 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक चर्चा की जाए। विभागों से एफआरबीएम के तहत प्रस्तुत होने वाले विवरण की जानकारी 1 जनवरी, 2025 तक प्राप्त की जाए। प्राप्तियों व व्यय के बजट के प्रस्तावों पर विभागीय अधिकारियों (प्रमुख सचिव, सचिव) के साथ 23 दिसंबर से 15 जनवरी तक चर्चा होगी। वित्त विभाग के भारसाधक उपमुख्यमंत्री द्वारा अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ बजट प्रस्तावों पर 27 जनवरी से 30 जनवरी तक चर्चा होगी। वित्त विभाग के उपमुख्यमंत्री के बजट भाषण के लिए विभागों से 15 जनवरी तक जानकारी प्राप्त करें।

पारंपरिक बजट में पिछले साल के बजट को आधार बनाकर अगले साल का बजट तैयार किया जाता है। वहीं, शून्य-आधारित बजट में हर साल बजट की शुरुआत फिर से शुरू की जाती है। पारंपरिक बजट में पिछले साल के बजट में बदलाव करके अगले साल का बजट तैयार किया जाता है। वहीं, शून्य-आधारित बजट में हर लाइन आइटम की जरूरत और लागत का विश्लेषण करने के बाद बजट तैयार किया जाता है। पारंपरिक बजट में इतिहास के आंकड़ों और भविष्य के अनुमानों के आधार पर आय और खर्चों का अनुमान लगाकर संसाधनों का आवंटन किया जाता है। वहीं, शून्य-आधारित बजट का मकसद असली खर्चों को पेश करना होता है। शून्य आधारित बजट में एक ऐसा बजट होता है जिसमें अनुमान शून्य से प्रारंभ किए जाते हैं। शून्य आधारित बजट में गत वर्षों के व्यय संबंधी आंकड़ों को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। इस प्रणाली में कार्य इस आधार पर शुरू किया जाता है कि अगली अवधि के लिए बजट शून्य है। इस प्रक्रिया में यह बताया जाना जरूरी है कि चली आ रही योजनाओं और नवीन प्रोजेक्ट में खर्चा क्यों और कितना किया जाना चाहिए। इसका सीधा मतलब यह है कि कार्य अथवा परियोजना का जब तक औचित्य नहीं दिया जाता है तब तक नया पैसा जारी नहीं किया जाता है। शून्य-आधारित बजट बनाने में ज्यादा समय लगता है। इसमें पुरानी योजनाओं की समीक्षा करने और नई योजनाओं को शुरू करने में काफी समय लग जाता है।

● **लोकेश शर्मा**

विधानसभा में अनुपूरक बजट लाने की तैयारी शुरू

प्रदेश में दिसंबर में होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र में लाए जाने वाले अनुपूरक बजट प्रस्ताव के लिए वित्त विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके लिए वित्त विभाग ने सभी विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं और यह भी तय कर दिया है कि किस आधार पर अनुपूरक बजट के लिए प्रस्ताव लाए जा सकेंगे। जिन विभागों की ओर से अनुपूरक बजट के प्रस्ताव दिए जाएंगे, उन्हें यह बताना होगा कि 31 अक्टूबर तक उनके विभाग द्वारा बजट में किए गए प्रावधान के आधार पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है। सभी विभागों से 10 नवंबर तक अनुपूरक बजट प्रस्ताव देने के लिए कहा गया है। वित्त विभाग ने साफ किया है कि अनुपूरक बजट में नए वित्तीय मद के प्रस्ताव शामिल नहीं किए जा सकेंगे, जिनमें राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से अतिरिक्त डिमांड की जा रही हो। फाइनेंस ने यह भी क्लियर कर दिया है कि वाहनों की खरीदी के लिए अनुपूरक बजट में कोई प्रस्ताव नहीं दिए जा सकेंगे।

निगम कमिश्नरों का पावर कट

डॉ. मोहन यादव सरकार नगर निगम कमिश्नरों का फाइनेंशियल पावर कम करने की तैयारी में है। पिछले दिनों कुछ मेयरों ने नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बैठक में कहा था कि कमिश्नर एक ही काम के दो-दो टेंडर जारी कर रहे हैं। इसके बाद उनके अधिकारों में कटौती पर विचार चल रहा है। इसके अलावा, कमर्शियल प्रोजेक्ट में बिल्डर से लिया जाने वाला आश्रय शुल्क भी घटाने की तैयारी है। लीज रिन्यूअल और निगम की लीज प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का मुद्दा भी मंत्री के सामने रखा गया था। मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि इन चार में से दो मांगों को पूरा करने के लिए सरकार सैद्धांतिक तौर पर सहमत है। मेयर नगर निगम कमिश्नर के फाइनेंशियल पावर में कटौती क्यों चाहते हैं? आश्रय शुल्क घटाने से क्या असर पड़ेगा?

राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले (अगस्त 2023) महापौर, एमआईसी (महापौर परिषद) नगर निगम आयुक्त के वित्तीय अधिकार दोगुने किए थे। इसके तहत पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम में आयुक्त को 5 करोड़, महापौर को 10 करोड़ और एमआईसी को 10 से 20 करोड़ रुपए के कामों की स्वीकृति देने का अधिकार दिया गया। इसी तरह 5 लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निगम आयुक्त को एक करोड़ रुपए तक, महापौर को 5 करोड़ और मेयर इन काउंसिल को 10 करोड़ और निगम को 10 करोड़ से 20 करोड़ से अधिक तक के कामों के अधिकार दिए गए। जुलाई के महीने में नगर निगम कमिश्नर और मेयर के साथ नगरीय आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक ली थी। इस बैठक में कुछ नगर निगम के मेयर ने कहा कि कमिश्नर्स को जो 5 करोड़ के अधिकार दिए हैं, वे उससे ज्यादा के काम करवा रहे हैं। मसलन 8 करोड़ का काम है तो कमिश्नर ही दो हिस्सों में टेंडर जारी कर रहे हैं। इससे मेयर और एमआईसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। जानकार कहते हैं कि कमिश्नर के वित्तीय अधिकारों में कटौती होने से पब्लिक पर सीधा असर तो नहीं पड़ेगा, लेकिन महापौर के अधिकार बढ़ने से पार्षदों के काम होना आसान हो जाएंगे। उन्हें क्षेत्र के कामों के लिए अफसरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

मप्र में सरकार किसी भी कमर्शियल प्रोजेक्ट में ईडब्ल्यूएस मकान बनाने के एवज में 5 प्रतिशत आश्रय शुल्क लेती है। प्रदेश के बिल्डर्स इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि आश्रय शुल्क हाउसिंग प्रोजेक्ट में लागू करना ठीक है, लेकिन कमर्शियल प्रोजेक्ट में नहीं। कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने यह मुद्दा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के सामने उठाया था। अब सरकार इसे खत्म करने के बजाय 2.5 प्रतिशत करने की तैयारी कर रही है। जानकारों का कहना है कि कमर्शियल प्रोजेक्ट से आश्रय शुल्क घटाने का असर निम्न आय वर्ग के लिए बनाए जाने वाले मकानों की योजना पर जरूर पड़ेगा। सरकार इस राशि का इस्तेमाल ईडब्ल्यूएस स्कीम में करती है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के साथ हुई बैठक में इंदौर के मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने फ्री होल्ड का मसला उठाया था। उन्होंने कहा था कि इंदौर में लीज की प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड करने का काम नहीं हो रहा है। इससे जनता परेशान है। इस पर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने जवाब दिया कि नियमों में बहुत जटिलता है, जिसके कारण यह काम नहीं हो पा रहा है। वर्मा ने यह सुझाव तक दे दिया था कि फ्री होल्ड के अधिकार एमआईसी को दे देना चाहिए। बैठक में मंत्री विजयवर्गीय ने सभी मेयर से लीज प्रकरण और फ्री होल्ड के बारे में जानकारी ली।

जबलपुर के मेयर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने बताया कि दो साल में लीज रिन्यू के 327 में से 132 प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। जबकि फ्री होल्ड के 480 में से 208 प्रकरणों को मंजूरी दी गई है। वहीं इंदौर मेयर ने बताया कि फ्री होल्ड के सिर्फ 9 मामले ही स्वीकृत हो सके हैं। लीज स्वीकृत करने और नवीनीकरण के नियम में मार्च 2023 में संशोधन किया था। जिसके तहत नगर निगमों में आयुक्त, एमआईसी और निगम परिषद के बीच नए सिरे से अधिकारों का बंटवारा किया था। बावजूद इसके निगमों में लीज के प्रकरण बड़ी संख्या में लंबित पड़े हैं।

5 लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले निकाय में कमिश्नर को 2 करोड़, एमआईसी को 2 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ तक। निगम परिषद को 10 करोड़ से ज्यादा लेकिन 20 करोड़ तक। नगरीय प्रशासन आयुक्त को 20 करोड़ से ज्यादा लेकिन 50 करोड़ तक। वहीं राज्य सरकार को 50 करोड़ से ज्यादा तक के अधिकार है। वहीं 5 लाख से कम जनसंख्या वाले निकाय में कमिश्नर को 40 लाख रुपए, एमआईसी को 40 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक। निगम परिषद को 2 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ तक, वहीं नगरीय प्रशासन आयुक्त को 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक। राज्य सरकार को 10 करोड़ रुपए तक के अधिकार हासिल है।

● **विकास दुबे**

मास्टर प्लान के कारण अटके बड़े प्रोजेक्ट

मंत्री विजयवर्गीय हाल ही में जबलपुर दौरे पर गए थे, तब इस मुद्दे को क्रेडाई ने उठाया था। दरअसल, नगर पालिक निगम की धारा-16 में नियम है कि 5 एकड़ से अधिक के हाउसिंग प्रोजेक्ट की अनुमति शहर के बाहर मिलेगी। इसके लिए नक्शा भी नगर निगम से नहीं, बल्कि टीएंडसीपी से स्वीकृत कराना पड़ता है। यदि किसी शहर का मास्टर प्लान लागू हो जाता है तो धारा-16 समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हाउसिंग प्रोजेक्ट शहर में करना आसान हो जाएगा। बताया जाता है कि मास्टर प्लान के इंतजार में प्रदेश में 135 एकड़ के प्रोजेक्ट पेंडिंग हैं। मुख्य सचिव अनुराग जैन का फोकस बड़े शहरों के मास्टर प्लान पर है। मुख्य सचिव अनुराग जैन ने पदभार ग्रहण करने के बाद 3 अक्टूबर को विभाग प्रमुखों की पहली बैठक ली थी। बैठक में मुख्य सचिव को बताया गया कि भोपाल और इंदौर के मास्टर प्लान पर काम चल रहा है। ये जल्द ही आ जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा कि पुराने सातों संभाग (नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल को छोड़कर) मुख्यालयों के मास्टर प्लान साथ में तैयार किए जाएं।

सिंहस्थ में दिखेगा मप्र का वैभव

सिंहस्थ को लेकर पूरे प्रदेश के विकास पर फोकस

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन ने कहा कि उज्जैन सहित प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में समग्र विकास के लिए सबकी खुशहाली के द्वार खुलेंगे। सभी देव-स्थानों के आसपास हमारे धर्माचार्य आ जाएं, हमारी यह प्राथमिकता हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर-उज्जैन मेट्रो ट्रेन संचालन की स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि उज्जैन, देवास, फतेहाबाद, इंदौर को जोड़ते हुए सर्किल वंदे मेट्रो ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। रेल रूट के साथ उज्जैन के सभी मार्गों को भी व्यवस्थित किया जा रहा है। उज्जैन से निकलने वाले सभी मार्ग फोरलेन किए जाएंगे। वर्तमान एयरस्ट्रिप का भी उन्नयन कर टेक्निकल रूप से एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिससे 12 महीने हवाई यातायात सुविधा भी उज्जैन को मिल सके।

सिंहस्थ-2028 कुंभ मेला को लेकर मप्र के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने कहा है उज्जैन की पहचान साधु-संतों से है। हर 12 साल पर यहां एक बार सिंहस्थ कुंभ मेला का भव्य आयोजन होता है। इस बार भी कुंभ मेले को ऐतिहासिक रूप देने की तैयारी की जा रही है। देश के कोने-कोने से यहां आने वाले साधु-संतों के ठहरने, कथा, भागवत जैसे धार्मिक आयोजनों के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करने में जुटी है। प्रदेश सरकार ने साधु-संतों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का मन बनाया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महाकाल महालोक बनने के बाद से बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। निरंतर धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन-इंदौर सिक्स-लेन कार्य की टेंडर प्रक्रिया हो गई है। उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड फोर-लेन मार्ग का शीघ्र भूमिपूजन किया जाएगा। इस वृहद् योजना में इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आदि को विकसित किया जाएगा। उज्जैन के धार्मिक मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि हरिद्वार में जिस प्रकार साधु-संतों के अच्छे आश्रम बने हुए हैं, उसी प्रकार उज्जैन में भी साधु-संतों के स्थायी आश्रम बनवाने के प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से योजना को आकार दिया जाएगा। सिंहस्थ के दृष्टिगत सड़क, बिजली, पेयजल, जल-निकासी इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्थायी अधोसंरचना का निर्माण भी होगा, जिससे अस्थायी निर्माण से होने वाली समस्याएं निर्मित न हों। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि उज्जैन में भी हरिद्वार की तरह साधु-संतों, महंतों, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर को स्थायी आश्रम बनाने की अनुमति दी जाएगी। उज्जैन की पहचान साधु-संतों से है। 12 साल में एक बार आयोजित होने वाला सिंहस्थ का आयोजन 2028 में किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान साधु-संतों को उज्जैन में आने, ठहरने, कथा, भागवत जैसे आयोजन के लिए पर्याप्त रूप से स्थान की जरूरत होगी, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के साथ आश्रम बनाए जाने की योजना बनाई है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हरिद्वार में जिस प्रकार साधु-संतों के अच्छे आश्रम बने हुए हैं, उसी प्रकार उज्जैन में भी साधु संतों के स्थायी आश्रम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। उज्जैन विकास प्राधिकरण के माध्यम से इस बड़ी योजना को आकार दिया जाएगा। सिंहस्थ को देखते हुए सड़क, बिजली, पेयजल, जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए भी स्थायी अधोसंरचना का निर्माण किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन को धार्मिक शहर के रूप में विकसित करने के लिए सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कार्ययोजना तैयार की गई है। सभी प्रकार के फोरलेन, सिक्सलेन ब्रिज आदि स्थायी अधोसंरचना विकास के कार्य किए जाएंगे। सभी मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ साधु-संतों के लिए आश्रम निर्माण के कार्य समानांतर रूप से किए जाएंगे। समाज के इच्छुक सनातन धर्मावलंबियों के माध्यम से अन्न क्षेत्र, धर्मशाला, आश्रम, चिकित्सा केंद्र, आयुर्वेद केंद्र आदि सार्वजनिक गतिविधियों के संचालन कार्य को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि साधु-संतों को आश्रम बनाने के लिए नियम बनाए गए हैं। 5 बीघा के एक भूखंड पर ही भवन का निर्माण किया जा सकेगा। शेष 4 बीघा भूखंड खुला रहेगा, जिसमें पार्किंग आदि व्यवस्थाओं के लिए पर्याप्त खुला स्थान रहे। यह अनुमति केवल साधु-संतों, महंत, अखाड़ा प्रमुखों, महामंडलेश्वर को ही दी जाएगी। व्यक्तिगत और कमर्शियल उपयोग के लिए इस प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि महाकाल महालोक बनने के बाद से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। निरंतर यहां धार्मिक आयोजनों का क्रम जारी रहता है। ऐसे में यह योजना धर्मावलंबियों के लिए बड़ी लाभकारी सिद्ध होगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरी योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन-इंदौर सिक्स लेन कार्य की भी टेंडर प्रक्रिया हो गई है। वहीं उज्जैन-जावरा ग्रीन फील्ड फोरलेन मार्ग का शीघ्र भूमिपूजन किया जाएगा। इसी प्रकार वृहद योजना के तहत इंदौर, उज्जैन, धार, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर आदि को विकसित किया जाएगा। उज्जैन के धार्मिक मूल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए विकास कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर-उज्जैन मेट्रो ट्रेन के संचालन की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दे दी गई है। इसी के साथ उज्जैन, देवास, फतेहाबाद, इंदौर को जोड़ते हुए सर्किल वंदे मेट्रो ट्रेन का भी संचालन किया जाएगा। जिसकी गति मेट्रो ट्रेन की तुलना में अधिक होगी। उज्जैन से निकलने वाले सभी मार्ग फोरलेन किए जाएंगे। वर्तमान एयरस्ट्रिप का भी उन्नयन कर टेक्निकल रूप से एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ताकि 12 महीने हवाई यातायात सुविधा भी उज्जैन को मिल सके।

● **कुमार राजेंद्र**

अंधविश्वास की इतेहा...

हाल ही में छत्तीसगढ़ सूबे के सुकमा जिले के इतकाल गांव में लोगों ने जादू-टोने के शक में पांच लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी। मरने वालों में तीन महिलाएं भी हैं और सभी मृतक एक ही परिवार के थे। वहीं हाथरस जिले में एक प्राइवेट स्कूल में 11 वर्षीय छात्र की हत्या के पीछे काले जादू और अंधविश्वास का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। इस घटना में पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें स्कूल का प्रिंसिपल भी शामिल है। जांच में खुलासा हुआ है कि स्कूल की प्रसिद्धि और तरक्की के लिए काले जादू के चलते बच्चे की बलि दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है।

घटना डीएल पब्लिक स्कूल की है, जहां छात्र हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहा था। स्कूल प्रबंधन ने उसके परिजनों को फोन कर बताया कि बच्चे की तबीयत खराब है और उन्हें जल्द स्कूल पहुंचने को कहा गया। जब परिवार वहां पहुंचा, तो उन्हें काफी देर तक बच्चे से मिलने नहीं दिया गया। गुमराह करने के लिए कहा गया कि कृतार्थ को अस्पताल ले जाया गया है। कुछ समय बाद पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल दिनेश बघेल को सादाबाद इलाके में एक कार के साथ गिरफ्तार किया, जिसमें छात्र का शव पाया गया। छात्र के पिता ने दिनेश बघेल समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। कृतार्थ के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जिसमें यह खुलासा हुआ कि उसकी मौत गला दबाने से हुई है। उसके गले पर चोट के निशान भी मिले। पुलिस जांच में सामने आया कि छात्र की हत्या काले जादू के चक्कर में की गई। स्कूल प्रबंधक के पिता, जो एक तांत्रिक हैं, ने सुझाव दिया था कि बच्चे की बलि देने से स्कूल की तरक्की होगी। इसी कारण से दिनेश बघेल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर इस घिनौने अपराध को अंजाम दिया।

यह खबर विकसित भारत, स्मार्ट सिटी की घोषणाओं, देश में हवाई अड्डे बनाने की होड़ और अब भारत को दुनिया का चिप हब बनाने की दिशा में जनता के सामने रखी जाने वाली सरकारी तस्वीरों के बीच उस भारत की तस्वीर है, जो अभी तक डायन प्रथा का दंश झेल रहा है। हैरत होती है कि देश में स्कूलों, विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि, साक्षरता दर बढ़ने, बेहतर संचार-व्यवस्था, प्राथमिक अस्पतालों की संख्या में इजाफा होने के बावजूद डायन-प्रथा आज भी जिंदा है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड शाखा के अनुसार, वर्ष 2022 में देश में 85 लोगों की हत्या डायन मानकर कर दी गई इनमें से ज्यादातर मामले छत्तीसगढ़, मप्र, झारखंड और ओडिशा राज्यों के थे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड शाखा के आंकड़ों के अनुसार, देश में वर्ष 2015 से वर्ष 2021 के दरमियान डायन-प्रथा के तहत 663 हत्याएं हुईं, जो मामले दर्ज किए गए यानी सालाना औसतन 95 मामले ऐसे दर्ज किए गए, जिनमें लोगों की हत्या उन्हें डायन कहकर कर दी गई ऐसी हत्याओं में 65 फीसदी मामले झारखंड, छत्तीसगढ़, मप्र और ओडिशा राज्यों से थे।

गौरतलब है कि डायन बिसाही सरीखी क्रूर कुप्रथा भारत के 12 राज्यों में अधिक है, इसमें झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, उप्र, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और असम शामिल हैं। यह क्रूर प्रथा कम आय वाले इलाकों और ऐसे समुदायों में जहां सामाजिक, आर्थिक असमानता के अलावा लैंगिक असमानता हावी है, में जिंदा है। इसके साथ ही अशिक्षा, जागरूकता का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच कम होने जैसे कारण भी इन प्रथाओं को बढ़ावा देते हैं। पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस कुप्रथा का शिकार अधिकतर महिलाओं को ही बनाया जाता है।

सवाल यह है कि इस पुरुष प्रधान समाज, व्यवस्था में अक्सर महिलाएं ही इसकी गिरफ्त में क्यों आती हैं? वो भी ज्यादातर मौकों पर ऐसी महिलाओं को डायन कहकर प्रताड़ना दी जाती है या उनकी हत्या कर दी जाती है, जो उम्रदराज, अकेली, निसंतान या विधवा होती हैं। इसके पीछे एक मुख्य मंशा महिलाओं को कमतर आंकना, उनकी संपत्ति हड़पना, किसी रंजिश के तहत समाज में उन्हें बदनाम करना, एक खास उम्र (प्रजनन-अवस्था) के बाद उन्हें बेकार समझना आदि होते हैं। पीड़ित लोगों में अधिकतर गरीब, आदिवासी और दलित होते हैं। डायन घोषित करने के लिए जादू-टोना और काला जादू करने जैसे शक भी करके या आरोप लगाकर लोग, समुदाय पीड़ित और उसके परिवार को कई-कई तरह की यातनाएं देते हैं। कई बार तो यातनाएं देने वालों में परिवार के लोग भी शामिल होते हैं।

ऐसी कुप्रथाओं के तहत किसी की हत्या की घटनाएं हैरत में डालती हैं; क्योंकि कई राज्यों में इस कुप्रथा के खिलाफ कानून भी बने हुए हैं। बिहार देश का ऐसा पहला राज्य है, जिसने 1993 में ऐसा कानून बनाया था। इस कानून के तहत किसी को प्रताड़ित करने वालों को 6-6 माह तक की कैद की सजा या 2,000 रुपए तक के आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया था। आज बिहार के अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, असम में भी इस तरह की प्रताड़ना के खिलाफ कानून बने हुए हैं।

● **बृजेश साहू**

विकास की परिभाषा पर सवाल उठाती कुप्रथा

दरअसल इस कुप्रथा के कई सामाजिक, जातीय, आर्थिक व मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं। यह कुप्रथा विकास की गढ़ी गई परिभाषा पर भी सवाल उठाती है। देश में जनकल्याण, महिलाओं के उत्थान, सशक्तिकरण के लिए चालू महत्वाकांक्षी योजनाओं पर भी सोचने को मजबूर करती है। दलित, आदिवासी कल्याण, उत्थान के नाम पर सियासत कभी थमती नहीं दिखती, हर राजनीतिक पार्टी उनका सबसे अधिक हितैषी होने का दावा करती है; लेकिन हकीकत कुछ और ही होती है। 21वीं सदी के दो दशक बीत चुके हैं। इसरो भारत को स्पेस के क्षेत्र में बहुत आगे ले जाने के लिए प्रयासरत है। वैज्ञानिक और डॉक्टर भी रोगियों के इलाज को सुलभ बनाने की दिशा में शोध करने में जुटे हैं। शेयर बाजार भी रिकॉर्ड बनाता रहता है। पर इसके बीच छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कारण पांच लोगों की हत्या हमें लोगों की घटिया मानसिकता को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए आईना दिखाती है।

धधकते जंगलों से बढ़ रहा है उत्सर्जन

जंगल न केवल पर्यावरण और जैवविविधता को बनाए रखते हैं, बल्कि साथ ही कार्बन सिंक के रूप में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यही वजह है कि जलवायु परिवर्तन को बढ़ते प्रभावों को सीमित करने के लिए इन्हें बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन पिछले कुछ दशकों से जिस तरह जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उससे इनके कार्बन सिंक के रूप में काम करने की क्षमता घटती जा रही है, जो जलवायु परिवर्तन के लिहाज से बेहद चिंताजनक है। जंगलों में लगती आग की घटनाओं और उससे होने वाले उत्सर्जन को लेकर किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि 2001 के बाद से इस दावाग्नि से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड (सीओ2) उत्सर्जन में 60 फीसदी की वृद्धि हुई है। वहीं जलवायु के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील उत्तरी बोरियल वनों में यह उत्सर्जन करीब तीन गुना बढ़ गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया (यूईए) के नेतृत्व में किए इस अध्ययन के नतीजे अंतरराष्ट्रीय जर्नल साइंस में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने दुनिया को अलग-अलग पाइरोम्स में वर्गीकृत किया है। यह पाइरोम्स ऐसे क्षेत्र हैं जहां जंगल में लगने वाली आग के पैटर्न समान पर्यावरणीय, मानवीय और जलवायु कारकों से प्रभावित होते हैं। इसने हाल में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं में वृद्धि के मुख्य कारणों पर प्रकाश डाला है।

शोधकर्ताओं के मुताबिक यह अपनी तरह का पहला अध्ययन है जिसमें वन क्षेत्रों और दूसरे क्षेत्रों में लगने वाली आग की वैश्विक स्तर पर जांच की है। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनके मुताबिक यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका के बोरियल वन क्षेत्रों में फैले सबसे बड़े पाइरोम में आग की वजह से होने वाले उत्सर्जन 2001 से 2023 के बीच करीब तीन गुना बढ़ गया है। रिसर्च से पता चला है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से बाहर मौजूद वनों में भी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इन क्षेत्रों में प्रतिवर्ष करीब 50 करोड़ टन अतिरिक्त सीओ2 का उत्सर्जन हो रहा है। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उत्सर्जन का केंद्र उष्णकटिबंधीय जंगलों से हटकर उष्णकटिबंधीय जंगलों के बाहरी क्षेत्रों की ओर शिफ्ट हो रहा है।

रिसर्च के मुताबिक उत्सर्जन में हो रही यह वृद्धि मौसम से जुड़ी है, जो आग लगने की आशंका को और बढ़ा रही है। जैसे कि लू और सूखे के दौरान गर्म और शुष्क परिस्थितियां चीजों को बना रही हैं। इसी तरह वन विकास ने अतिरिक्त वनस्पति भी पैदा की हैं जो आग को बढ़ावा दे रही हैं। उत्तरी क्षेत्रों में तेजी से हो रही गर्मी से ये दोनों प्रवृत्तियां और बदतर हो गई हैं, जहां तापमान वैश्विक औसत से दोगुनी गति से बढ़ रहा है। अध्ययन से पता चला है कि पिछले दो दशकों में न केवल जंगलों में आग लगने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है, बल्कि उनकी गंभीरता भी बढ़ी है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी रिपोर्ट में भी बढ़ती दावाग्नि के बारे में चेतावनी दी थी कि सदी के अंत तक बढ़ते तापमान के साथ ऐसी घटनाओं में 50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है। देखा जाए तो दुनियाभर के जंगलों में लगने वाली आग की घटनाएं अब बढ़ते तापमान के साथ सामान्य होती जा रही हैं। इसी तरह कार्बन दहन दर, जो प्रति इकाई क्षेत्र में कितना कार्बन उत्सर्जित होता है, उसके आधार पर आग की गंभीरता की माप है। वो 2001 से 2023 के बीच दुनियाभर में करीब 50 फीसदी बढ़ गई है। ऐसे में शोधकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि इस तेजी से फैलती आग को तभी रोका जा सकता है जब जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों जैसे जीवाश्म ईंधन से हो रहे उत्सर्जन से निपटा जाए।

देखा जाए तो यह जंगल दुनिया के लिए बेहद मायने रखते हैं। जलवायु लक्ष्यों को भी हासिल करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इनकी वृद्धि जहां ज्यादा से ज्यादा कार्बन को स्टोर करने में मदद करती है, जिससे वातावरण में सीओ2 का स्तर घटता है, नतीजन ग्लोबल वार्मिंग की दर धीमी हो जाती है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना न केवल पर्यावरण बल्कि इंसानों के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद अहम है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ) द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल फारेस्ट रिसोर्स एसेस्समेंट 2020 के अनुसार 1990 से लेकर अब तक दुनियाभर के करीब 17.8 करोड़ हेक्टेयर में फैले जंगल खत्म हो चुके हैं। ऐसे में यदि पृथ्वी पर मौजूद हर व्यक्ति के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति केवल 0.52 हेक्टेयर जंगल बाकी बचे हैं। ऐसे में इन जंगलों की मदद से कार्बन हटाने की योजनाएं तभी कारगर होंगी जब जंगल स्थाई रूप से कार्बन को स्टोर कर सकें, लेकिन जंगलों में लगती आग इसे जोखिम में डाल देती है। उदाहरण के लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर धधकते जंगल अब 20 साल पहले की तुलना में 50 करोड़ टन

आग से जलने वाले कुल क्षेत्र में एक चौथाई की कमी आई

दिलचस्प बात यह है कि दावाग्नि से होने वाले उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जबकि उसी दौरान उष्णकटिबंधीय सवाना में आग लगने की घटनाओं में गिरावट आई है। अध्ययनों से पता चलता है कि 2001 के बाद से, सभी प्रकार की आग से जलने वाले कुल क्षेत्र में एक चौथाई की कमी आई है। ये निष्कर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं क्योंकि जंगलों में लगने वाली आग सवाना के घास के मैदानों में लगने वाली आग से कहीं ज्यादा भयंकर होती है। इसकी वजह से कहीं ज्यादा धुआं होता है, जो आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित करता है। इतना ही नहीं इसकी वजह से वायु गुणवत्ता में भी गिरावट आती है जो इस आग से दूर रहने वाले समुदायों के लिए भी खतरा पैदा कर देती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि अध्ययन इस धारणा को गलत साबित करता है कि आग से जलने वाले कुल क्षेत्र में हर साल कमी आ रही है, इसका मतलब यह है कि जंगलों में लगने वाली आग का प्रभाव भी कम हो रहा है। ऐसे में यह जरूरी है कि जलते जंगलों को बचाने और उनकी बहाली के गंभीरता से प्रयास किए जाने चाहिए। इसके लिए न केवल जंगलों के प्रबंधन पर ध्यान देना जरूरी है। साथ ही स्थानीय समुदायों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। जनता में भी इसको लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है।

जल सहेलियों की जलक्रांति

बुंदेलखंड के छतरपुर जिले की जल सहेलियों ने अपने गांवों को जल संकट से उबारने में अकल्पनीय काम करके दिखाए हैं, चाहे वह पहाड़ को काटना हो या मृतप्राय नदी को जिंदा करना। भेल्दा ग्राम पंचायत बुंदेलखंड क्षेत्र में मप्र के हिस्से में आने वाले छतरपुर जिले के बड़ामलहरा ब्लॉक में स्थित है। सूखे और जल संकट के लिए कुख्यात बुंदेलखंड के अन्य गांवों की तरह भेल्दा और अगरौठा भी 2018 तक इस संकट से अछूते नहीं थे। अगरौठा की पानी पंचायत की सदस्य किरन आज भी वह दिन याद करके गुस्से से भर उठती हैं, जब ऊंची जाति के लोग अपने घर के पास लगे एकमात्र चालू हैंडपंप से दलितों को पानी नहीं भरने देते थे। वह बड़े संकोच के साथ अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहती हैं, 2018 में हमारे बर्तन फेंके गए थे। दिन में अक्सर लड़ाई के डर से हम रात को पानी भरने पहुंचते थे। पानी को लेकर इस तरह के जातीय भेदभाव की जानकारी प्रशासन तक पहुंची तो दलितों के लिए टैंकर की व्यवस्था की गई। किरन कहती हैं, अगड़ी जाति के कुछ लोगों को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने हमारे टैंकर में गोबर घोल दिया, ताकि हम पानी का उपयोग न कर पाएं।

पठारी क्षेत्र होने के कारण इस ग्राम पंचायत में अचानक और तेजी के साथ बरसा पानी पूरा बहकर निकल जाता है। पानी का ठहराव न होने से भूजल के स्रोतों जैसे हैंडपंपों और कुओं का गर्मियों में सूखना आम था। किसान केवल खरीफ की फसल ले पाते थे। पानी की कमी ने उन्हें रबी की फसल से दूर कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक, साल 2000 के बाद पानी का संकट काफी बढ़ गया था। मुख्य रूप से खेती पर निर्भर यहां की आबादी कम बारिश, सूखा और खेती से सीमित आय में गुजर-बसर न कर पाने के कारण दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में पलायन के लिए मजबूर थी। पानी संकट को देखते हुए ही सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज से एक विशाल तालाब अगरौठा में बनवाया था और सिंचाई के लिए इससे नहर भी निकाली गई थी लेकिन इससे खास फायदा नहीं हुआ, क्योंकि तालाब बरसात में भी नहीं भरता था।

किरन और गांव की अन्य महिलाएं जिन्हें 1-2 किलोमीटर दूर से पानी ढोना पड़ता था, यह बात अच्छी तरह जानती थीं कि गांव की बदहाली का सूखे तालाब से सीधा संबंध है और अगर इसमें पानी भर जाए तो यह बदहाली दूर हो सकती है। इन महिलाओं ने पानी पंचायत समिति का गठन किया और समिति में सबसे सक्रिय महिलाओं को जल सहेली के रूप में चुना गया। किरन भी उनमें शामिल थीं। अगरौठा की पानी पंचायत की बैठकों में महिलाओं ने सोचा कि अगर पहाड़ के एक हिस्से को काटकर जंगल से पानी पहुंचने का रास्ता बना दिया जाए तो हमेशा सूखा रहने वाला 70 एकड़ का तालाब भर सकता है और जल संकट दूर हो सकता है। मई 2020 में अगरौठा की पानी पंचायत की बैठक में तय हुआ कि पहाड़ काटकर पानी का रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन इस काम में एक बड़ी अड़चन यह थी कि पहाड़ वन विभाग के अधीन था और इसके लिए विभाग की अनुमति जरूरी थी। अनुमति के लिए महिलाओं का समूह जिला वन अधिकारी से मिला और पानी पंचायत में पहाड़ काटने के अपने निर्णय से अवगत कराया तो वह इस शर्त पर राजी हुए कि इस काम में मशीनों का उपयोग न हो।

वन विभाग की सशर्त अनुमति के बाद अगरौठा की महिलाओं ने जून 2018 में गांव और पड़ोसी गांव भेल्दा की महिलाओं को एकजुट किया और फावड़े, कुदाल, सब्बल, हथौड़े और गैंती जैसे औजारों से पहाड़ खोदने का काम शुरू हुआ। करीब 18 महीने चले इस काम में ग्राम पंचायत की करीब 300 महिलाएं जुटी रहीं और 2021 के अंत तक 107 मीटर लंबा, करीब 12 फीट गहरा और चौड़ा पहाड़ चीरने में उन्हें कामयाबी मिल गई। इसका सुखद नतीजा 2022 के मानसून में दिखा जब गांव का तालाब लबालब भर गया। ग्रामीणों ने पहली बार गांव के तालाब को इतना भरा हुआ देखा। इस काम में पूरी लगन से जुटने वाली किरन कहती हैं कि जब हमने पहाड़ खोदकर पानी लाने के पानी पंचायत का निर्णय गांव के लोगों को बताया तो अधिकांश लोगों खासकर पुरुषों द्वारा हमारा मजाक उड़ाया गया। यहां तक कि हमें परिवार का भी सहयोग नहीं मिला। लेकिन जब इस काम में सफलता मिल गई और पहली बार तालाब भरा तो सभी महिलाओं की हिम्मत की दाद देने लगे।

तालाब में पानी भरने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि सूखे पड़े कुएं और हैंडपंप जिंदा हो गए। अगरौठा गांव के 50 वर्षीय किसान प्रेम लाल लोदी के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। प्रेम लाल के परिवार के हिस्से में 57 एकड़ खेत हैं जिन पर 11 सदस्यों की हकदारी है। अपने धान के खेत में कीटनाशक दवा का छिड़काव कर रहे प्रेम लाल का कहना है कि तालाब में पानी रहने से उनके खेत के पास से गुजर रहे नाले में तालाब से रिसकर पानी आने लगा जिससे पूरे साल पानी की उपलब्धता सुनिश्चित हो गई। नाले के पानी को तीन जगह चेकडैम बनाकर रोकने से भूजल स्तर में भी सुधार हुआ। तालाब से निकलने वाले गांव में ऐसे दो नाले हैं जिन पर जल सहेलियों की पहल से 7 चेकडैम बनाए गए हैं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

कौन हैं जल सहेलियां

बुंदेलखंड के गांवों में जल सहेलियां उन महिलाओं का समूह है जो गांव में पानी से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में तत्परता और सक्रियता दिखाती हैं। इनका मुख्य काम पानी का संरक्षण और संचयन, कुओं को गहरा करना, हैंडपंप की मरम्मत, चेकडैम और तालाब जैसी जल संरचनाओं का पुनर्निर्माण, समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से मिलना और लगातार फॉलोअप करना और समुदाय को जोड़ना है। पूरे बुंदेलखंड में ऐसी 1,000 से अधिक जल सहेलियों का बड़ा नेटवर्क है। परमार्थ समाजसेवी संस्थान द्वारा प्रकाशित पुस्तक प्रयास : नदी पुनर्जीवन की मानें तो जल सहेलियों ने पानी पंचायत के माध्यम से न केवल 2,256 हेक्टेयर कृषि भूमि को कुल 10.12 बिलियन लीटर पानी उपलब्ध कराया है बल्कि कृषि पद्धति में बदलाव व स्मार्ट कृषि से कुल 3.22 बिलियन लीटर पानी की बचत भी की है।

महाराष्ट्र और झारखंड की चुनावी कहानी

अकेले दम पर सत्ता नहीं...!

हरियाणा और जम्मू-कश्मीर के बाद अब भाजपानीत एनडीए और कांग्रेसनीत इंडिया गठबंधन की महाराष्ट्र और झारखंड में अग्निपरीक्षा है। अगर पुराने चुनावों के परिणाम देखें तो महाराष्ट्र में 40 और झारखंड में 24 साल से किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। यानि दोनों राज्यों में गठबंधन की सरकार बनती आ रही है और इस बार भी बनने की संभावना है। लेकिन इस बार दोनों गठबंधनों की पार्टियों में टिकट को लेकर जिस तरह का घमासान दिखा उससे तो एक बात तय है कि ये चुनाव आसान नहीं होने वाले हैं।

● राजेंद्र आगाल

दो राज्यों हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और इनकी टीमों की अग्निपरीक्षा अब महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में होनी है। इन दोनों राज्यों के चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं होने वाले। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में 4 दशक और झारखंड में ढाई दशक के दौरान किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला है। इसको देखते हुए एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपने-अपने सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरने का निर्णय लिया है। लेकिन टिकटों के बंटवारे में समन्वय नहीं बन पाने के कारण गठबंधन की गांठ कमजोर पड़ गई है। इसका परिणाम यह देखने को मिल रहा है कि जैसे-तैसे पार्टियों ने टिकट का वितरण तो कर दिया है, लेकिन जीत का गणित उलझ गया है। अब देखना यह है कि ये चुनाव क्या गुल खिलाते हैं।

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा के लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में हैं। यही कारण है कि बागी भी ज्यादा हैं। प्रदेश की लगभग हर सीट पर बागी हैं। अब सबकी निगाह नाम वापसी की अंतिम तारीख (4 नवंबर) पर है। उसके बाद पता चलेगा कि लड़ाई कैसी होगी। इस बार 7,995 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। आखिरी दिन 4,996 ने पर्चे भरे। महायुति और एमवीए ने नामांकन खत्म होने के बाद भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बताया। प्रत्याशी देखें तो महायुति में 148 उम्मीदवारों के साथ भाजपा और एमवीए में 103 के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। वहीं, शिवसेना-शिंदे ने 80, एनसीपी अजित ने 53, शिवसेना-उद्धव ने 89, एनसीपी-शरद ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। इन सबके अलावा इस बार महायुति ने 5 सीटें सहयोगी पार्टियों के लिए छोड़ी हैं। दूसरी तरफ एमवीए के छोटे सहयोगी दल 6 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। महायुति की 2 और एमवीए की 3 सीटों पर अभी भी स्थिति साफ नहीं है। वहीं झारखंड में एनडीए में भाजपा 68, सुदेश महतो की आजसू 10, नीतीश कुमार की जदयू दो और चिराग पासवान की एलजेपीआर एक सीट पर चुनाव लड़ रही है। वहीं, इंडिया ब्लॉक में झामुमो 43, कांग्रेस 30, लालू यादव की राजद ने 6 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। तीन सीटों बगोदर, सिंदरी और निरसा में भाकपा माले के कैंडिडेट को सपोर्ट किया है। जबकि, भाकपा माले ने धनवार सीट से अपने प्रत्याशी को वापस नहीं लेने का ऐलान किया है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की सियासी सरगर्मी के बीच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का एक बयान चर्चा के केंद्र में है। फडणवीस ने कहा कि हमें जमीनी हकीकत को लेकर व्यावहारिक होना पड़ेगा। भाजपा अकेले दम पर महाराष्ट्र चुनाव नहीं जीत सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जरूर होगी। उन्होंने विश्वास जताया कि भाजपा, शिवसेना, एनसीपी और आरपीआई मिलकर सरकार बनाएंगी। महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटें है, जिसके लिहाज से बहुमत के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। 1985 में आखिरी बार बहुमत का आंकड़ा कांग्रेस को मिला था, उसके बाद से करीब 40 साल हो रहे हैं, राज्य में किसी भी एक दल को 145 विधानसभा सीटों पर जीत नहीं मिली। इस तरह चार दशक महाराष्ट्र की राजनीति गठबंधन के सहारे चल रही है। भाजपा और कांग्रेस जैसे राष्ट्रीय दल अपने दम पर सियासी आत्मनिर्भर नहीं है बल्कि छत्रपों से गठबंधन या फिर समर्थन से सरकार बनाई है। कांग्रेस से शिवसेना और भाजपा तक ने सरकार बनाई तो बैसाखी के सहारे। इस जमीनी हकीकत को फडणवीस बखूबी समझ रहे हैं।

सियासी घरानों के स्टार-किड्स की अंगड़ाई

महाराष्ट्र की राजनीति के कई दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी भी चुनाव मैदान में किस्मत आजमाने जा रहे हैं, और करीब-करीब हर सीट पर एक जैसी चुनौती मिल रही है, लेकिन सबसे दिलचस्प तो नारायण राणे परिवार का मामला है, जिनके दोनों बेटे चुनाव मैदान में हैं। एक भाजपा के टिकट पर तो दूसरा एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार के रूप में। दूसरी तरफ आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे की तरह बाकियों के कंधे पर भी अपनी विरासत बचाने की जिम्मेदारी आ पड़ी है। बॉलीवुडिया भाषा में कहें तो सियासी प्रोडक्शन हाउस के नौनिहाल यानी नेपो किड्स चुनाव मैदान में उतर आए हैं। चूंकि, इस बार दोनों ओर करीब छह पार्टियां अलग-अलग गठबंधन में हैं, इसलिए परिवारवाद के खिलाफ कोई नैतिकता का डंडा नहीं चला पा रहा है। जहां तक चुनावी कसौटी की बात है, बहुत कम इलाके हैं जहां चैलेंज थोड़ा कम है। कट्टर हिंदुत्व की राजनीति करने वाले बालासाहेब ठाकरे की तीसरी पीढ़ी के दो युवा नेता मुंबई के दो अलग-अलग इलाकों से चुनाव मैदान में हैं। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मंत्री रह चुके बेटे आदित्य ठाकरे वर्ली से, तो ठाकरे परिवार के ही एमएनएस नेता राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 2019 में आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के रसूखदार ठाकरे परिवार के पहले सदस्य थे, जिन्होंने चुनावी राजनीति का रुख किया था। तब तक न तो उनके पिता उद्धव ठाकरे और न ही चाचा राज ठाकरे ही ऐसा कर पाए थे। बालासाहेब ठाकरे के बारे में तो कहा जाता है कि उनको तो रिमोट पॉलिटिक्स में ही ज्यादा मजा आता था। उद्धव ठाकरे भी मुख्यमंत्री बनने के बाद ही विधान परिषद का चुनाव लड़े थे और राज ठाकरे के चुनाव लड़ने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ऐसा हुआ तो बाल ठाकरे की विरासत पर दावेदारी कमजोर हो जाएगी।

भाजपा ने उस जमाने में शिवसेना के साथ गठबंधन बनाया था, जब दोनों ही पार्टियों की न सिर्फ राष्ट्रीय फलक पर बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी कोई खास हैसियत नहीं थी। उस समय शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ही गैर-कांग्रेसवाद का चेहरा थे। वे हिंदुत्व और मराठी मानुष दोनों को एक साथ लेकर राजनीति कर रहे थे। उस जमाने की भाजपा ने ठाकरे की बनाई जमीन पर ही अपनी राजनीति शुरू की और शिवसेना की सहयोगी के तौर पर महाराष्ट्र में पांव जमाए, लेकिन आत्मनिर्भर नहीं बन सकी। महाराष्ट्र की सियासत में भाजपा का अब तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन 2014 में रहा था, जब वह अकेले चुनाव लड़ी थी और 122 सीटें जीती थी। भाजपा ने 1980 में महाराष्ट्र विधानसभा का पहला चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में भाजपा ने 145 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 14 ही जीत सकी थी। इसके बाद से भाजपा महाराष्ट्र के हर चुनाव में किस्मत आजमाती रही, लेकिन बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं कर सकी है। शिवसेना और एनसीपी के रूप में दो क्षेत्रीय दल भी उभरे, जिनमें शिवसेना ने भाजपा से दोस्ती बनाए रखी तो एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही। भाजपा ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 122 सीटें 2014 के चुनाव में जीती थीं और वो पहली बार सूबे में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन अपने दम पर राज्य में सरकार नहीं बना सकी। भाजपा को शिवसेना के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी थी। इससे पहले तक भाजपा महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ मिलकर चुनाव लड़ती रही है। शिवसेना बड़े भाई तो भाजपा छोटे भाई की भूमिका में थी।

गठबंधन की राजनीति का दौर

80 के दशक में जब कोई भी पार्टी भाजपा से हाथ मिलाने में कतराती थी। देश में गठबंधन की राजनीति का दौर भी शुरू नहीं हुआ था, तब

चुनावों में बड़ा रोल निभा रहे मप्र के नेता

महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दोनों राज्यों में भाजपानीत एनडीए और कांग्रेसनीत इंडिया गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसे में दोनों राज्यों में भाजपा और कांग्रेस ने विभिन्न राज्यों के अपने-अपने नेताओं को चुनावी मोर्चे पर तैनात किया है। दोनों पार्टियों ने अपनी इसी रणनीति के तहत मप्र के नेताओं को भी दोनों राज्यों के चुनावी मोर्चे पर उतारा है। महाराष्ट्र में मप्र के नेताओं ने 40 से अधिक विधानसभा सीटों पर अपनी-अपनी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने की जिम्मेदारी संभाली है। मप्र के नेताओं को सबसे बड़ी जिम्मेदारी अलायंस के सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाकर चुनावी मैदान में सक्रिय करना है। 288 विधानसभा सीटों वाले महाराष्ट्र और 81 सीटों वाले झारखंड में चुनाव जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने पूरा दम लगा रखा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने कांग्रेस नेतृत्व वाले गठबंधन के हौंसले बुलंद कर दिए हैं तो भाजपा के अगुवाई वाले गठबंधन के लिए चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में भाजपा ने महाराष्ट्र में अपने नेताओं की उसी टीम को लगाया है, जिसने मप्र की सियासी बाजी पलटकर सत्ता में बनाए रखने का रोल प्ले किया था। महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा ने जिलों की कमान भी चुनाव लड़ने और लड़ाने वाले अनुभवी नेताओं को सौंपी है। भाजपा भले ही किसी भी नेता को मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट न करे लेकिन पोस्टर बॉय के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का चेहरा होगा। महाराष्ट्र के चुनावी रण में भाजपा ने मप्र के अपने सियासी दिग्गजों को लगाया है। मप्र में वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को नागपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाजपा के ओबीसी चेहरे और मप्र सरकार में मंत्री प्रहलाद पटेल को यवतमाल वर्धा की जिम्मेदारी पर लगाया गया है। मप्र से पार्टी के एक अन्य नेता पूर्व उपमुख्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा को भंडारा-गोंदिया इलाके का प्रभार सौंपा गया है। मप्र के ये तीनों भाजपा नेता रणनीति बनाने के मामले में भी काफी अहम माने जाते हैं।

शिवसेना वह पार्टी थी, जिसने भाजपा के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन किया था। 1989 में भाजपा-शिवसेना के गठबंधन पर फाइनल मुहर लगी थी। इसमें प्रमोद महाजन का बड़ा योगदान था। करीब 3 दशक तक भाजपा-शिवसेना मिलकर महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ती रही है। शिवसेना को बड़े भाई की भूमिका मिली और मुख्यमंत्री का पद भी उसी पार्टी का मिला। शिवसेना महाराष्ट्र में भाजपा को छोटा भाई या पिछलग्गू ही समझती रही। महाराष्ट्र के 1990 में हुए विधानसभा चुनाव में शिवसेना 288 में से 183 सीटों पर लड़ी। छोटे सहयोगियों को शिवसेना ने अपने कोटे से सीट दी थीं। 1995 के चुनाव में यही फॉर्मूला कायम रहा था, जब भाजपा-शिवसेना सत्ता में आए थे। इस फॉर्मूले में थोड़ा बदलाव 1999 और 2004 के चुनाव में किया गया था। शिवसेना 171 और भाजपा 117 सीटों पर चुनाव लड़ी। इस नंबर में एक मामूली बदलाव 2009 के विधानसभा चुनाव में हुआ, जिसके बाद शिवसेना 169 और भाजपा 119 सीट पर लड़ी, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव नतीजे के बाद सियासी तस्वीर बदल गई।

भाजपा की राजनीति में नरेंद्र मोदी युग शुरू होने के बाद स्थितियां बदलने लगीं। नरेंद्र मोदी एक ऐसी राष्ट्रीय ताकत के तौर पर उभरे, जिन्होंने न सिर्फ भाजपा विरोधी दलों की जमीन अपने नाम की, बल्कि भाजपा के सहयोगियों की जमीन को भी सिकोड़ दिया। सियासी प्रवाह कुछ ऐसा हुआ कि भाजपा महाराष्ट्र की राजनीति में आत्मनिर्भर बनने की कवायद में शिवसेना से अलग हुई। 2014 में अलग-अलग दोनों पार्टियां चुनाव लड़ीं, लेकिन भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रह गई। इसके बाद भाजपा इस बात को समझ गई कि वो चाहकर भी महाराष्ट्र की राजनीति में आत्मनिर्भर नहीं बन सकती। भाजपा ने 2014 में फिर से शिवसेना के साथ हाथ मिला लिया और 2019 का चुनाव साथ लड़े, बहुमत भी मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद की लड़ाई ने दोनों ही दलों की दोस्ती में दरार डाल दी। शिवसेना ने भाजपा से गठबंधन तोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। लेकिन ढाई साल के बाद शिवसेना दो धड़ों में बंट गई और उसके बाद एनसीपी के दो टुकड़े हो गए। उद्धव ठाकरे का तख्तापलट करने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना और शरद पवार से एनसीपी छीनकर अपने हाथ में लेने वाले अजित पवार के साथ भाजपा ने गठबंधन कर रखा है तो कांग्रेस उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव में उतरी है। ऐसे में किसी एक दल के लिए बहुमत का नंबर जुटाना आसान नहीं है।

अकेले दम पर बहुमत नहीं

महाराष्ट्र की सियासत अलग-अलग छह क्षेत्रों में बटी हुई है, जहां के सियासी समीकरण भी अलग-अलग तरीके से हैं। विदर्भ में 62 सीटें, मराठवाड़ा में 46 सीटें, पश्चिमी महाराष्ट्र में 70 सीटें, मुंबई क्षेत्र में 36 सीटें ठाणे-कोंकण में 39 सीटें और उत्तरी महाराष्ट्र में 35 सीटें। प्रदेश में किसी कोई एक पार्टी का पूरे राज्य में सियासी प्रभावी नहीं है बल्कि अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग पार्टियों का प्रभाव है। इसीलिए पिछले 40 सालों में कोई भी पार्टी अकेले दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई है। महाराष्ट्र का वोटिंग पैटर्न देखें तो अलग-अलग पॉकेट में अलग-अलग तरीके से वोटिंग रही है। महाराष्ट्र में हर इलाका अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि जाति और सियासी समीकरण भी अलग-अलग हैं। विदर्भ में भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासत सिमटी हुई है तो पश्चिम महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में एनसीपी की अपनी ताकत रही है। कोंकण और मुंबई बेल्ट में शिवसेना और कांग्रेस के बीच फाइट होती रही है। उत्तर महाराष्ट्र में भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला होता रहा है। इसकी वजह से किसी एक पार्टी की सरकार अब तक नहीं बन पाई है। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले शरद पवार ने कई बार प्रयास के बावजूद 74 से ज्यादा सीटें जीत नहीं पाए थे। इसी तरह बालासाहेब ठाकरे जैसे नेता भी कभी अपने बलबूते पर सरकार बना नहीं पाए थे। भाजपा की भी यही रियलिटी है कि भाजपा ने भी कभी अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाई। इसलिए हमेशा गठबंधन की सरकारें बनती रही हैं। एक विशिष्ट स्थिति में अगर सरकार बनानी है तो गठबंधन की राह पर चलना होगा। इसीलिए कांग्रेस और भाजपा जैसे राष्ट्रीय दलों ने महाराष्ट्र में गठबंधन के सहारे सत्ता में आने का सपना देख रही है।

2024 के लोकसभा चुनाव नतीजों ने भाजपा के महाराष्ट्र की राजनीति में आत्मनिर्भर बनने की उम्मीदों पर बड़ा झटका दिया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने सूबे की 48 लोकसभा सीटों में से 30 सीटें जीतीं तो भाजपा के अगुवाई वाला एनडीए सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गया। लोकसभा के चुनावी नतीजों को विधानसभा क्षेत्रों के लिहाज से देखें तो इंडिया गठबंधन 153 सीटों (कांग्रेस 63, उद्धव की शिवसेना 57, पवार की एनसीपी 33 सीटें) तो भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को 126 सीटें (भाजपा 79, शिंदे की शिवसेना 40, अजित पवार की एनसीपी को पवार छह) पर आगे रही थी। भाजपा उत्तर महाराष्ट्र में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्रों (35 में से 20 सीटें) में बढ़त हासिल की थी तो कांग्रेस पार्टी विदर्भ और मराठवाड़ा में आगे रही, शिवसेना (यूबीटी) मुंबई में, शिवसेना (शिंदे) ठाणे-कोंकण में और एनसीपी (एसपी) पश्चिमी महाराष्ट्र में आगे रही। इंडिया गठबंधन ने ठाणे-कोंकण और उत्तरी महाराष्ट्र को छोड़कर सभी क्षेत्रों में बढ़त हासिल की थी। कांग्रेस विदर्भ में भाजपा को शिकस्त देने में सफल रही थी, जिसमें 62 में से 29 सीटों पर बढ़त मिली थी। मराठवाड़ा में आरक्षण की मांग पूरी न होने पर मराठाओं में गुस्सा था। इसके **परिणामस्वरूप** इंडिया गठबंधन 46 में से 32 सीटों पर आगे रही है। पश्चिमी महाराष्ट्र में शरद पवार ने अपना दबदबा कायम रखा था।

भाजपा-कांग्रेस के बीच मुकाबला

विदर्भ बेल्ट में इस बार भाजपा बनाम कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल सकता है। ऐतिहासिक रूप से कांग्रेस का गढ़ रहे विदर्भ में 1999 से 2009 तक भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। 2014 में नरेंद्र मोदी की लहर के दम पर भाजपा ने इस क्षेत्र में कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया था। 2024 के आम चुनावों में कांग्रेस अपना गढ़ बचाए रखने में कामयाब रही। मराठवाड़ा में कांग्रेस और सेना (यूबीटी) बनाम भाजपा और सेना (शिंदे) की लड़ाई देखने को मिल सकती है। ऐसे पश्चिमी महाराष्ट्र में भाजपा और एनसीपी (अजित पवार) बनाम कांग्रेस और एनसीपी (शरद पवार) की टक्कर देखने को मिल सकती है। ठाणे-कोंकण में भाजपा-शिवसेना (शिंदे) का कांग्रेस-शिवसेना (यूबीटी) के बीच मुकाबला देखने को मिल सकता है।

महाराष्ट्र में महायुति यानी शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोट को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती होगी। 2024 लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों में इंडिया गठबंधन को 30 और एनडीए को 17 सीटें मिलीं। इनमें भाजपा को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को सिर्फ 1 सीट मिली। भाजपा को 23 सीटों का नुकसान हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव से एनडीए को 41 सीटें मिली थीं। 2014 में यह आंकड़ा 42 था। यानी आधे से भी कम। 2024 लोकसभा चुनाव के हिसाब से भाजपा 60 सीटों के आसपास सिमट जाएगी। विपक्षी गठबंधन के एक सर्वे में राज्य की 288 सीटों पर एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी को 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। भाजपा के लिए मराठा आंदोलन सबसे बड़ी चुनौती है। इसके अलावा शिवसेना और एनसीपी में तोड़फोड़ के बाद उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ लोगों की सहानुभूति है।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में हार-जीत का मामला इतना आसान नहीं है, जितना अन्य राज्यों में होता है। यहां पर 2 या 3 पार्टियां नहीं हैं, कुल 6 पार्टियां हैं जो दो अलग-अलग गठबंधनों के माध्यम से आमने-सामने हैं। भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार) और कांग्रेस अपनी-अपनी दावेदारी के साथ मैदान में उतर चुकी हैं। कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) मिलकर महाविकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन मैदान में है तो दूसरी ओर भाजपा, शिवसेना और एनसीपी महायुति के बैनर तले भाग्य आजम रहे हैं। महायुति और एमवीए की आमने-सामने की टक्कर चल रही है। अभी कुछ दिनों पहले हुई लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र की जनता ने एमवीए को सिर-माथे पर चढ़ा लिया था। उसके हिसाब से एमवीए को विधानसभा चुनावों में बढ़त मिलनी चाहिए। पर जिस तरह हरियाणा में कांग्रेस के हाथ से बाजी फिसल गई थी, उसी तरह महाराष्ट्र में भी हो सकता है।

साइलेंट नाराजगी बदलेगी समीकरण

राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में कौनसी सीट पर बगावत और नाराजगी समीकरण बदल सकती है, नामांकन के बाद तस्वीर खुलकर सामने आ गई है। भाजपा ने शुरुआती तौर पर सलूंबर, झुंझुनू और रामगढ़ सीटों पर टिकट कटने से नाराज नेताओं को मना लिया है। खींवसर सीट पर भी समीकरण बिगाड़ने वाले नेता को अपने खेमे में ले लिया है। हालांकि कुछ जगहों पर नेताओं की साइलेंट नाराजगी बरकरार है। विपक्षी पार्टी कांग्रेस में डैमेज कंट्रोल उतना प्रभावी रूप से नहीं हो पाया है। देवली-उनियारा से बागी नरेश मीणा कांग्रेस के लिए चुनौती बन गए हैं। इसी सीट पर पूर्व केंद्रीय मंत्री नमोनारायण मीणा तो सलूंबर में रघुवीर मीणा की नाराजगी बरकरार है। कुछ सीटों पर तो नाराजगी टीस में बदल गई है। लोकसभा चुनाव में बना इंडिया गठबंधन राजस्थान में टूटने से भी कांग्रेस के भीतर नेताओं में खींचतान है। भाजपा में भी किसी नेता ने खुलकर नाराजगी नहीं दिखाई है, लेकिन जनरल सीट पर एसटी उम्मीदवार देने से भी एक वर्ग में दबी जुबान में नाराजगी जरूर है। हालांकि भाजपा का कोर वोटर इस पर अभी चुप है। भाजपा के पूर्व विधायक और पिछली बार के उम्मीदवार शंकरलाल शर्मा भी टिकट कटने से अंदरूनी तौर पर नाराज बताए जा रहे हैं। उनके समर्थकों के मन में टीस है। कांग्रेस में अशोक गहलोत और सचिन पायलट खेमों की अंदरूनी खींचतान भी इन उपचुनावों में इशारों में दिखनी शुरू हो गई है। गहलोत ने दौसा में नामांकन सभा के दौरान कांग्रेस सांसद मुरारीलाल मीणा और मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बीच मैच फिक्सिंग की चर्चाओं की बात गलत होने का बयान देकर इशारों में बहुत कुछ कह दिया।

किसी की दल को बहुमत नहीं

बिहार से काटकर झारखंड को अलग राज्य का दर्जा सन् 2000 में दिया गया। इस तरह 24 साल में 13 अलग-अलग सरकारें बन चुकी हैं और चार बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। राज्य में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 41 का है। झारखंड बनने के बाद सबसे पहला चुनाव साल 2005 में हुआ था, जिनमें भाजपा 30 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। हालांकि तब वह बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाई थी। इस चुनाव में जेएमएम 17 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही थी। साल 2009 में हुए विधानसभा चुनाव में भी किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और जेएमएम 18-18 सीटें जीतने में कामयाब रही थीं। कांग्रेस 14 और जेवीएम 11 सीटें जीती थीं। नतीजे सामने आए तो कोई भी दल 41 सीटों के जादुई आंकड़े को नहीं छू पाया। ऐसे में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। इसके बाद दिसंबर 2019 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, लेकिन भाजपा ने समर्थन वापस ले लिया तो सरकार गिर गई। इसके बाद भाजपा के अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बने, लेकिन वो भी सफल पारी नहीं खेल सके। फिर एक बार राष्ट्रपित शासन लग गया और बाद में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने और ड़ेढ साल सरकार चली।

2014 में झारखंड विधानसभा चुनाव हुए। राज्य की 81 सीटों में से भाजपा 37 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े से दूर रही। जेएमएम ने 17 सीटें जीतीं तो जेवीएम 8 और कांग्रेस 6 सीटें जीतने में कामयाब रही। इसके अलावा आजसू के पांच और अन्य दलों के छह विधायक जीतकर आए थे। इस तरह किसी भी दल को बहुमत का आंकड़ा इस चुनाव में भी नहीं मिला। भाजपा ने आजसू और अन्य दलों के विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाई और रघुवरदास मुख्यमंत्री बने। झारखंड के इतिहास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने पांच साल का कार्यकाल पूरा किया था। 2019 विधानसभा चुनाव में जेएमएम 30 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत का नंबर अपने दम पर नहीं पा सकी। भाजपा 25 सीटों पर सिमट

गई थी तो कांग्रेस को 16 सीटों से संतोष करना पड़ा था। जेवीएम के तीन और आजसू के दो विधायक जीतने में सफल रहे थे। इसके अलावा दो निर्दलीय विधायक, आरजेडी, माले और एनसीपी के एक-एक विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। कांग्रेस और जेएमएम ने मिलकर सरकार बनाई और अब फिर से एक बार चुनावी मैदान में उतरे हैं।

मुख्यमंत्री नहीं बचा पाता अपनी सीट

झारखंड के 24 साल के सियासत में जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, उन सभी को चुनावी मैदान में मात मिल चुकी है। बाबूलाल मरांडी से लेकर रघुवरदास तक सियासी रण में हार का स्वाद चख चुके हैं। ऐसे में मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ बेरहट सीट से भाजपा के गमालियेल हेमब्रम मैदान में है। ऐसे में देखना होगा कि हेमंत सोरेन रिकॉर्ड तोड़ेंगे या फिर मुख्यमंत्रियों की हार का इतिहास दोहराएंगे। झारखंड के गठन के साथ सन् 2000 में पहली बार भाजपा सरकार बनाने में कामयाब रही थी और बाबूलाल मरांडी राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे। मरांडी ने भाजपा से बगावत कर अलग झारखंड विकास पार्टी बना ली है। 2014 में गिरिडीह और धनवार सीट से बाबूलाल मरांडी मैदान में उतरे, लेकिन दोनों सीट से जीत नहीं सके। इस तरह भाजपा से तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे अर्जुन मुंडा को ही 2014 में खरसावां सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा था। अर्जुन मुंडा को झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी दशरथ गागराई ने 11 हजार 966 मतों से मात दी थी। इसी तरह 2005 में मधु कोड़ा निर्दलीय मैदान में उतरे और विधायक बनकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। 2014 चुनाव में मधु कोड़ा चाईबासा की मंझगांव विधानसभा सीट से जय भारत समानता पार्टी से मैदान में उतरे थे। कोड़ा को जेएमएम के नीरल पूर्ति ने 11710 मतों से मात दी थी।

झारखंड के दिग्गज नेता जेएमएम के अध्यक्ष शिबू सोरेन तीन बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मधु कोड़ा के हटने के बाद 2008 में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने, उस समय वह विधानसभा के सदस्य नहीं थे। ऐसे में 2009 में उन्होंने तमाड़ विधानसभा सीट से किस्मत आजमाई, लेकिन जीत नहीं सके। उपचुनाव में शिबू सोरेन झारखंड पार्टी के प्रत्याशी राजा पीटर से हार गए थे। हेमंत सोरेन 2013 में झारखंड के मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने 2014 चुनाव में दो सीटों- बरहेट और दुमका से चुनाव लड़ा था। इसमें बरहेट से वो जीत गए थे, लेकिन दुमका सीट पर हार गए थे। भाजपा की सत्ता में वापसी के साथ रघुवरदास मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में रघुवरदास अपनी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट से उतरे थे, लेकिन भाजपा के बागी सरयू राय ने निर्दलीय मैदान में उतरकर उन्हें मात दी थी। इस तरह रघुवरदास भी अपनी सीट नहीं बचा सके।

न किसी को बहुमत... न किसी की सत्ता रिपीट

झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सूबे की 81 सीटों पर दो चरणों में चुनाव होंगे। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए और जेएमएम के अगुवाई वाले गठबंधन के बीच मुख्य मुकाबला है। भाजपा सत्ता में वापसी के लिए बेताब है तो जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन अपने सियासी दबदबे को बनाए रखना चाहती है। ऐसे में देखना है कि झारखंड में चला आ रहा सियासी ट्रैक रिकॉर्ड क्या इस बार टूटता है या नहीं? झारखंड की राजनीति इतनी कॉम्प्लेक्स है कि इस राज्य के गठन को 24 साल हो गए हैं, लेकिन न ही किसी दल को बहुमत का आंकड़ा मिला है और न ही कोई भी सरकार रिपीट कर सकी है। इतना ही नहीं सत्ता के सिंहासन पर विराजमान रहने वाले मुख्यमंत्री को अपनी सीट बचाना मुश्किल हो जाता है। मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले नेताओं को हार का मुंह देखना पड़ा है। इसके अलावा झारखंड विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने वाले स्पीकर भी अपनी सीट नहीं बच सके हैं। ऐसे चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड के चलते हेमंत सोरेन और जेएमएम-कांग्रेस गठबंधन की टेंशन बढ़ी है।

चुनौती बनता लॉरेंस बिश्नोई

लॉरेंस बिश्नोई... यह एक ऐसा नाम है जिसे शायद ही कोई न जानता हो। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में यह नाम खूब सुर्खियों में छाया था। इसी की गैंग पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या का आरोप लगा था। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात की अहमदाबाद जेल में बंद है। लेकिन यहां रहने के बावजूद उसकी पूरी गैंग एक्टिव है। इसी साल 14 अप्रैल को बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान के घर पर भी इसी की गैंग ने फायरिंग करवाई। और अब एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में भी एक बार फिर लॉरेंस का नाम सामने आया है।

लॉरेंस का साम्राज्य 11 राज्यों और विदेश के छह देशों तक फैला हुआ है। आगे भी इसे और फैलाने का काम लॉरेंस के गुर्गे कर रहे हैं। लॉरेंस जेल में रहकर भी बेखौफ होकर अपनी गैंग को चला रहा है। इसके कुछ खास गुर्गे हैं, गोल्डी बराड़, काला जठेड़ी, रोहित गोदारा, सुरेंद्र सिंह उर्फ चीकू और भाई अनमोल बिश्नोई। यही वो लोग हैं जो इसके साम्राज्य का विस्तार देश-विदेश में कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात ये है कि अपना गुंडाराज चलाने के लिए ये उन लोगों को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो या तो गरीब घर से होता है या इनके नाम से खूब प्रभावित हुआ होता है। इनके ज्यादातर शूटर्स कम उम्र के होते हैं। 18 साल से लेकर 25 साल के युवाओं को ये सबसे ज्यादा टारगेट करते हैं। अगर सिद्धू मूसेवाला केस की बात करें तो उस केस में पुलिस ने 25 से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार हुए थे, जबकि 34 नामजद आरोपी थे। इनमें प्रियव्रत फौजी, अंकित, केशव, मनप्रीत मानू, जगरूप रूपा, कशिश, कपिल और दीपक मुंडी जैसे कई युवा लड़के शामिल थे। सभी आरोपी पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र के थे। वहीं, सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर विक्की गुप्ता (24) और सागर पाल (21) बिहार से ताल्लुक रखते हैं। दोनों शूटर बिहार के पश्चिमी चंपारण के नरकटिया तहसील के मसही गांव के रहने वाले हैं। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी धर्मराज कश्यप, शिवकुमार गौतम, जीशान अख्तर और गुरमेल सिंह हैं। ये उप्र, हरियाणा और पंजाब के हैं।

लॉरेंस गैंग सोशल मीडिया के जरिए शूटर्स को हायर करता है। ये कोई प्रोफेशनल शूटर नहीं होते हैं। इन लोगों को ज्यादा पैसों का लालच या विदेश भेजने के नाम पर अपनी गैंग में शामिल किया जाता है। कई युवा ऐसे भी होते हैं जिन्हें डरा धमका कर भी लॉरेंस के गुर्गे अपनी गैंग में शामिल कर लेते हैं, ताकि अपने खौफनाक मंसूबों को इनके जरिए अंजाम दे सकें। इसी तरह ये लोग अपना साम्राज्य फैलाते जा रहे हैं। देखा जाए तो इन शूटर्स का एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इनमें से अधिकतर युवा ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते और कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो लॉरेंस की गैंग में शामिल होकर उसके नाम का सहारा लेते हैं और बेखौफ होकर दबंगई दिखाते हैं। वहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने और विदेश जाने के चक्कर में इस तरह की गैंग में शामिल हो जाते हैं।

सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म पर लॉरेंस और इससे जुड़े गैंग के अहम सदस्यों के नाम से पेज, ग्रुप और प्रोफाइल बने हुए हैं। किसी भी पोस्ट पर लाइक व कमेंट करने वालों में से कुछ युवकों की पहचान कर गिरोह के लोग संपर्क करते हैं। फिर इनकी डिटेल लेकर गैंग में शामिल कर लिया जाता है। इसके साथ ही गैंग के अहम शूटरों की रिकमेंडेशन को भी तरजीह देकर बतौर शूटर शामिल कर लिया जाता है। जेल में किसी साथी बदमाश से मुलाकात के बाद शूटर उनकी रिकमेंडेशन गिरोह के लिए करते हैं। किसी वारदात से पहले शूटरों की लिस्ट तैयार की जाती है। फिर इन शूटरों को वारदात के लिए वाहन और रुपयों की मदद के लिए कोई संपर्क दिया जाता है। जिससे संपर्क कर ये हथियार और वाहन लेते हैं। इसके साथ ही वारदात के लिए विदेशी और ऑटोमेटिक पिस्टल भी इन तक पहुंचाई जाती है। पिस्टल सप्लाई करने वाले को तय समय और स्थान बताया जाता है। शूटर को भी उसी समय पर उस जगह भेजा जाता है। फिर वहां पर सप्लायर शूटर को हथियार और गोलियां सौंप देता है। शूटर को सख्त हिदायत दी जाती है कि वारदात के बाद ये हथियार किसे वापस पहुंचाना है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शूटर हैं और जय बलकारी उसकी गैंग का नारा है। इसमें 300 के करीब शूटर अकेले पंजाब से हैं। बाकी देश के अलग-अलग राज्यों से हैं।

लॉरेंस बिश्नोई पिछले 8 साल से जेल में बंद है। इस दौरान जैसे-जैसे उसकी जेल बदलती गई तो उसके जुर्म का रिकॉर्ड और गैंग भी बढ़ता गया। दो साल पहले 29 मई, 2022 को जब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का नाम सामने और और तभी उसकी राष्ट्रीय स्तर सबसे ज्यादा चर्चा भी हुई। जिस लॉरेंस के जुर्म के किस्से सिर्फ पंजाब में मशहूर थे, अब पूरे देश में उनकी चर्चा होने लगी है। सलमान खान पर हमला और फिर महाराष्ट्र के विधायक बाबा सिद्दीकी के मर्डर में नाम आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने हड़कंप मचा दिया है। जेल में रहकर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया तो लॉरेंस बिश्नोई के शूटर से लेकर सहयोगी तक हर कोई चर्चा में आ गया। इंग्लैंड और कनाडा से पुर्तगाल तक उसका नेटवर्क फैला हुआ है। वो एक इशारा करता है और बिश्नोई गैंग के 700 शूटर एक्टिव हो जाते हैं।

● **रजनीकांत पारे**

कई क्षेत्रिय गैंगेस्टर संभाल रहे कमान

लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस वक्त देश में पंजाब, उप्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान और झारखंड से लेकर अमेरिका, कनाडा, इंग्लैड और पुर्तगाल जैसे देशों तक फैल चुका है। गोल्डी बराड़, लखा और राजा उर्फ मोंटी लॉरेंस बिश्नोई के करीबी हैं और विदेशों में ये लोग गैंग की जिम्मेदारी संभालते हैं। कनाडा में गोल्डी बराड़, लेखप्रीत और सत्यवीर सन गैंग को चला रहे हैं और अमेरिका में गुरप्यार बागापुराना, अमनदीप मुल्तानी, वीरेंदर, अनमोल बिश्नोई और घरमान कहलोन जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। पुर्तगाल में लखा कुरुक्षेत्र, थाईलैंड में मनीष भंडारी और इंग्लैंड में गैंग को राजा उर्फ मोंटी संभाल रहा है। लॉरेंस बिश्नोई को और गैंग का भी साथ मिला हुआ है, जो उसके लिए काम करते हैं। इनमें दिल्ली का हाशिम बाबा गैंग, हरियाणा का काला जठेड़ी, गोगी गैंग और सुखविंदर ग्रुप शामिल हैं। राजस्थान का आनंदपाल गैंग, उप्र के बृजेश सिंह, धनंजय सिंह और बिहार के अनंत सिंह और राजन तिवारी भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का हिस्सा हैं। वहीं, पाकिस्तान के खालिस्तान समर्थक आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा के भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ लिंक सामने आ चुके हैं।

मोदी युग में भाजपा सशक्त

भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। इस उपलब्धि के पीछे पार्टी के करोड़ों देवतुल्य कार्यकर्ताओं की मेहनत है। कोई भी संगठन, संस्था अथवा राजनीतिक दल प्रगति के सर्वोच्च शिखर को तभी छू सकते हैं, जब उनके सामने लक्ष्य और दिशा सुस्पष्ट हो।

भाजपा पंचनिष्ठाओं पर आधारित पार्टी है। ये पंचनिष्ठाएं हैं- राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय अखंडता, लोकतंत्र, सर्वधर्म समभाव, गांधीवादी समाजवाद तथा मूल्य आधारित राजनीति। भाजपा के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है और वह सदैव राष्ट्रहित में काम करती है। भाजपा प्रत्येक देशवासी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। भाजपा का विरोध सिर्फ अलगाववादियों एवं आतंकवादियों से है। उन देशद्रोहियों और षड्यंत्रकारियों से है, जो राष्ट्रहित पर आघात करने के मंसूबे पालते है।

विश्व के अग्रणी नेता के रूप में प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पांच दशक के सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में हमने लोकप्रियता की इस ऊंचाई पर किसी नेता का आरोहण होते हुए नहीं देखा है। भाजपा के सदस्यता अभियान के प्रत्यक्ष अवलोकन से स्पष्ट है कि सदस्य संख्या के मान से भाजपा दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल की प्रतिष्ठा पहले ही अर्जित कर चुकी है। किसी संगठन और नेतृत्व का संकल्प जब जनता से जुड़ने, जन-जन से खुद को जोड़ने और अपने आचरण व कार्य व्यवहार से जनता के दिलों को जीत लेने का होता है तो कालांतर में उसका असर स्वयमेव दिखाई देता है। भाजपा ने अपनी नीतियों से संगठन के प्रति लोगों का भरोसा जगाया है। जनमानस में यह धारणा बनने लगी है कि भाजपा ही हमारी हितैषी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो अपना मंतव्य भी स्पष्ट कर रखा है- सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। समाज का कोई भी वर्ग इससे अछूता नहीं। किसी के साथ पक्षपात नहीं। किसी के साथ भेदभाव नहीं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा समाज के शोषित, वंचित, पीड़ित व सर्वहारा वर्ग के हितों में अनेक ऐतिहासिक एवं कल्याणकारी निर्णय लिए गए हैं। महिला सशक्तिकरण के साथ ही नौजवानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी के लिए उत्तम स्वास्थ, शिक्षा एवं सामाजिक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। विकसित भारत का सपना संजोए भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भाजपा के सदस्यता अभियान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। संगठन पर्व 2024 के द्वितीय चरण में पार्टी एवं नेतृत्व के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए देश में अब तक 9 करोड़ से अधिक जिसमें मप्र में लगभग डेढ़ करोड़ लोग भाजपा के सदस्य के रूप में पंजीकृत हुए। यह उल्लेखनीय उपलब्धि भाजपा के देवतुल्य सजग कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत की वजह से मिल पाई है। भाजपा के केंद्रीय नेताओं के मार्गदर्शन व मप्र के कर्मठ नेतृत्व में भाजपा अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए कटिबद्ध है।

इस मान्यता में कतई अतिशयोक्ति नहीं है कि नरेंद्र मोदी विश्व की पहली पंक्ति के नेताओं में शुमार हो चुके हैं। विश्वमंच पर उनकी बात ध्यान से सुनी जाती है। संकट-समाधान के लिए उनकी ओर आशा भरी नजरों से देखा जाता है। मोदी मूलत: संगठन के व्यक्ति हैं। वे बड़े गर्व से स्वयं को भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता कहते हैं। यही बड़प्पन उन्हें बड़ा नेता बनाता है। पिछले 23 वर्षों से वे सत्ता के सूत्र संचालन कर रहे हैं। वे 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और 10 वर्ष से भारत के सफल प्रधानमंत्री हैं। लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम में मिलती है। कालिदास जी कहते हैं- अविश्रामोऽयं लोकतंत्राधिकार:। अर्थात् लोकतंत्र के अधिकार में विश्राम नहीं। नरेंद्र मोदी ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो केवल घोषणा करने और निर्णय लेने तक सीमित नहीं रहते बल्कि कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण की मॉनीटरिंग और समीक्षा करते हैं। कमियों को दुरुस्त करवाते हैं। अच्छे काम करने वालों की हौसला अफजाई करते हैं। देश के किस राज्य के किस कोने में क्या नवाचार किया जा रहा है, उसकी समाज के लिए क्या उपादेयता है, इन सबको परखते हुए अपने अनूठे और अभूतपूर्व लोक संवाद मन की बात में उसको रेखांकित करते हैं। मोदीजी ने 10 साल से चल रहे मन की बात कार्यक्रम में हजारों देशवासियों को बेहतर करने की प्रेरणा दी है। भाजपा के असंख्य कार्यकर्ता अपने यशस्वी जननेता से प्रेरणा लेकर दोगुने उत्साह के साथ काम करते हैं।

नरेंद्र मोदी जीवन के संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। उन्होंने जब राष्ट्र की बागडोर संभाली, तब गरीब, किसान, नौजवान तथा महिलाएं उनकी प्राथमिकता के केंद्र बिंदु बने। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए निशुल्क खाद्यान्न, किसानों के लिए सम्मान निधि, गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान चिकित्सा योजना इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। प्रधानमंत्री हमेशा नए भारत की बात करते हैं।

भाजपा का भ्रम

अगर इस समय सहयोगी दलों या इंडिया ब्लॉक से कोई खतरा नहीं है, तो मोदी सरकार के यू-टर्न की क्या वजह है? इसका कारण यह है कि पार्टी को अभी भी पूरा पता नहीं है कि पिछले लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान क्यों हुआ। आम धारणा यह है कि 400 पार के नारे की वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के बारे में भाजपा के इरादे पर संदेह करने लगे। हालांकि, हर कोई इस बात से सहमत नहीं है। जैसा कि कई भाजपा नेताओं ने बताया है, प्रधानमंत्री मोदी खुद अभी भी पार्टी के सहयोगियों से पूछ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या गलत हुआ। जाहिर है, कोई भी उनकी लोकप्रियता के ग्राफ के बारे में बात नहीं करेगा, लेकिन कई लोगों ने 400 पार के नारे पर सवाल उठाए हैं।

विश्वसनीयता का संकट

चाहे जो भी हो, शासन में यू-टर्न भाजपा में एक बड़े संकट की ओर इशारा करते हैं- विश्वसनीयता का संकट। पार्टी के तीन मुख्य एजेंडे में से दो: अयोध्या राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद-370 को निरस्त करना, पूरे हो चुके हैं। तीसरा, समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करना, बहुत ज्यादा गति नहीं पकड़ रहा है। पहले दो के कार्यान्वयन से भी कोई चुनावी लाभ नहीं हुआ। ये तीन मुद्दे भाजपा की राजनीति का मूल आधार थे। अब जब ये मुद्दे चुनावी तौर पर उत्पादक नहीं रह गए हैं, तो भाजपा संघर्ष कर रही है। मोदी लहर के कम होते ही, पार्टी और भी ज्यादा भ्रमित नजर आ रही है। शासन में ये यू-टर्न यही दर्शाते हैं। जैसा कि भाजपा के एक नेता ने कहा, राहुल गांधी जॉन बनियन की याद दिलाते हैं, जो नीचे है उसे गिरने से डरने की जरूरत नहीं है। वे जाति जनगणना, अडाणी, अंबानी और न जाने क्या-क्या बोल सकते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है।

नया भारत कुछ वर्षों के बाद विकसित भारत बनकर दुनिया का सिरमौर बने, इसके लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना उनकी प्राथमिकता रही है। शिक्षा के क्षेत्र में तो अभूतपूर्व क्रांति हुई है। नई शिक्षा नीति ज्ञान को भारतीयता से जोड़ने की सार्थक पहल है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सर्वांगीण विकास के लिए जो सपना संजो रखा है, उसे पूरा करने के लिए उनके नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है। निसंदेह, मोदीजी का हर पल, हर क्षण राष्ट्र के लिए समर्पित है और वे इसी संकल्प के साथ विश्व में देश का मान बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को मंजूरी दिए जाने पर विपक्ष की ओर से अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि यूपीएस में नरेंद्र मोदी सरकार के यू-टर्न का प्रतीक है, जबकि आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे एनपीएस से भी बदतर बताया। सरकार के स्पिन डॉक्टर पेंशन सुधारों पर पीछे हटने की बात का खंडन करते रहे हैं। उनका तर्क था कि पुरानी पेंशन योजना के विपरीत यूपीएस अंशदायी निधि है। यह तथ्य कि यूपीएस सरकारी खजाने पर अतिरिक्त बोझ डालेगा कि ज्यादा चर्चा करने की जरूरत ही नहीं समझी गई। हालांकि, यह सभी को मालूम है कि सरकार ने इस साल चार राज्यों (जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड) के चुनावों से पहले कर्मचारियों को खुश करने के लिए एनपीएस पर यू-टर्न लिया।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के मद्देनजर पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए समिति का गठन किया गया था। कहा जाता है कि हार में योगदान देने वाले कारकों में से एक कांग्रेस का पुरानी पेंशन प्रणाली को बहाल करने का वादा था। उसके बाद छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों ने ओपीएस लागू किया था, जिससे उसे बाद के विधानसभा चुनावों में सत्ता बरकरार रखने में मदद नहीं मिली। अब भाजपा पेंशन सुधारों को वापस लेकर यूपीएस लाने में ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही है।

मोदी 3.0 में एनपीएस पर यू-टर्न पहली बार नहीं हुआ है। न ही विपक्ष के दबाव के अंदर सरकार के झुकने की यह पहली मिसाल है। राहुल गांधी की छाप तब भी दिखी जब केंद्र ने नौकरशाही में लेटरल एंट्री पर पीछे हटना शुरू किया। इन घटनाक्रमों ने राजनीतिक हलकों में एक मजाक शुरू कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सरकार कोई नीति बदले या कोई नई नीति अपनाए, तो ऐसा करने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति राहुल गांधी हैं। भाजपा के सहयोगी दल भी कुछ बदलावों का श्रेय ले सकते हैं। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान और जनता दल (यूनाइटेड) के नेता केसी त्यागी ने लेटरल एंट्री नीति पर गांधी के हमले का समर्थन किया था। वक्फ विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की विपक्ष की मांग को तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के समर्थन के कारण सरकार को इस पर सहमत होना पड़ा। इसका श्रेय गांधी को दिया जाए या भाजपा के सहयोगियों को, सच्चाई यह है कि मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद से 11 हफ्तों में यू-टर्न देखने को मिले हैं। क्या यह गठबंधन की मजबूरी है या विपक्ष के सामने घुटने टेकने वाली प्रतिक्रिया? क्या फर्क पड़ता है अगर सरकार गठबंधन सहयोगियों की परवाह किए बिना नीतिगत निर्णय ले? क्या कोई सहयोगी सरकार को इस समय गिराने की कोशिश करेगा? नीतीश कुमार ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि केवल भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाए रख सकती है (यही एकमात्र चीज है जिसकी उन्हें परवाह है)।

चंद्रबाबू नायडू भी ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करना है और अपने बेटे लोकेश को उत्तराधिकारी बनाने के लिए ठोस मंच देना है, इससे पहले कि टीडीपी के प्रमुख नई दिल्ली में किंगमेकर बनने के बारे में सोचें। ऐसा चिराग पासवान भी नहीं करेंगे, जो अपने दिवंगत पिता रामविलास पासवान के योग्य उत्तराधिकारी साबित हुए हैं। बिहार में दलितों के बीच अपना आधार मजबूत करने के लिए चिराग मोदी की लोकप्रियता उनके हनुमान बनकर भुना रहे हैं। वे इतने व्यावहारिक राजनेता हैं कि एक मुद्दे को अपने राम, नरेंद्र मोदी के साथ अपने समीकरणों को खतरे में डालने नहीं देंगे। एनडीए में भाजपा के अन्य सहयोगी, जैसे कि शिवसेना के एकनाथ शिंदे या अपना दल की अनुप्रिया पटेल, अगर भाजपा से अलग होने के बारे में सोचते हैं, तो उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा।

कल्पना करते हैं कि अगर सबसे बुरा हो जाए और इनमें से कुछ सहयोगी लोकसभा में सरकार को अल्पमत में ला दें, तो वैकल्पिक सरकार कौन बनाएगा? संसद में इंडिया ब्लॉक भले ही मजबूत दिख रहा हो, लेकिन बाहर वे बंटे हुए हैं। देखिए कि कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले ने इस साझेदारी में कैसे दरारें उजागर की हैं, जिसमें गांधी ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोपी को बचाने के प्रयास के लिए हमला किया है। हालांकि, गांधी इंडिया ब्लॉक में अलग-थलग दिखे, क्योंकि अन्य भागीदारों ने संयमित रुख अपनाया और बनर्जी से सवाल करने से परहेज किया। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भाजपा पर मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया।

● **विपिन कंधारी**

देश में चुनावी माहौल है, ऐसे में सभी पार्टियां कमर कसती हुई नजर आ रही हैं, जहां अगले महीने महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहीं उत्तर-प्रदेश और राजस्थान में उपचुनाव होने वाले हैं। सभी चुनावों के लिए तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। इन चुनावों में कांग्रेस सबसे कमजोर नजर आ रही हैं, क्योंकि गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों का नुकसान कांग्रेस ही झेल रही है!

गठबंधन की आस में कांग्रेस लाचार

इंडिया गठबंधन में शामिल छत्रप कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा सीटें देते नहीं दिख रहे हैं। यही वजह है कि कांग्रेस को उप्र, महाराष्ट्र और झारखंड में जहर का घूंट पीकर सीटों पर समझौता करना पड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी की दो दिनों तक चली मैराथन बैठकों के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच पहले ही सीट बंटवारा फाइनल हो चुका है। इस तरह से सीट शेयरिंग में महाराष्ट्र से लेकर उप्र और झारखंड तक में सबसे बड़ा झटका कांग्रेस को लगा है।

कांग्रेस अपने सियासी इतिहास में अभी तक सबसे कम सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को गठबंधन के चलते समझौता करना पड़ा था और फिर से विधानसभा चुनाव में भी छत्रपों के आगे कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया है। नरेंद्र मोदी के केंद्रीय राजनीति में दस्तक देने के साथ ही कांग्रेस पूरी तरह से कमजोर हो गई है। कांग्रेस के हाथों से देश की ही सत्ता नहीं बल्कि राज्यों की सत्ता भी बाहर होती जा रही है। हरियाणा चुनाव की जीती बाजी, जिस तरह कांग्रेस हारी है, उसके चलते इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों ने उस पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए थे। इसी का नतीजा है कि कांग्रेस को महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और उप्र तक में समझौता करना पड़ा है।

उप्र में पांच सीटों पर उपचुनाव लड़ने की उम्मीद में बैठी कांग्रेस खाली हाथ रह गई है। महाराष्ट्र में कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच बराबर-बराबर सीटों पर चुनाव लड़ने की सहमति बनी है। कांग्रेस महाराष्ट्र में 100 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी है जबकि झारखंड में पिछले विधानसभा चुनाव से कम सीटों पर उसे लड़ना पड़ा। झारखंड और महाराष्ट्र में कांग्रेस इतनी कम सीटों पर कभी चुनाव नहीं लड़ी है। सवाल उठता है कि गठबंधन की सियासी मजबूरी में कांग्रेस किस स्थिति में आज खड़ी नजर आ रही।

उत्तर प्रदेश की दस विधानसभा सीटें खाली हुई हैं, जिसमें 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस ने पांच सीटों पर उपचुनाव लड़ने का प्रस्ताव बनाया था, जहां पर भाजपा, आरएलडी और निषाद पार्टी का कब्जा था। सपा की तरफ से कांग्रेस को सिर्फ गाजियाबाद और खैर दो सीट मिल रही थी। यह दोनों ही सीटें कांग्रेस अपने लिए कम्फर्ट नहीं मान रही है, क्योंकि खैर सीट पर 44 साल से तो गाजियाबाद सीट पर 22 साल से जीत नहीं मिली। सपा के लिहाज से भी ये दोनों सीटें कभी बेहतर नहीं रहीं। ऐसे में कांग्रेस ने खैर और गाजियाबाद सीट पर चुनाव लड़ने से अपने कदम पीछे खींच लिए और सपा सभी 9 सीट पर चुनाव लड़ेगी।

कांग्रेस और भाजपा की साख दांव पर लगी

राजस्थान उपचुनाव की जिन सात सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें चार सीटें कांग्रेस कोटे से खाली हुई हैं। भाजपा, बीएपी और आरएलपी कोटे से एक-एक विधानसभा सीट खाली हुई है। इस तरह सबसे ज्यादा साख कांग्रेस की दांव पर लगी है तो भाजपा के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने अपने कोटे की खाली चार विधानसभा सीटों को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है तो सत्ता पर काबिज भाजपा क्या अपना दम दिखा पाएगी? झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है तो भाजपा ने राजेंद्र भांबू पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अपने कब्जे वाली झुंझुनू सीट को बचाए रखने के लिए गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और झुंझुनू से मौजूदा सांसद बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला पर दांव खेला है। 2023 चुनाव में यह सीट बृजेंद्र ओला ने जीती थी।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल निशान पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और सपा एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है। इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में, जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से सपा की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस तरह कांग्रेस उपचुनाव में एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है।

महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग में कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। सूबे की कुल 288 सीटों में से 255 सीटों पर इंडिया गठबंधन के बीच सीट-बंटवारे का समझौता किया है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के बीच 85-85 सीटों पर चुनाव लड़ने का फॉर्मूला बना है, लेकिन 33 सीटों पर कोई फैसला नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने कहा कि हम गठबंधन के रूप में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हमने अब तक 270 सीटों पर बात कर ली हैं और 85-85-85 सीटों के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। हम आगे अपने अन्य सहयोगियों से बात करेंगे जब बाकी सीटें भी साफ हो जाएंगी।

लोकसभा चुनाव नतीजों से उत्साहित कांग्रेस इंडिया गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाना चाहती थी, लेकिन उद्धव और शरद पवार के सियासी दांव से सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हालांकि, कांग्रेस ने 105 से 110 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था, लेकिन 100 सीट का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकी। 2009 में कांग्रेस 170 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 2014 में 287 सीटों पर किस्मत को आजमाया था। 2019 में कांग्रेस 147 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। इस तरह से कांग्रेस अपने सियासी इतिहास में सबसे कम सीटों पर इस बार महाराष्ट्र चुनाव में किस्मत आजमाएगी।

झारखंड विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पिछली बार से कम सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ रहा है। कांग्रेस साल 2019 में 31 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन इस बार कांग्रेस को 30 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पिछले चुनाव की तुलना में एक सीट पर कम चुनाव लड़ रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन में जेएमएम बड़े भाई की भूमिका में है तो कांग्रेस छोटे भाई के रोल में है। झारखंड की कुल 81 विधानसभा सीटों में से जेएमएम 41, कांग्रेस 30, आरजेडी 6 सीट और माले 4 सीट पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस झारखंड में इतनी कम सीट पर कभी चुनाव नहीं लड़ी है।

अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बात सीट की नहीं जीत की है। इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सपा को अभूतपूर्व सहयोग दिया है। वो लिखते हैं, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन का एक-एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नई ऊर्जा से भर गया है। राजनीति का एक रंग ये भी है। जमकर कूटो और रोने भी न दो। कांग्रेस ने तो पांच सीटों पर दावेदारी करके जताया था कि वो सपा का छोटा नहीं बल्कि बराबर का साझेदार है, लेकिन सपा ने कहा- छोटे ही हो, बराबरी की सोची तो निकल लो। अखिलेश ने कांग्रेस के बूथ लेवल कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक के सहयोग की दावेदारी की ऐसी चाल चली कि कांग्रेस करे तो क्या? वो मुंह खोलती है तो उस गठबंधन में दरार का संदेश जाएगा जिसने लोकसभा चुनाव में उप्र में परचम लहरा दिया। बस चार-साढ़े चार महीने ही तो हुए इस बात के, जब सपा-कांग्रेस ने मिलकर उप्र 80 में से 43 लोकसभा सीटें जीत लीं और भाजपा को छोटा कर दिया। लेकिन इसी दौरान एक और बात हो गई, हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार। बस इसी हार ने गठबंधन में कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर दी। हरियाणा में कांग्रेस जीत गई होती तो सपा उप्र में उसकी जबरदस्त धुनाई करके रोने का रास्ता भी नहीं छोड़ने जैसी बड़ी हिमाकत नहीं कर पाती।

उप्र उपचुनाव में सपा की तरफ से कांग्रेस को ठेंगा दिखाने के पीछे एक और कारक भी काम कर रहा है। लोकसभा चुनाव में सपा ने 63 जबकि कांग्रेस ने 17 सीटों पर साझेदारी में चुनाव लड़ा था। सपा ने 63 में से 37 सीटें जीतकर 59 प्रतिशत का स्ट्राइक रेट हासिल कर लिया, जबकि कांग्रेस 17 में सिर्फ 6 सीटें जीतकर स्ट्राइक रेट में सपा से बहुत दूर रह गई। कांग्रेस पार्टी का स्ट्राइक रेट सिर्फ 35 रहा। अब उपचुनाव की बारी आई तो सपा ने कांग्रेस को पांच की मांग पर सिर्फ दो सीटों का ऑफर रखा। वो भी ऐसी सीटें जहां का ट्रैक रिकॉर्ड ही कहता है कि कांग्रेस की हार लगभग तय होगी। ये सीटें हैं- गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट। कांग्रेस ने चुनावी मैदान में विरोधियों के हाथ पिटने की जगह साथी के हाथों पछाड़े जाने का विकल्प चुना और उपचुनाव से कदम वापस खींच लिए। जिस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नाम लिए बिना कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की आड़ लेकर राहुल गांधी की दरियादिली की प्रशंसा की है, ठीक वही मौका राहुल के पास महाराष्ट्र में है। राहुल भी महाराष्ट्र में अखिलेश को जमीन सुंघाकर उनकी ही दरियादिली का गुणगान कर सकते हैं।

● इन्द्र कुमार

हरियाणा नहीं हारती कांग्रेस तो भी यही होता?

लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन सुधारकर राहुल गांधी ने जो भी सपने देखे थे, हरियाणा की हार ने उन सब पर पलीता लगा दिया। उप्र में अखिलेश ने राहुल का हाथ जिस ताकत से झटका है, उसका अंदाजा तो राहुल को हो गया होगा। उधर, झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने कांग्रेस को बराबर का साझेदार मानने से इनकार कर दिया है। 81 सीटों वाली विधानसभा में जेएमएम ने अपने पास 40 जबकि कांग्रेस को 30 सीटें दी हैं। सवाल है कि क्या हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जीत जाती तो भी सीट शेयरिंग का यही फॉर्मूला रहता?

घर वापस आईए...!

दंतेवाड़ा जिले में चलाए जा रहे लोन वर्राटू (घर वापस आईए) अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। 2 ईनामी माओवादियों सहित कुल 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2-2 लाख रुपए के ईनामी थे और दरभा डिवीजन के मलांगेर एरिया कमेटी में सक्रिय थे। आत्मसमर्पण करने वालों में पहला नंदू माड़वी है जो पिछले 6-7 सालों से माओवादी संगठन के प्लाटून नंबर 24 में सक्रिय था। इसके अलावा हिड़मा माड़वी भी शामिल हैं, जो एक साल से प्लाटून नंबर 24 का सदस्य था। हिड़मा माड़वी को डीवीसी सचिव जगदीश का गार्ड भी नियुक्त किया गया था। छत्तीसगढ़ सरकार ने दोनों माओवादियों पर 2-2 लाख रुपए का ईनाम भी जारी किया हुआ था। इसके अलावा तीसरा माओवादी हेमला (29) ने भी पुलिस के आगे सरेंडर किया है।

जानकारी के मुताबिक, लोन वर्राटू अभियान के तहत अब तक 204 ईनामी माओवादी सहित कुल 880 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ये अभियान छत्तीसगढ़ शासन और पुलिस प्रशासन की अहम रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद माओवादियों को हिंसा छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए प्रेरित करना है। आत्मसमर्पित माओवादियों को छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल पुनर्वास नीति के तहत 25-25 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। इसके साथ ही उन्हें छत्तीसगढ़ शासन की अन्य पुनर्वास सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी जिससे कि वे सामान्य जीवन जीने के लिए जरूरी संसाधनों से वंचित न रहें। भले ही थोड़े-थोड़े समय पर छत्तीसगढ़ में माओवादी सक्रिय हो उठते हैं और सुरक्षाबलों को चुनौती देते रहते हैं, लेकिन इस वर्ष शुरुआत से ही उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाने लगी। सरकारी योजनाएं ये थीं कि पहले ही सख्त कार्रवाई के जरिए माओवादियों का मनोबल तोड़ दिया जाए। पिछले छह महीने में दो बड़े माओवादी विरोधी ऑपरेशन किए गए। पहला अप्रैल के महीने में कांकेर में और दूसरा 4 अक्टूबर को दंतेवाड़ा-नारायणपुर जिले के बॉर्डर पर हुआ। इस ऑपरेशन को अब तक का सबसे बड़ा नक्सल विरोधी अभियान बताया जा रहा है। इस ऑपरेशन में 30 से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में कांकेर में हुई मुठभेड़ में 29 नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया गया था।

पुलिस के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिलों की सीमा पर अबूझमाड़ क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली। वहां 4 अक्टूबर को सुरक्षाबलों की संयुक्त पार्टी पहुंचा दी गई। कथित जानकारी के मुताबिक दोनों जिलों से लगभग 1000 जवान इस संयुक्त दल में शामिल थे। संयुक्त दल के जवानों ने थुलथुली इलाके में अपना मोर्चा संभाल लिया। इसी दौरान माओवादियों की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। सुरक्षाबल के जवानों ने जवाबी फायरिंग की। पुलिस के मुताबिक, काफी समय तक माओवादियों और सुरक्षाबलों के बीच गोलीबारी का दौर चलता रहा। दंतेवाड़ा के एसपी गौरव राय ने बताया कि अबूझमाड़ के जंगलों में दंतेवाड़ा से डीआरजी, बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ के 500 जवानों ने ऑपरेशन चलाया और पहले राउंड की मुठभेड़ में ही सात माओवादी मारे गए। दावा किया गया कि इस मुठभेड़ में 36 से ज्यादा माओवादी मारे गए। बस्तर के आईजी सुंदरराज पी. के मुताबिक 28 शव बरामद किए गए हैं जबकि तीन-चार शव और बरामद होने की संभावना है। अधिकारियों का कहना है कि मुठभेड़ दोपहर एक बजे से चार बजे तक चली। मुठभेड़ के बाद एके-47 सहित कई ऑटोमैटिक हथियारों के अलावा बड़ी मात्रा में गोला-बारूद भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा जा है कि इस ऑपरेशन में माओवादियों के सबसे सुरक्षित ठिकानों को सुरक्षाबलों ने ध्वस्त कर दिया। इसे अब तक की सबसे बड़ी सफलता बताया गया। यह पहला मौका है जब पुलिसिया दावे के मुताबिक इतनी बड़ी संख्या में माओवादी मारे गए हैं। इससे पहले कांकेर में एक मुठभेड़ में 29 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया गया था, लेकिन एक मुठभेड़ में 36 से ज्यादा कथित माओवादियों को मारे जाने का यह पहला मामला है। इसके पहले 2016 में पड़ोसी राज्य ओडिशा के मलकानगिरी स्थित रामागुड़ा के जंगलों में स्पेशल फोर्स के ऑपरेशन में 34 माओवादियों के मारे जाने का दावा किया गया था। सुरक्षाबल उसे सबसे बड़ी मुठभेड़ मानते रहे हैं। बताया जा रहा कि इस मानसून में 235 नक्सली मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। मुठभेड़ के बाद देर रात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक की। उसमें पुलिस महानिदेशक और मुख्यमंत्री सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ कोई ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ को माओवाद से मुक्त करने के लिए दृढ़ संकल्प है।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

गांव-गांव में पुनर्वास नीति का प्रचार

पुलिस प्रशासन ने बताया कि शासन की नक्सल पुनर्वास नीति का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। गांव-गांव में नक्सलवाद के खिलाफ जागरूकता फैलाने के साथ ही पुनर्वास की संभावनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है जिसके प्रभाव से शीर्ष माओवादियों से लेकर भटके हुए युवा माओवादी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि माओवादी संगठन में शामिल हुए युवा अब अमानवीय और आधारहीन विचारधारा, आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों और शोषण से तंग आ चुके हैं। इन आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने अब समाज की मुख्यधारा में शामिल होने और एक सामान्य जीवन जीने का संकल्प लिया है। लोन वर्राटू अभियान और नक्सल पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों के लिए यह एक नई शुरुआत है। छत्तीसगढ़ सरकार और पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटें और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।

पार्टियों में बंटा परिवार

महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों अपने पूरे सियासी उफान पर है। सूबे की सत्ता पर काबिज होने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए (महायुति) और कांग्रेस के अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन (महा विकास अघाड़ी) के बीच शह-मात का खेल जारी है। टिकट न मिलने पर कोई बागी हो रहा है, कोई आंसू बहा रहा है, तो कोई सियासी ठिकाना तलाश रहा है। चुनाव लड़ने और विधायक बनने की चाह में परिवार भी सियासी दलों के बीच बंट गए हैं। ऐसे में बाप-बेटा और भाई-भाई अलग-अलग पार्टियों में अपनी राजनीति चमका रहे हैं।

महाराष्ट्र में पवार और ठाकरे परिवार ही दो सियासी धड़ों में नहीं बंटा, बल्कि राणे परिवार से लेकर नाईक कुनबे तक में यही स्थिति दिख रही है। शरद पवार और अजित पवार एक-दूसरे के खिलाफ चुनावी आजमाइश के साथ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की अग्निपरीक्षा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राणे भाजपा से सांसद हैं, तो उनके बेटे नीलेश राणे ने एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने का फैसला किया है। गणेश नाईक भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके बेटे संदीप नाईक ने शरद पवार की एनसीपी (एस) का दामन थाम रखा है। इसी तरह छगन भुजबल और उनके भतीजे अलग-अलग दल से चुनावी पिच पर उतरेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद नारायण राणे भाजपा के टिकट पर सिंधुदुर्ग से लोकसभा सांसद चुने गए हैं। नारायण राणे के छोटे बेटे नीतेश राणे सिंधुदुर्ग कणकवली सीट से विधायक हैं और एक बार फिर से भाजपा के टिकट पर इसी सीट से चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे राजनीतिक पाला बदलने जा रहे हैं। नारायण राणे भाजपा सांसद हैं, तो उनके एक बेटे नीतेश राणे भाजपा विधायक हैं। इस तरह से नारायण राणे और नीतेश भाजपा में, तो नीलेश राणे टिकट की चाह में शिंदे की शिवसेना का दामन थामने जा रहे हैं।

नारायण राणे के बड़े बेटे नीलेश राणे भी चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं, जिसके लिए कणकवली के ही बगल की सीट कुडाल सीट का सिलेक्शन किया है। कुडाल सीट भाजपा के बजाय एकनाथ शिंदे की शिवसेना के कोटे में है। इसीलिए नीलेश राणे ने भाजपा के बजाय शिवसेना से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। माना जा रहा है कि सिंधुदुर्ग में राणे परिवार के सियासी वर्चस्व को देखते हुए एकनाथ शिंदे उन्हें चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। नीलेश राणे का मुकाबला उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) के वैभव नाईक से होगा। नवी मुंबई की सियासत में नाईक परिवार की तूती बोलती है। भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री गणेश के बेटे संदीप नाईक की राजनीतिक राह एक-दूसरे से अलग हो गई है। भाजपा ने गणेश नाईक को ऐरोली विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है, लेकिन उनके बेटे संदीप नाईक ने विधायक बनने की चाह में भाजपा को अलविदा कहकर शरद पवार की एनसीपी का दामन थाम लिया है। संदीप नाईक बेलापुर से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन टिकट नहीं मिला तो राजनीतिक पाला बदल लिया है।

बेलापुर सीट पर मौजूदा भाजपा विधायक मंदा म्हात्रे हैं, जिन्हें पार्टी ने एक बार फिर से मौका दिया है। शरद पवार ने अपनी पार्टी से संदीप नाईक को मैदान में उतार दिया है। गणेश नाईक 2019 तक एनसीपी में थे और चुनाव के दौरान भाजपा में शामिल हो गए थे, लेकिन अब पिता भाजपा में, तो बेटे शरद पवार की पार्टी में शामिल हो गए हैं। इस तरह से नाईक परिवार दो धड़ों में बंट गया है। अब सवाल उठता है कि क्या भाजपा गणेश नाईक के खिलाफ कार्रवाई करेगी क्योंकि शिंदे की शिवसेना ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है। भाजपा के दिग्गज नेता धनंजय महादिक का परिवार भी दो दलों के बीच बंटने के कगार पर खड़ा है। धनंजय महादिक भाजपा से राज्यसभा सांसद हैं। महादिक के बड़े बेटे कृष्णराज महादिक कोल्हापुर उत्तर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में यह सीट शिंदे की शिवसेना के कोटे में चली गई है। धनंजय महादिक ने अपने बेटे के लिए देवेंद्र फडणवीस और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की है। शिंदे की पार्टी से राजेश क्षीरसागर कोल्हापुर उत्तर सीट से चुनाव लड़ने की रेस में हैं। शिंदे कोल्हापुर की सीट को नहीं छोड़ते हैं, तो धनंजय के बेटे कृष्णराज पाला बदलकर शिवसेना का दामन थाम सकते हैं।

महाराष्ट्र के दिग्गज ओबीसी नेता छगन भुजबल का परिवार भी बिखराव के द्वार पर खड़ा है। छगन भुजबल उपमुख्यमंत्री अजित पवार के करीबी माने जाते हैं। अजित पवार के साथ छगन भुजबल ने शरद पवार का साथ छोड़ दिया था। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल नासिक जिले के नंदगांव विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन नंदगांव सीट से मौजूदा विधायक सुहास कांदे शिंदे गुट में हैं। यह सीट शिंदे गुट की शिवसेना को मिली है, जिसके चलते अब वो सियासी पाला बदलने के मूड में है। एनसीपी (एस) के भी संपर्क में है, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ भी अपना विकल्प तलाश रहे हैं। नंदगांव विधानसभा सीट महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास है, इसलिए अगर शरद पवार गुट को यह सीट नहीं मिली तो फिर समीर भुजबल ठाकरे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं।

● **बिन्दु माथुर**

क्या वर्ली सीट पर आदित्य की राह होगी आसान?

महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार से एक और सदस्य की चुनाव पिच पर उतरने की तैयारी है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पिछले विधानसभा चुनाव में मुंबई की वर्ली सीट से सियासी डेब्यू किया था तो इस बार मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से मैदान में उतरने जा रहे हैं। अमित ठाकरे माहिम से चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें उद्धव ठाकरे वॉकओवर दे सकते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वर्ली विधानसभा सीट पर आदित्य के लिए राज ठाकरे फिर एक बार बड़ा दिल दिखाएंगे? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज ठाकरे के सामने अमित ठाकरे को माहिम सीट से चुनाव लड़ाने का ऑफर दिया है। माहिम सीट पर मनसे 2009 में जीत दर्ज कर चुकी है और इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट शिवसेना (यूबीटी) के खाते में जाने की संभावना है।

कांग्रेस का गठबंधन से किनारा

कांग्रेस और भाजपा की साख दांव पर लगी

राजस्थान उपचुनाव की जिन सात विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें चार सीटें कांग्रेस कोटे से खाली हुई हैं। भाजपा, बीएपी और आरएलपी कोटे से एक-एक विधानसभा सीट खाली हुई है। इस तरह सबसे ज्यादा साख कांग्रेस की दांव पर लगी है तो भाजपा के सामने अपनी प्रतिष्ठा को बचाए रखने की चुनौती है। कांग्रेस के सामने अपने कोटे की खाली चार विधानसभा सीटों को बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है तो सत्ता पर काबिज भाजपा क्या अपना दम दिखा पाएगी? कांग्रेस ने सातों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं यानी राजस्थान में कांग्रेस बिना गठबंधन के अकेले दम भर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था लेकिन उपचुनाव में ऐसा नहीं है और दोनों पार्टियां एक-दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं। अब उपचुनाव में कहीं त्रिकोणीय, तो कहीं भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी और राजकुमार रोत की बीएपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।

सियासत में कोई किसी का सगा नहीं होता, हर कोई अपना सियासी नफा-नुकसान का गुणा-भाग कर दोस्त और दुश्मन बनाने का फैसला करता है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में जिनके साथ फायदा दिख रहा था, उन्हें गले लगाने से परहेज नहीं किया, लेकिन उपचुनाव में उन्हीं से किनारा कर लिया है। उप्र से लेकर राजस्थान तक हो रहे उपचुनाव में यही पैटर्न दिख रहा है कि बड़े दल अपने पार्टनर दल पर भरोसा करने के बजाय अपने दम पर चुनावी जंग लड़ने उतरे हैं। राजस्थान में कांग्रेस बीएपी और आरएलपी के साथ मिलकर 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी, लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस ने दोनों ही सहयोगी दलों से किनारा कर लिया है। राजस्थान उपचुनाव में सभी सातों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस ने झुंझुनू से अमित ओला को टिकट दिया है तो रामगढ़ से विधायक रहे जुबेर खान के बेटे आर्यन जुबेर पर भरोसा जताया है। दौसा सीट से डीडी बैरवा, देवली-उनियारा से केसी मीणा, खींवसर से डॉ. रतन चौधरी, सलूंबर से रेशमा मीना और चौरासी से महेश रोत को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है।

कांग्रेस ने राजस्थान में गठबंधन से किनारा कर लिया है और अपने दम पर उपचुनाव लड़ने के लिए ताल ठोक दी है। भारतीय आदिवासी पार्टी (बीएपी) चौरासी और सलूंबर सीट से चुनाव लड़ रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और बीएपी मिलकर लड़ी थी, लेकिन उपचुनाव में एक-दूसरे के खिलाफ किस्मत आजमा रही है। ऐसे में कुछ सीटों पर भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय लड़ाई की संभावना बन गई है। राजस्थान की सात में से छह सीट पर भाजपा ने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी तक चौरासी विधानसभा सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद अब **इंडिया गठबंधन** के इंतजार में बैठी हनुमान बेनीवाल की आरएलपी भी अब खींवसर के अलावा अन्य कुछ सीटों पर भी अपने प्रत्याशी उतार सकती है। राजस्थान की सात विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जिसमें पांच सीटें विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई है तो दो सीटें विधायक के निधन से खाली हुई हैं। रामगढ़ सीट कांग्रेस से विधायक रहे जुबेर खान और सलूंबर सीट भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा के निधन से खाली हुई हैं। वहीं, पांच विधानसभा सीटें 2024 के लोकसभा चुनाव में विधायकों के सांसद बन जाने से खाली हुई हैं, जिसमें झुंझुनू सीट कांग्रेस विधायक बृजेंद्र ओला, देवली-उनियारा सीट हरीश चंद्र मीणा और दसाऊ सीट मुरारीलाल मीणा के लोकसभा सांसद चुने जाने से खाली हुई हैं। इसके अलावा खींवचर सीट आरएलपी के विधायक रहे हनुमान बेनीवाल और चौरासी सीट भारत आदिवासी पार्टी के विधायक राजकुमार रोत के लोकसभा सांसद चुने जाने से खाली हुई है। दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने डीडी बैरवा को प्रत्याशी बनाया है। बैरवा की पत्नी बीना बैरवा वर्तमान में लवाण पंचायत समिति की प्रधान हैं जबकि बीडी बैरवा जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं। डीडी बैरवा का मुकाबला भाजपा के जगमोहन मीणा से है। जगमोहन मीणा राजस्थान के कैबिनेट मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा के छोटे भाई हैं। रामगढ़ सीट पर कांग्रेस ने आर्यन जुबेर को प्रत्याशी बनाया है, जो पूर्व विधायक जुबेर खान के छोटे बेटे हैं। यह सीट जुबेर खान के निधन के चलते खाली हुई है और कांग्रेस ने उनके बेटे को उतारकर सहानुभूति का लाभ उठाने की कोशिश की है। ऐसे में आर्यन का मुकाबला भाजपा के सुखवंत सिंह से है। खींवसर सीट पर भाजपा से रेवंत राम डांगा चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से डॉ. रतन चौधरी किस्मत आजमाएंगी। रतन चौधरी पूर्व आईपीएस सवाई सिंह की पत्नी हैं और ज्योति मिर्धा के साथ ही इन्होंने भी भाजपा जॉइन की थी, लेकिन अब कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगी। देवली उनियारा सीट पर भाजपा से राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ रहे हैं तो कांग्रेस से केसी मीणा मैदान में होंगे। हाल ही में केसी मीणा ने वीआरएस लिया है और कांग्रेस सांसद हरीश मीणा की पैरवी पर टिकट मिला है। इस तरह हरीश मीणा अपनी सीट से अपने करीबी को चुनाव लड़ा रहे हैं।

सलूंबर से भाजपा ने दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की पत्नी शांता देवी मीणा को चुनावी मैदान में उतारा है तो कांग्रेस ने रघुवीर मीणा की जगह रेशमा को टिकट देकर चौंका दिया है। बीएपी ने जितेश कटारा को प्रत्याशी बनाया है, लेकिन भाजपा ने सहानुभूति कार्ड खेला है। चौरासी विधानसभा सीट पर कांग्रेस से महेश रोत चुनाव लड़ रहे हैं, जो छात्र राजनीति से आए हैं। भाजपा ने चौरासी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन बीएपी ने अनिल कटारा को उतारकर मुकाबला रोचक बना दिया है। यहां पर बीएपी के प्रमुख राज कुमार रोत की साख दांव पर लगी है। झुंझुनू विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अमित ओला को प्रत्याशी बनाया है तो भाजपा ने राजेंद्र भांबू पर दांव खेला है। कांग्रेस ने अपने कब्जे वाली झुंझुनू सीट को बचाए रखने के लिए गहलोत सरकार के पूर्व मंत्री और झुंझुनू से मौजूदा सांसद बृजेंद्र ओला के बेटे अमित ओला पर दांव खेला है। 2023 चुनाव में यह सीट बृजेंद्र ओला ने जीती थी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

ओवैसी ने बढ़ाई टेंशन

उप्र विधानसभा उपचुनाव में सपा और भाजपा के बीच मुकाबले में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की भी एंट्री हो गई है। ओवैसी ने उपचुनाव की 9 सीटों में से मुस्लिम बहुल दो सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। एआईएमआईएम ने कुंदरकी विधानसभा सीट से मोहम्मद वारिस और मीरापुर विधानसभा सीट से अरशद राणा को उम्मीदवार बनाया है। पश्चिमी उप्र की दोनों मुस्लिम बहुल सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट उतारकर असदुद्दीन ओवैसी ने सपा और बसपा की टेंशन बढ़ा दी है। ऐसे में मुकाबला रोचक हो गया है?

उप्र उपचुनाव में ओवैसी ने पीडीएम (पिछड़ा, दलित, मुस्लिम) फॉर्मूले पर चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसके तहत मुस्लिम बहुल सीटों पर एआईएमआईएम चुनाव लड़ रही है तो ओबीसी बहुल सीटों पर ओबीसी आधारित पार्टियों के खाते में गई है। इसके तहत ही कुंदरकी और मीरापुर सीट पर ओवैसी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा तो मझवां सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने मझवां सीट से स्वयंबर पाल को कैंडिडेट घोषित किया है। ओवैसी ने जिन दो सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, उनमें सपा और बसपा ने भी मुस्लिम उम्मीदवार पर ही दांव खेल रखा है।

मीरापुर विधानसभा सीट से 2022 में सपा के समर्थन से आरएलडी के चंदन चौहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में बिजनौर से सांसद बन गए हैं। आरएलडी ने अब भाजपा के साथ गठबंधन कर रखा है, जिसके तहत मीरापुर सीट जयंत चौधरी की आरएलडी के खाते में गई है। आरएलडी ने अभी अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। सपा ने पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को प्रत्याशी बनाया है तो बसपा ने शाहनजर पर दांव लगाया है। चंद्रशेखर आजाद की आसपा ने जाहिद हुसैन को उम्मीदवार बनाया है और अब ओवैसी ने भी अरशद राणा को उतार दिया है। मीरापुर सीट पर चार दलों से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में है, जिसके चलते मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बसपा, सपा, आसपा और एआईएमआईएम की ओर से मुस्लिम प्रत्याशी उतारने की घोषणा के बाद आरएलडी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन कर दिया है। अब आरएलडी गुर्जर या फिर जाट समाज के किसी चेहरे को उतार सकता है। भाजपा के साथ गठबंधन होने के चलते आरएलडी हिंदू प्रत्याशी मीरापुर में उतारती है तो मुकाबला रोचक हो सकता है।

कुंदरकी विधानसभा सीट से 2022 में सपा के जियाउर्रहान विधायक चुने गए थे, लेकिन 2024 में संभल सीट से सांसद बन गए हैं। कुंदरकी सीट पर सपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं यानी टिकट घोषित नहीं किए हैं। सपा से पूर्व विधायक हाजी रिजवान के चुनाव लड़ने की प्रबल उम्मीद है। बसपा ने रफतउल्ला उर्फ छिद्दा को प्रत्याशी बनाया है तो ओवैसी की एआईएमआईएम से मोहम्मद वारिस को उतारा है। चंद्रशेखर आजाद ने आसपा से हाजी चांद बाबू को प्रत्याशी बनाया है। इस तरह चार विपक्षी दलों से मुस्लिम कैंडिडेट मैदान में है, जिसके चलते मुकाबला मुस्लिम बनाम मुस्लिम कुंदरकी सीट पर हो गया है। भाजपा ने अभी टिकट घोषित नहीं किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने मीरापुर सीट पर कांग्रेस से आए नेता को प्रत्याशी बनाया है तो कुंदरकी में प्रभावी चेहरे पर दांव खेला है। कुंदरकी सीट पर ओवैसी की पार्टी का अपना सियासी आधार रहा है। इन दोनों ही सीटों पर सपा का सियासी आधार पूरी तरह से मुस्लिम वोटबैंक पर टिका हुआ है, क्योंकि दोनों ही सीटों पर यादव वोटर एकदम नहीं है। ओवैसी ने जिस तरह से मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं और बसपा से लेकर चंद्रशेखर आजाद तक के मुस्लिम कैंडिडेट हैं। आसपा और बसपा दलित और मुस्लिम वोट के सहारे सियासी नैया पार लगाना चाहती है।

ओवैसी से लेकर सपा, बसपा और चंद्रशेखर आजाद तक मुस्लिम वोटों को ही साधने में लगे हैं तो भाजपा और आरएलडी की नजर बहुसंख्यक समाज के वोटबैंक पर है। मुख्यमंत्री योगी से लेकर भाजपा के कई नेता खुलकर बटोगे तो कटोगे का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इसके जरिए हिंदू वोटों को सियासी संदेश दिया जा रहा है। उप्र के उपचुनाव में भी भाजपा बटोगे तो कटोगे का दांव चल सकती है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना सपा-बसपा का चुनावी गेम बिगाड़ सकती है तो भाजपा के लिए उम्मीद की किरण जगा सकती है? मीरापुर और कुंदरकी जैसे मुस्लिम बहुल सीटों पर सभी विपक्षी पार्टियों ने मुस्लिम प्रत्याशी पर दांव खेला है, जिसके चलते मुस्लिम वोटों के बिखराव की संभावना बन गई है। मीरापुर सीट पर करीब 35 फीसदी के करीब मुस्लिम वोटर हैं तो कुंदरकी में 50 फीसदी से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

उम्मीदवार और सिंबल दोनों सपा के होंगे

उप्र विधानसभा चुनाव की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने आपस में मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा था कि कांग्रेस सपा के उम्मीदवार को समर्थन करेगी। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय और उप्र कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि उप्र में कांग्रेस विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेगी। सभी सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस सपा के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। अखिलेश यादव द्वारा यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर ट्वीट करने के बाद कांग्रेस का यह अधिकारिक बयान सामने आया है। अविनाश पांडे ने कहा कि उप्र में आगामी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। हम इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के सभी प्रत्याशियों को पूरी ताकत से जिताने का काम करेंगे। इस देश के संविधान और देश के मूल्यों को बचाने के लिए और भाजपा के हराने के लिए जनता के हित में यह आवश्यक निर्णय लिया गया है। अविनाश पांडे ने कहा कि उप्र में 10 में से 9 सीटों पर उपचुनाव कराने का चुनाव आयोग ने ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा पिछले 10 सालों से देश में संविधान को कमजोर करने के लिए और अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में उप्र की जनता ने करारा जवाब देकर उन्हें सचेत किया है।

झारखंड में न्यू परिवारवाद

चुनाव के वक्त आमतौर पर नेता अपने बेटे या बेटी को सियासी विरासत सौंप देते हैं, लेकिन झारखंड में परिवारवाद का ट्रेंड बदल गया है। यहां बहुएं सियासी विरासत संभालने मैदान में उतर गई हैं। करीब आधा दर्जन सीटों पर नेताओं ने अपनी बहुओं को आगे किया है।

झारखंड के चुनाव में इस बार नेताओं के बेटे, बेटियां और पत्नियों से ज्यादा बहुओं का सियासी दबदबा है। राज्य की करीब आधा दर्जन सीटों पर नेताओं की बहुएं सियासी विरासत संभालने उतरी हैं। इनमें शिबू सोरेन की बहू सीता और कल्पना, रघुबर दास की बहू पूर्णिमा का नाम प्रमुख है। इनमें कुछ नेताओं की बहुएं पहले ही सियासी तौर पर स्थापित हो चुकी हैं तो कुछ पहली बार राजनीति में उतर रही हैं।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन की 2 बहुएं सियासी मैदान में हैं। गिरिडिह की गांडेय सीट से शिबू के बेटे हेमंत की पत्नी कल्पना चुनाव लड़ रही हैं। कल्पना 2024 में इस सीट से उपचुनाव जीत चुकी हैं। हेमंत के जेल जाने के बाद कल्पना ने राजनीति में एंट्री ली। एमबीए तक की पढ़ाई करने वाली कल्पना की शादी 7 फरवरी 2006 को हेमंत सोरेन से हुई थी। दोनों के दो बच्चे हैं। कल्पना सोरेन राजनीति में आने से पहले एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रही थीं।

शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता भी राजनीति में हैं। सीता अपने पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद राजनीति में आईं। वे जामा सीट से विधायक भी रह चुकी हैं। हालांकि, 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने इस बार सीता सोरेन को जामताड़ा से मैदान में उतारा है। जामताड़ा सीट भाजपा के लिए सियासी तौर पर आसान नहीं है। यहां आदिवासी और मुस्लिम गठजोड़ काफी मजबूत है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल रघुबर दास ने जमशेदपुर पूर्वी सीट से अपनी बहू पूर्णिमा दास को मैदान में उतारा है। 2019 में रघुबर दास इस सीट से चुनाव हार गए थे। इसके बाद से ही उनकी झारखंड की सियासत से विदाई हो गई। पूर्णिमा की शादी 2019 में रघुबर के इकलौते बेटे ललित दास से हुई है। ललित हाल ही में तब सुर्खियों में आए थे, जब ओडिशा राजभवन के एक कर्मचारी ने उन पर मारपीट का आरोप लगाया था। यह मामला विधानसभा में भी उछला था। छत्तीसगढ़ की मूल निवासी पूर्णिमा ने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की है। पूर्णिमा पर जमशेदपुर में रघुबर दास की सियासी विरासत को लौटाने की जिम्मेदारी है।

झारखंड आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की बहू सविता महतो भी सियासी मैदान में हैं। सविता झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिंबल पर सरायकेला की इचागढ़ सीट से लड़ रही हैं। 2019 में सविता इस सीट से जीत भी चुकी हैं। 2014 में पति सुधीर महतो के निधन के बाद सविता राजनीति में आईं। इचागढ़ सीट पर सविता का मुकाबला आजसू उम्मीदवार से है। सविता महतो ने नौंवी तक की पढ़ाई की हुई है। सविता के नामाकंन सभा में हेमंत सोरेन ने कहा कि इनके अंदर शहीदों का खून दौड़ रहा है। भाजपा के लोग इनसे क्या मुकाबला कर सकेंगे?

संयुक्त बिहार-झारखंड के कद्दावर नेता रहे अवध बिहारी सिंह की बहू दीपिका पांडे फिर से मैदान में हैं। दीपिका महगामा सीट से 2019 में जीती थी, जिसके बाद उन्हें हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री बनाया गया था। दीपिका के पति प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं। दीपिका राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता क्षेत्र में सक्रिय थीं। यूथ कांग्रेस के जरिए राजनीति में आने वाली दीपिका को 2014 में गोड्डा का जिलाध्यक्ष बनाया गया था। दीपिका का इस बार मुकाबला पुराने प्रतिद्वंद्वी अशोक भगत से है।

सत्यानंद भोगता हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं। 2019 में वे चतरा (सुरक्षित) सीट से जीतकर विधायक बने थे। 2022 में उनकी जाति को केंद्र सरकार ने आदिवासी वर्ग में आरक्षित कर दिया। भोगता और उनके बेटे इस वजह से चतरा सीट से चुनाव लड़ने से वंचित रह गए, लेकिन भोगता ने सियासी हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी बहू रश्मि प्रकाश को यहां से मैदान में उतार दिया है। रश्मि की जो जाति है, वो दलित कैटेगरी के अधीन है और रश्मि इस वजह से चतरा सीट से चुनाव लड़ने योग्य हैं। रश्मि के पति मोहित स्थानीय कोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत हैं। रश्मि का मुकाबला चतरा सीट पर चिराग पासवान के उम्मीदवार जनार्दन पासवान से है। जनार्दन पहले भी सत्यानंद भोगता के सामने चुनाव लड़ चुके हैं।

● **टीपी सिंह**

सरना धार्मिक कोड बनेगा बड़ा मद्दा

झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राजनीतिक पार्टियां चुनावी अखाड़े में जमकर पसीना बहा रही हैं। सत्तापक्ष और विपक्ष की ओर से एक-दूसरे पर जमकर प्रहार किए जा रहे हैं। इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेने की पत्नी कल्पना सोरेन ने भाजपा को चुनौती दी है कि अगर उसमें हिम्मत है तो वह सरना धार्मिक कोड का समर्थन करे। यही नहीं, उन्होंने भाजपा को भर्ती नीति, आदिवासी अधिकारों और ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण का समर्थन करने को लेकर भी चुनौती है। कल्पना सोरेन ने धनबाद जिले के टुंडी में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती है, जिसे झारखंड के लोग समझ गए हैं। इसके लिए भगवा पार्टी को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जेएमएम विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों, ओबीसी और महिलाओं के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं। दरअसल, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री रहते हुए चंपई सोरेन सरना धर्म को लेकर आवाज उठा चुके हैं। यह राज्य की आदिवासी आबादी के बीच लंबे समय से लंबित और भावनात्मक मांग है। चंपई सोरेन अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। प्रकृति की पूजा पर केंद्रित सरना आदिवासी धर्म मुख्य रूप से झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, असम और पश्चिम बंगाल में आदिवासी समुदायों की ओर से मनाया जाता है। अभी इस धर्म को लेकर कोई अलग कोड नहीं था। केवल हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के पास अपना खुद का कोड है। 2011 की जनगणना में लगभग 50 लाख लोगों ने अपना धर्म सरना के रूप में दर्ज किया था।

बांग्लादेश में एक बार फिर बड़े छात्र आंदोलन की आहट सुनाई पड़ रही है, शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर दिए गए राष्ट्रपति शहाबुद्दीन के बयान से छात्र नाराज हैं और वो राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। छात्रों की इस मांग के बीच एक सवाल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की संवैधानिक वैधता को लेकर भी उठ रहा है। अगर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है तो क्या सेना की ओर से गठित मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार गैर-कानूनी है?

तख्तापलट के बाद भी नहीं बदले हालात

बांग्लादेश में एक नया संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या शेख हसीना अब भी देश की प्रधानमंत्री हैं और अगर ऐसा है तो क्या सेना की ओर से गठित मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अवैध है? क्योंकि संविधान के मुताबिक प्रधानमंत्री का पद तभी खाली होगा जब वह राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपे। लेकिन अगस्त में बांग्लादेश छोड़कर भारत पहुंची शेख हसीना का इस्तीफा हुआ भी है या नहीं यह अब एक बड़ा सवाल बनकर रह गया है। दरअसल, बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनके पास शेख हसीना के इस्तीफे का कोई सबूत नहीं है। उनके इस बयान से छात्र संगठनों में खासा आक्रोश है। गत दिनों जहां राष्ट्रपति के खिलाफ कई छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया तो वहीं भेदभाव विरोधी छात्र संगठन के लीडर्स ने मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार को अल्टीमेटम तक दे डाला। छात्रों ने राष्ट्रपति के इस्तीफे समेत कई मांगें सरकार के सामने रखी थीं। इसमें सबसे प्रमुख मांग थी शेख हसीना की पार्टी के छात्र संगठन पर बैन और नए राष्ट्रपति का ऐलान। हालांकि मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश स्टूडेंट लीग पर प्रतिबंध लगा दिया है लेकिन राष्ट्रपति बदलने की संभावना से सरकार ने इनकार कर दिया है।

वहीं इस मामले को लेकर बीएनपी और अंतरिम सरकार के बीच मतभेद देखने को मिला, जिसके बाद 23 अक्टूबर को रात आनन-फानन में खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी के नेता अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस से मिलने पहुंचे। दरअसल बीएनपी की लीडरशिप का मानना है कि मौजूदा समय में राष्ट्रपति पर इस्तीफे के लिए दबाव डालने से संवैधानिक और राष्ट्रीय संकट पैदा हो सकता है। वहीं अंतरिम सरकार के कानून मंत्री नाहिद इस्लाम का कहना है कि मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है और बातचीत जारी है। नाहिद इस्लाम, शेख हसीना के खिलाफ हुए आंदोलन के मुख्य चेहरों में से एक थे जिन्हें मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में जगह मिली थी।

सूत्रों के हवाले से खबर है कि राष्ट्रपति के बयान से मचे बवाल के बाद यूनुस सरकार के एक वरिष्ठ सलाहकार और दो छात्र नेताओं ने न्यायपालिका के वरिष्ठ सदस्य से मुलाकात की और उन्हें राष्ट्रपति बनाए जाने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। सूत्रों के अनुसार, जमात-ए-इस्लामी के छात्र विंग की राजनीतिक पकड़ को कमजोर करने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वकार-उज-जमां राष्ट्रपति के बाद इन छात्र नेताओं का अगला टारगेट हो सकते हैं। इसके बाद अगला कदम बांग्लादेश के संविधान में बदलाव होगा जिसकी मांग भेदभाव विरोधी छात्र संगठन ने 22 अक्टूबर को की थी। इस छात्र संगठन के संयोजक हसनत अब्दुल्ला ने कहा था कि हमारी 5 मांगों में से सबसे पहली मांग है प्रो-मुजीब 1972 संविधान को हटाना, जिसकी वजह से राष्ट्रपति अपने पद पर बने हुए हैं। छात्र संगठनों ने कहा है कि अगर मोहम्मद यूनुस की सरकार इन मांगों को एक हफ्ते में पूरा नहीं करती है तो वह एक बार फिर पूरी ताकत के साथ सड़क पर उतरेंगे।

छात्रों की इस मांग के बीच एक सवाल मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार की संवैधानिक वैधता को लेकर भी उठ रहा है। अगर शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है तो क्या सेना की ओर से गठित मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार गैर-कानूनी है? दरअसल, बांग्लादेश के संविधान की धारा 57 (ए) के मुताबिक प्रधानमंत्री किसी भी समय राष्ट्रपति को इस्तीफा दे सकता है, जिसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। लेकिन बांग्लादेश के राष्ट्रपति का कहना है कि उनके पास शेख हसीना का इस्तीफा नहीं है। ऐसे में क्या ये माना जाए कि शेख हसीना अब भी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। वहीं दूसरी ओर बांग्लादेश के संविधान में कार्यवाहक सरकार का प्रावधान खत्म किया जा चुका है, 2011 तक देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कार्यवाहक सरकार का प्रावधान था लेकिन 30 जून 2011 को शेख हसीना की पार्टी ने संविधान संशोधन कर इस प्रावधान को रद्द कर दिया था।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

अंतरिम सरकार को बचाने की कोशिश

ताजा विवाद के बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार अजीज अहमद भुइयां ने बताया है कि गत दिनों कानून मामलों के सलाहकार आसिफ नजरुल और मंत्री नाहिद इस्लाम ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सैयद रफात अहमद के साथ उनके दफ्तर में करीब आधे घंटे लंबी मुलाकात की। हालांकि इस मुलाकात के दौरान किस विषय पर चर्चा की गई इसकी जानकारी नहीं दी गई। बांग्लादेश के संविधान के आर्टिकल 106 के मुताबिक, अगर देश में कोई ऐसा समय आता है जब राष्ट्रपति के सामने कानून से जुड़ा कोई सवाल पैदा होता है या जिसके पैदा होने की संभावना है, और जो वाकई जनता के हित से जुड़ा मुद्दा है तो इसके उपाय के लिए राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी चाहिए। इसके लिए राष्ट्रपति उस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट की अपीलीय डिविजन के सामने भेज सकते हैं। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट अपनी राय राष्ट्रपति को बता सकता है। लिहाजा माना जा रहा है कि अंतरिम सरकार को इस संवैधानिक संकट से निकालने की कोशिशें तेज हो गई हैं। एक ओर छात्र राष्ट्रपति को हटाने की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार अपने की अस्तित्व को बचाने के प्रयास में जुटी हुई है। आने वाले कुछ दिनों में बांग्लादेश ने अगर इन तमाम विवादों को नहीं सुलझाया, तो एक बड़ा राजनीतिक और संवैधानिक संकट पैदा हो सकता है।

PRISM®
CEMENT

प्रिज़्म® चैम्पियन प्लस

ज़िम्मेदारी मज़बूत और टिकाऊ निर्माण की.

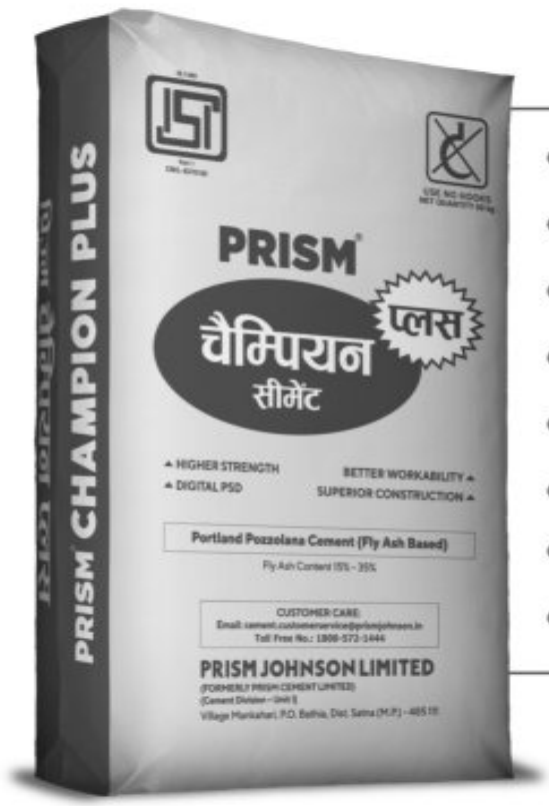

- ज्यादा मज़बूती
- ज्यादा महीन कण
- ज्यादा वर्कबिलिटी
- बेहतरीन निर्माण कार्य
- इको–फ्रेन्डली
- कन्सिसटेंट क्वालिटी
- ज्यादा प्रारम्भिक ताक़त
- ज्यादा बचत

PRISM®
चैम्पियन प्लस
सीमेंट

दूर की सोच®

Toll free: 1800-572-1444 Email: cement.customerservice@prismjohnson.in

कमला की लोकप्रियता ऊान पर

अमेरिका में नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव का अंदाजा चुनाव पूर्व प्रत्याशियों के बीच हुई सार्वजनिक बहस में जीत-हार से नहीं लगाया जा सकता। फिलहाल, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने पूर्व राष्ट्रपति तथा रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रम्प को प्रेसिडेंशियल डिबेट में पछाड़ दिया है। वे बहुत आत्मविश्वास में दिखीं, उनके हमले बहुत पैने थे और उन्होंने ट्रम्प को ऐसा छीला कि वे भड़क गए। खासकर, जब कमला ने ट्रम्प की रैलियों में आ रही कम भीड़ का हवाला दिया तो ट्रम्प हड़बड़ा गए। बहस देखने वालों के बीच सीएनएन के एक तत्काल सर्वे से पता चला कि 63 फीसदी लोग मान रहे हैं कि कमला हैरिस ने बाजी जीत ली है जबकि 37 फीसदी ट्रम्प के पक्ष में हैं। ट्रम्प और उनके समर्थकों ने एबीसी चैनल के प्रस्तोताओं पर आरोप लगाया कि वे हैरिस का पक्ष ले रहे थे। ऐसा लगता है कि रिपब्लिकन पार्टी को ट्रम्प की हार का अहसास है।

अमेरिका आज एक बंटा हुआ राष्ट्र है। वहां भी भारत की तरह गैरों का खौफ चुनावी बहसों पर हावी है। अमेरिका के गोरे ईसाइयों को डर है कि उनके प्रभुत्व को गैरों से चुनौती मिल रही है। यह डर कमला हैरिस के कारण पैदा हुआ है जो अश्वेत हैं, एशियाई मूल की हैं और एक साथ नस्ली पूर्वाग्रहों और पितृसत्ता को चुनौती दे रही हैं। अमेरिका में पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में बराक ओबामा के चुने जाने के बाद अचानक गोरों के वर्चस्ववादी समूह सक्रिय हो गए थे। उन्होंने ओबामा के बारे में झूठ फैलाना शुरू कर दिया था कि वे मुसलमान हैं और देश के बाहर पैदा हुए हैं। ट्रम्प के कार्यकाल के दौरान गोरों की ऐसी साजिशों को हवा मिली, जिसकी परिणति कैपिटल हिल पर हमले में हुई। गैरों का ऐसा डर, खासकर अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में कुछ तबकों पर खूब हावी है। इसकी छाया राजनीति पर भी पड़ी है। बांटने वाली इसी राजनीति का फायदा डोनाल्ड ट्रम्प को मिला है। न सिर्फ रिपब्लिकन पार्टी के भीतर उनका प्रभुत्व बढ़ा है, बल्कि उनकी निजी लोकप्रियता में भी इजाफा हुआ है। इसीलिए कमला हैरिस की लोकप्रियता बढ़ती हुई तो दिख रही है, पर उनकी लड़ाई डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत करीबी रहने वाली है। खासकर पेनसिल्वेनिया, जॉर्जिया, विस्कॉन्सिन, नेवादा, एरिजोना और मिशिगन में यह लड़ाई कांटे की होगी और यही प्रांत अंतिम चुनाव नतीजों को तय करेंगे। गर्भपात और प्रजनन अधिकारों पर अपने पक्ष के चलते कमला को औरतों का खास समर्थन है। इसमें वे लोग भी हैं जो परंपरागत रूप से रिपब्लिकन पार्टी के हुआ करते थे। इसकी वजह यह है कि वे मानते हैं कि पार्टी का चरित्र अब बदल चुका है और उसके ऊपर अब ट्रम्प की चौतरफा छाप है। इसके प्रमुख उदाहरणों में पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी, उनकी बेटी और कांग्रेस प्रतिनिधि लिज चेनी, पूर्व कांग्रेस प्रतिनिधि एडम किंजिंगर, ट्रम्प की वाइट हाउस प्रेस सचिव तथा मेलेनी ट्रम्प की चीफ ऑफ स्टाफ रह चुकीं स्टेफिनी ग्रीशम, और कुछ समय के लिए ट्रम्प के प्रेस सचिव का काम कर चुके एंथनी कारामुच्ची हैं। इन सभी ने अबकी बार हैरिस को अपना समर्थन दे दिया है। इतना ही नहीं, ट्रम्प के विश्वस्त सहयोगी और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके जॉन बोल्टन भी पाला छोड़ चुके हैं। उन्होंने अब तक हैरिस को समर्थन तो नहीं दिया है, लेकिन वे अब ट्रम्प के कटु आलोचक बन गए हैं और अक्सर उनकी बुद्धिमत्ता पर सवाल उठाते हैं।

दो साल पहले सभी दलों की महिलाएं अवाक रह गई थीं जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने रो बनाम वेड के मुकदमे में 1973 का एक फैसला पलट डाला था, जो औरतों को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देता था। उसके बाद कई रिपब्लिकन-शासित प्रांतों ने गर्भपात का अधिकार समाप्त कर दिया, जिससे औरतों को अवांछित गर्भ समाप्त करने में बहुत दिक्कत आने लगी। कमला हैरिस इस फैसले के खिलाफ जमकर बोलीं। उनका कहना था कि अपनी देह से जुड़े फैसले लेने का अधिकार खुद औरतों के पास होना चाहिए, सरकार के पास नहीं। तब जाकर ट्रम्प को लगा कि कहीं औरतों का वोट उनके हाथ से चला न जाए। तब से वे यही कह रहे हैं कि यह मसला प्रांतों के अधिकार-क्षेत्र में छोड़ दिया जाना चाहिए। जिन औरतों को 2016 में उम्मीद थी कि हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बन जाएंगी, उन्हें उनकी हार से बहुत निराशा हुई थी। इन तमाम औरतों को अब लगता है कि इतिहास पलटने का हैरिस के पास यही मौका है। अगर वे जीत जाती हैं, तो न सिर्फ वे पहली महिला राष्ट्रपति होंगी बल्कि दक्षिण एशियाई मूल की पहली अश्वेत राष्ट्रपति भी होंगी। इस राह में हालांकि उनका पिछला रिकॉर्ड आड़े आ रहा है, जबसे उन्होंने जो बाइडन के नेतृत्व में उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभाला। बाइडन प्रशासन के तीन वर्षों के दौरान वे तकरीबन अदृश्य रही हैं। बाइडन ने उन्हें मैक्सिको और मध्य अमेरिका से पलायन के कारणों की पड़ताल करने का जिम्मा सौंपा था क्योंकि डेमोक्रेट पार्टी का मानना था कि अवैध प्रवासन एक गंभीर घरेलू समस्या बनता जा रहा है। इस संदर्भ में बाइडन के नीतिगत प्रस्ताव बहुत कठोर थे- सीमाओं पर शरणार्थी दावों में कमी लाना, अवैध प्रवासियों के निष्कासन में तेजी लाना और प्रवासी बच्चों को उनके माता-पिता से अलग करना। हैरिस को इस संबंध में रिपब्लिकन सांसदों के हमलों का शिकार होना पड़ा कि वे सीमा पर अवैध प्रवासन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रही हैं।

● **कुमार विनोद**

विदेश नीति

प्रेसिडेंशियल बहस में इजरायल और यूक्रेन का मसला भी उठा था, लेकिन बोलने के लिए समय इतना कम था कि कुछ खास निकलकर नहीं आ सका। ट्रम्प ने हमेशा की तरह दंभ में कहा कि यदि वे राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन पर रूस हमला नहीं कर पाता। उन्होंने दावा किया कि चुनाव जीतने के बाद वे शपथ लेने से पहले ही शांति बहाली कर देंगे। वे ऐसा कैसे करेंगे, इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि हैरिस इजरायल से नफरत करती हैं, इसीलिए वे कांग्रेस के संयुक्त सत्र में नेतन्याहू के भाषण में नहीं गई थीं। ट्रम्प के भाषण में तानाशाहों की प्रशंसा भी देखने को मिली, जब उन्होंने हंगरी के विक्टर ओर्बन की बड़ाई की और कहा कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं। उन्होंने चीन के शी जिनपिंग और रूस के व्लादिमीर पुतिन का भी जिक्र किया। कमला हैरिस ने इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार की पैरवी करते हुए द्विराष्ट्र सिद्धांत को समाधान बताया और एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र के निर्माण की वकालत की। बहस के अंत तक लोगों को दोनों प्रत्याशियों की ओर से नीतिगत मसलों पर बहुत कुछ सुनने को नहीं मिला।

लोक आस्था का महापर्व-'छठ'

लोक-आस्था के महापर्व छठ को हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार माना जाता है। यह मुख्यत: बिहार, पूर्वी उप्र और झारखंड में मनाया जाता है लेकिन इस पर्व से जुड़ी आस्था और महत्व के कारण अब देश के लगभग सभी भागों यहां तक कि विदेशों में भारतीय मूल के लोग भी इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। विशेषकर महिलाएं इस व्रत को अपने संतान और परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं।

छठ पर्व, भगवान सूर्यदेव और प्रकृति से जुड़ा हुआ एक महान पर्व है जो वैदिक काल से मनाया जा रहा है। महाभारत और रामायण में भी छठ पर्व का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि पांडव जब सारा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने चार दिनों तक इस व्रत को किया था।

छठ पर्व की पौराणिक कथा के अनुसार, राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। इसे लेकर राजा और उसकी पत्नी दोनों हमेशा दुखी रहते थे। संतान प्राप्ति की इच्छा के साथ राजा और उसकी पत्नी महर्षि कश्यप के पास पहुंचे। महर्षि कश्यप ने यज्ञ कराया और इसके फलस्वरूप प्रियव्रत की पत्नी गर्भवती हो गईं लेकिन नौ महीने बाद रानी ने जिस पुत्र को जन्म दिया, वह मरा हुआ पैदा हुआ। यह देख प्रियव्रत और रानी अत्यंत दुखी हो गए। संतान शोक के कारण राजा ने पुत्र के साथ ही श्मशान पर स्वयं के प्राण त्यागने व आत्महत्या करने का मन बना लिया। जैसे ही राजा ने स्वयं के प्राण त्यागने की कोशिश की वहां एक देवी प्रकट हुईं जो कि मानस पुत्री देवसेना थीं। देवी ने राजा से कहा कि वे सृष्टि की मूल प्रवृति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हैं। उन्होंने कहा मैं षष्ठी देवी हूं। यदि तुम मेरी पूजा करोगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करोगे तो मैं पुत्र रत्न प्रदान करूंगी।

संभवत: तभी से संतान की कामना के साथ लोग पूरी निष्ठा और पवित्रता से इस महापर्व को मनाते आ रहे हैं। ऐसी भी मान्यता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत को करने से कुष्ठ और सफेद दाग जैसे रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। इस पर्व को विधि-विधान से संपन्न करने के बाद व्रती की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वैसे तो इस पर्व को मनाने के लिए लोग सूर्य मंदिरों में जाते हैं। गंगा के पावन घाटों पर भी भारी संख्या में व्रती और उनके परिजन इस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। अर्घ्य देने के लिए पवित्र नदियों, पोखरों, तालाबों या कृत्रिम जलाशयों पर भी साफ-सुथरे घाटों को बनाया जाता है जहां व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य अर्पित करते हैं। आजकल भीड़भाड़ से बचने के लिए घरों की छत पर भी यह व्यवस्था की जाने लगी है, परंतु पर्व का असली आनंद तो छठ घाटों पर ही मिलता है, जहां गांव, कस्बे या शहर के सारे लोग एक स्थान पर एकत्रित होते हैं।

लोक आस्था के इस महापर्व छठ के चार दिवसीय पवित्र एवं कठिनतम अनुष्ठान का पहला दिन नहाय-खाय से शुरू होता है। इस दिन व्रत करने वाले गंगा या पवित्र सरोवरों के पावन जल से स्नान कर शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं जिनमें मुख्य रूप से अरवा चावल के साथ चना और कद्दू की दाल पवित्र स्थान पर पूर्ण शुद्धता के साथ सेंधा नमक में बनाया जाता है। व्रती भगवान सूर्य की आराधना और महानुष्ठान हर्षोल्लास के साथ संपन्न होने की कामना के साथ उक्त सामग्री को ग्रहण करते हैं। फिर उसे प्रसाद के रूप में परिजन और इष्ट-मित्रों को खिलाया जाता है।

अनुष्ठान के दूसरे दिन खरना होता है, जिसका अर्थ है- शुद्धिकरण। इसे लोहंडा भी कहा जाता है। जिसमें व्रती संध्या बेला में नदियों अथवा सरोवरों आदि में स्नान कर पूरी श्रद्धा निष्ठा और पवित्रता के साथ प्रसाद बनाने में जुट जाते हैं। इस विशेष प्रसाद में गाय के दूध में गुड़ अथवा गन्ने के रस की खीर तैयार करते हैं। साथ में घी से चुपड़ी हुई गेहूं के आटे की रोटियां और चावल के आटे का पिट्ठा भी बनाते हैं। प्रसाद को मिट्टी के चूल्हे पर आम की लकड़ी जलाकर तैयार किया जाता है। शाम ढलने के बाद व्रती पूजा-अर्चना तथा छठ माता और भगवान भास्कर को विशेष प्रसाद अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। शक्ति और स्फूर्ति बनाए रखने के लिए इच्छानुसार व्रती गाय के दूध का भी सेवन करते हैं क्योंकि इसके बाद लगातार 36 घंटे तक बिना अन्न-जल ग्रहण करते हुए पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ निर्जला उपवास करना होता है। खरना के दिन खीर और रोटी को प्रसाद के रूप में सभी लोगों को खिलाया जाता है। लोग इस दिन प्रसाद पाने के लिए व्रतधारी के घर या घाटों पर अवश्य जाते हैं और प्रसाद ग्रहण कर स्वयं को धन्य मानते हैं। कहीं-कहीं खरना के प्रसाद के रूप में चावल और सेंधा नमक में दाल बनाने और खिलाने की भी प्रथा है। अनुष्ठान के तीसरे दिन की सुबह लगभग चार बजे के पहले से ही व्रती और उनके परिजन नहा-धोकर पूरी पवित्रता के साथ मुख्य प्रसाद ठेकुआ बनाने में लग जाते हैं। ठेकुआ को गेहूं के आटा में गुड़ मिलाकर बनाया जाता है और शुद्ध घी में तला जाता है।

भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के समय व्रती के हाथ में जो बांस से बना हुआ या पीतल का सूप होता है उसमें सभी प्रकार के फल जैसे केला, सेवा, संतरा, शरीफा, अमरूद, पानीफल (सिंघारा), घघरा नींबू, पानी वाला नारियल, ईख, अन्नानास, त्रिफला, सुथनी, शकरकंद, पत्ते वाली हल्दी और अदरक के साथ ठेकुआ और चावल के आटे से बना पिट्ठा भी रखा जाता है। इनके अलावा पान का पत्ता, तुलसीदल, बद्धि (धागे की माला), आलता आदि भी रखा जाता है। फिर सारे सूपों को बांस से बनी हुई बड़ी टोकरी में रख दिया जाता है जिस पर अक्षत, सिंदूर और चावल के आटे का लेप लगाया जाता है। मिट्टी के दिए में घी की बाती और धूप भी जलाते हैं। महिला व्रतियों को भर मांग सिंदूर लगाया जाता है। बारी-बारी से सभी सूपों से भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता हैं। संध्या बेला में सूर्य भगवान के अस्त होने से पहले व्रती जल में उतरते हैं और स्नान करने के बाद हाथ जोड़कर साक्षात भगवान सूर्य आराधना करते हैं। ठीक सूर्यास्त होने से कुछ देर पहले प्रसाद से सजे हुए सूप को हाथों में लेकर भगवान भास्कर को पांच बार जल में ही परिक्रमा करते हुए पूरी श्रद्धा और भक्तिभाव से पहला सांयकालीन अर्घ्य दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य की पूजा करना भी इस पर्व की बहुत बड़ी विशेषता है। उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की रीति तो कई व्रतों और त्योहारों में है लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा केवल छठ पर्व में ही है।

● **ओम**

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_0/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

Add:- C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687

साख हो गई चूर-चूर

विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत खेली जा रही भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के दो मुकाबले में भारत को कीवी टीम ने बड़ा झटका देते हुए शिकस्त दी। न्यूजीलैंड सीरीज में 2-0 से आगे हो गया है। 36 साल में पहली बार न्यूजीलैंड की टीम ने भारत में टेस्ट मैच जीता है। लगातार 18 सीरीज जीतने के बाद भारत को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं भारत ने साल 2012 के बाद अपने ही घर में पहली बार कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। बेंगलुरु के बाद अब पुणे में भी भारतीय क्रिकेट टीम ने नाक कटवा दी है। पहले तेज पिच पर फ्लॉप हुए तो अब पुणे की स्पिन पिच पर फेल हो गए। न्यूजीलैंड की टीम ने इतिहास रचते हुए भारत को 113 रन से हरा दिया है। कीवियों ने इसी के साथ ही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीतने में सफल हुई है। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट मैच 1 नवंबर से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा।

1955 से न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा कर रही है, लेकिन कभी भी उसने यहां कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती थी। हालांकि अब वक्त बदल गया है। न्यूजीलैंड की युवा टीम ने टॉम लैथम की कप्तानी में 69 साल का सूखा खत्म करते हुए इतिहास रच दिया है। 69 साल में पहली बार कीवी टीम ने भारत को भारत में ही टेस्ट सीरीज में धूल चटाई है। न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पर कब्जा जमाते हुए 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यहीं से मैच पलट गया। इस मैदान पर अब तक टॉस जीतने वाली टीमें ही टेस्ट मैच में जीती थीं। अब फिर से एक बार ऐसा ही हुआ है। कीवी टीम ने पहली पारी में 259 रन बनाए। भारतीय टीम पहली पारी में 156 रन पर ढेर हो गई। न्यूजीलैंड को 103 रन की बढ़त हासिल हुई। उसने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर अपनी बढ़त 358 रन की कर ली। इस तरह टीम इंडिया को जीत के लिए 359 रन का टारगेट मिला। रोहित शर्मा की टीम 245 पर सिमट गई। 359 रन के टारगेट के सामने भारतीय बल्लेबाज बेबस नजर आए। यशस्वी जायसवाल ने उतरते ही काउंटर अटैक जरूर किया, लेकिन लगातार विकेट गिरने के कारण टीम इंडिया संभल नहीं पाई। यशस्वी ने 65 गेंद पर 77 रन बनाए। रोहित शर्मा 8, शुभमन गिल 23, विराट कोहली 17 और सरफराज खान 9 रन बनाकर आउट हुए। ऋषभ पंत खाता नहीं खोल सके। वॉशिंगटन सुंदर ने 21 रन बनाकर थोड़ी देर तक लड़ाई लड़ी। रविचंद्रन अश्विन 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। रवींद्र जडेजा ने आखिरी में 42 रन बनाए, लेकिन ये टीम के लिए काफी नहीं थे। न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटनर ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। उन्होंने पहली पारी में 7 विकेट लिए थे।

12 साल बाद घर में टीम इंडिया ने कोई टेस्ट सीरीज गंवाई है। आखिरी बार भारतीय सरजमीं पर इंग्लैंड ने टीम इंडिया के खिलाफ साल 2012 में खेली गई चार मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-1 से जीत हासिल की थी। साल 2012 में खेली गई टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने भारत के दिग्गज बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के बल्ले पर अंकुश लगाए रखा था। उस टेस्ट सीरीज में ज्यादातर मौकों पर सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग के फ्लॉप होने से भारतीय टीम को नुकसान झेलना पड़ा था। वहीं, इंग्लैंड की तरफ से तत्कालीन कप्तान एलिस्टेयर कुक और केविन पीटरसन रनों की बरसात कर रहे थे। एलिस्टेयर कुक और केविन पीटरसन ने उस सीरीज में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को बेअसर साबित कर दिया था।

वर्ष 2013 से मौजूदा वक्त तक 18 सीरीज जीतकर भारत के पास घरेलू मैदान पर लगातार सबसे अधिक टेस्ट सीरीज जीतने का रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया लगातार 10 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका ने 8 और 7 लगातार घरेलू श्रृंखला जीत हासिल की है। सितंबर में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच इकलौता टेस्ट मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। उसके बाद टीम श्रीलंका के दौरे पर गई जहां उन्हें 0-2 से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। वहीं सितंबर-अक्टूबर में खेले गए भारत-बांग्लादेश सीरीज को भारत ने 2-0 से क्लीन स्वीप किया था। लेकिन बीते दिनों के खेल में गेंद और बल्ले के जबरदस्त प्रदर्शन से न्यूजीलैंड ने बेंगलुरु टेस्ट जीतकर सीरीज की शानदार शुरुआत की है। यशस्वी ने शुभमन गिल (31 गेंदों में 23) के संग दूसरे विकेट के लिए 62 रन जोड़े। सेंटनर ने 16वें ओवर में गिल और 22वें ओवर में यशस्वी को आउट किया। यशस्वी ने 65 गेंदों में 9 चौकों और 3 छक्कों की मदद से 77 रन जुटाए। स्टार बल्लेबाज विराट कोहली (40 गेंदों में 17) एक बार फिर छाप छोड़ने में नाकाम रहे। उन्हें सेंटनर ने 30वें ओवर में एलबीडब्ल्यू किया। ऋषभ पंत का खाता नहीं खुला। वह रनआउट हुए। मैच में 11 विकेट चटकाने वाले ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर ने 47 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया।

● आशीष नेमा

टीम इंडिया का टूटा घर का गुमान

टीम इंडिया का घर का गुमान टूट गया है। भारत ने 12 साल बाद घर पर टेस्ट सीरीज गंवाई है। भारत को इससे पहले 2012 में इंग्लैंड के हाथों टेस्ट सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा था। इंग्लैंड ने तब चार मैचों की सीरीज 2-1 से जीती थी। बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट 1955 में खेला गया था। भारत का कीवी टीम के विरूद्ध ओवरऑल रिकॉर्ड शानदार है। दोनों ने आपस में अभी तक 64 टेस्ट खेले हैं, जिसमें भारत को 22 में जीत नसीब हुई। न्यूजीलैंड ने इस दौरान 15 टेस्ट में बाजी मारी और 28 ड्रॉ पर छूटे। हालांकि, मौजूदा सीरीज में रोहित ब्रिगेड उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सकी। पहले सेशन में न्यूजीलैंड की दूसरी पारी 255 रनों पर ऑलआउट हुई। न्यूजीलैंड ने 198/5 से आगे खेलते हुए 57 रन के भीतर पांच विकेट खो दिए। इसके बाद, यशस्वी जायसवाल ने लक्ष्य का पीछा करते हुए तूफानी बल्लेबाजी की। यशस्वी ने दूसरी गेंद पर ही छक्का लगाया। वहीं, कप्तान रोहित शर्मा (8) का बल्ला नहीं चला, जो छठे ओवर में मिचेल सेंटनर का शिकार बने। रोहित ने यशस्वी के संग पहले विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी की। लंच ब्रेक तक भारत ने एक विकेट पर 81 रन जोड़े लेकिन दूसरे सेशन में कीवी टीम हावी गई। सेंटनर ने खतरनाक बॉलिंग की।

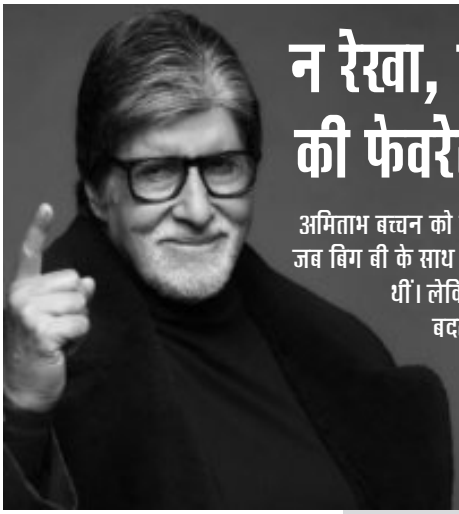

न रेखा, न हेमा और न ही जया, ये हैं अमिताभ बच्चन की फेवरेट हीरोइन, इस बात का है जीवन में अफसोस

अमिताभ बच्चन को दुनिया पसंद करती है। एक दौर वो भी था, जब बिग बी के साथ काम करने के लिए एक्ट्रेसेस मना कर देती थीं। लेकिन, एंग्री मैन की एक फिल्म से इमेज ऐसी बदली कि फिर उनके साथ काम करने के लिए हर एक्ट्रेस का सपना बन गया। क्या आप जानते हैं कि अमिताभ बच्चन की पसंदीदा एक्ट्रेस कौन हैं? और उन्हें किसके साथ काम न करने का मलाल है।

बिग बी ने सालों बाद केबीसी 16 के मंच पर इसका खुलासा किया है। महानायक ने इन बातों का जिक्र मोस्ट अवेटेड हॉरर कॉमेडी फिल्म भूल भुलैया 3 का प्रमोशन करने आई टीम से कही। अमिताभ ने कुछ राज खोले, जिसमें पसंदीदा एक्टर और जिंदगी के मलाल की बात थी। कार्तिक आर्यन और विद्या बालन बिग बी के अहम पलों को सुन हैरान रह गए।

ये एक्ट्रेस हैं बिग बी की फेवरेट

अमिताभ बताया कि वहीदा रहमान उनकी पसंदीदा एक्टर हैं और मीना कुमारी संग काम न कर पाने पर अफसोस जाहिर किया। वहीदा रहमान के बारे में बात करते हुए मेगास्टार ने बताया कि कैसे प्यासा के गाने के शॉट ने उनकी प्रतिभा को बाहर लाने का काम किया। बिग बी ने फिल्म प्यासा में एक्ट्रेस वहीदा रहमान के क्लोज-अप को भी याद किया, उन्होंने बताया कि उस सीन ने उन्हें काफी हद तक प्रभावित किया। बिग बी ने कहा यह कितना खूबसूरत शॉट था, उस क्लोज-अप शॉट को पूरा करने में दो या तीन टेक लगे। इन दिनों यह सब बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन तब ऐसा कभी नहीं होता था।

इस एक्ट्रेस संग काम न करने का है मलाल

बातचीत में बिग बी ने कई किस्से सुनाए। विद्या बालन और कार्तिक आर्यन के साथ बातचीत के दौरान अमिताभ ने 1962 की कल्ट फिल्म साहिब बीबी और गुलाम पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा, मुझे मीना कुमारी जी के साथ काम करने का कभी मौका नहीं मिला और इस बात का मुझे मलाल है। साहिब बीवी और गुलाम में एक गाना है - ना जाओ सैयां जिसमें उन्होंने इतना शानदार काम किया कि मैं उन्हें देखता रह गया। गौरतलब है कि हाल ही में अमिताभ बच्चन कल्कि मूवी में नजर आए थे।

जैकी की 1985 की वो सुपरहिट फिल्म, जिसमें कुत्ते ने लिया मालिक की हत्या का बदला

जैकी श्रॉफ ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर 80 के दशक की क्लासिक फिल्म के क्लिप के साथ एक वीडियो कोलाज शेयर किया। इसमें कुछ यादगार सीन शामिल हैं, जिसमें अभिनेता की इंटेंस डायलॉग डिलीवरी अदायगी और उनके ऑन-स्क्रीन पालतू कुत्ते ब्राउनी के साथ खास पल भी शामिल हैं।

मालिक की मौत का बदला लेता है कुत्ता

जैकी श्रॉफ ने इस पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा, हैशटैग 39 इयर्स ऑफ तेरी मेहरबानियां। बता दें, तेरी मेहरबानियां में पूनम ने जैकी के अपॉजिट लीड रोल निभाया था। तेरी मेहरबानियां के मुख्य किरदार जैकी श्रॉफ नहीं बल्कि उसका गोद लिया हुआ कुत्ता मोती है, जो राम के हत्यारों से बदला लेकर अपने मालिक का बदला चुकाता है। फिल्म में राम और मोती के बीच कुछ भावनात्मक पल हैं, जो राम के दर्द और मोती की वफादारी की झलक दिखाता है। अमरीश पुरी फिल्म में विलेन ठाकुर विजय सिंह बने थे।

डबल रोल में हीरो और कॉमेडियंस की फौज, मुंह के बल गिरी थी ये 150 करोड़ी मूवी

बॉक्स ऑफिस पर फिल्मों के हिट और फ्लॉप होने का खेल चलता रहता है। कई बार तो बड़ी लागत में बनी फिल्में भी बुरी तरह पिट जाती हैं। ऐसा ही कुछ एक बिग बजट मूवी के साथ हुआ था। लंबी-चौड़ी स्टार कास्ट से सजी फिल्म की कहानी ऑडियंस को पसंद नहीं आई थी। उस मूवी का नाम है सर्कस।

बिल्कुल नहीं चल पाया जादू...

कॉमेडी-ड्रामा फिल्म सर्कस साल 2022 के दिसंबर में महीने में रिलीज हुई थी। इसमें रणवीर सिंह डबल रोल में नजर आए थे। रोहित शेट्टी ने सर्कस का डायरेक्शन किया था। यह मूवी भारी-भरकम बजट में बनी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सर्कस पर 150 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। हालांकि ऑडियंस ने फिल्म को एक झटके में रिजेक्ट कर दिया था। रोहित शेट्टी एंटरटेनिंग मसाला फिल्में बनाने के लिए जाने जाते हैं और उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट होती है, लेकिन इस बार बॉक्स ऑफिस पर उनका जादू बिल्कुल भी नहीं चला।

बात समझ में आई

अजीब सा सवाल था- उनका, सारा दिन घर पर करती क्या हो? पतिदेव की यह बातें सच में कांटे की तरह चुभ रही थी मुझे। हैरान थी मैं उनकी बातों को सुनकर। कैसे बताती मैं उनको सारा दिन घर पर क्या-क्या काम रहता है, और किन-किन कामों में व्यस्त रहती हूं। मन तो बहुत गुस्से में था, और क्रोध की ज्वाला अंदर फूट रही थी। और अंदर ही अंदर में उनकी बातों से घुट रही थी। बस इतना ही तो कही थी मैं, सामान जगह पर रखें, इधर-उधर बिखेरे नहीं। कभी-कभी अपने से भी कुछ काम कर लिया करें। मुझे इतनी परेशानी तो नहीं होगी, क्योंकि मैं सारा दिन घर में काम कर-करके थक जाती हूं। वह तो मेरी सुने नहीं, और उल्टा ही मुझसे सवाल कर बैठे, सारा दिन घर पर करती क्या हो? मैंने भी तय कर लिया, इन्हें सब कुछ दिखा के रहूंगी, और रास्ते पर लाकर रहूंगी।

अगले ही दिन मैं कमर दर्द का बहाना करके बिस्तर पर लेटी रही। ओर जोर-जोर से चिल्लाती रही, उई मां मुझसे उठा नहीं जा रहा है, बहुत तेज दर्द हो रहा है। पतिदेव घबराते हुए उठे ओर जल्दी से झंडू बाम लेकर कमर दर्द पर मालिश करने लगे। और मुझसे पूछे अगर आराम लग रहा है, तो मेरे लिए एक कप चाय बना दो। मैंने कहा नहीं, आप तो मेरी हालत देख ही रहे हैं, और क्या स्थिति है हमारी। काश... हर रोज की तरह आज मेरी तबीयत ठीक रहती, तब इन्होंने कहा- कोई बात नहीं मैं खुद ही चाय बना लेता हूं। कुछ देर के बाद वे अपने लिए और मेरे लिए चाय बना के लाए। और मैंने चाय पीकर कप बेड पर ही रख दिया। कुछ देर के बाद फिर वो मेरे पास आए, और बोले- 8 बज चुका है, जल्दी से उठो, बच्चों का स्कूल का टिफिन और मेरे लिए ऑफिस का लंच बना दो। मैं उनकी बातों को सुनकर उठी और दर्द का बहाना करके फिर से लेट गई। और बोली आज मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ऐसा कीजिए आज आप ऑफिस से छुट्टी ले लीजिए। और आज आप घर पर ही रहिए, क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा।

पतिदेव ने मेरी बातें मान लीं। और बच्चों का टिफिन बनाकर, उन्हें तैयार करके बस स्टॉप पर छोड़ने गए। उधर से आए फिर नाश्ता बनाए। और मुझे नाश्ता परोस के दिए और खुद भी नाश्ता किए। मैं नाश्ता करके फिर से बेड पर लेट गई। फिर वो बर्तन धोकर, दोपहर का खाना बनाने में जुट गए। खाना बनाने के बाद, बच्चों को लाने गए। बच्चे आते ही शोर मचाने लगे, और कपड़ा इधर-उधर खोलकर फेंक दिए। घर बिखरा-बिखरा लगने लगा। इन्हें देखा नहीं जा रहा था फिर उन्होंने मुझसे कहा, जरा ठीक कर दो ना रूम को। मैं दर्द का बहाना करके बोली, आज मुझसे कुछ नहीं होगा, क्यूंकि मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा है। आप ठीक कर दीजिए रूम को प्लीज। यह बोले ठीक है मैं ठीक कर देता हूं रूम को।

उसके बाद बच्चों को खाना खिलाया, खुद भी खाए, और मुझे भी खाना परोस के दिए। मैं दर्द का बहाना बनाकर खाना खाकर फिर से लेट गई। और मैंने टेबल पर ही जूठी थाली रख दी। इन्हें बड़ा अजीब लग रहा था, मुझे देखकर, आखिर खाना तो ठीक से खाती है, मगर घर का काम करते वक्त बहाना क्यूं बनाती है? अब तो मुझसे कोई काम नहीं होगा, बहुत कर लिया सुबह से काम, अब मैं भी आराम करूंगा। और लेटने जा रहा हूं, बिस्तर पर। और कल ही ऑफिस ज्वाइन करूंगा। यदि घर पर रहूंगा तो, मैं चैन की सांस भी नहीं ले पाऊंगा। इतने सालों से मेरी वाइफ सारा काम कर रही थी। आज पता नहीं मैडम जी कमर दर्द का बहाना क्यों कर रही हैं? अभी वह मन ही मन सारी बातें सोच ही रहे थे। ओर मैं भांप रही थी इनके मन को।

तब तक बच्चे आ गए, और पापा-पापा करके इन्हें उठाने लगे। और बोलने लगे, पापा मुझे जोरों से नींद आ रही है। मुझे आप सुला दो ना। तभी ये कहने लगे मैं काम करते-करते थक गया हूं। आप मम्मा को बोलो ना वो, आपको सुला देगी। दोनों बच्चे जिद करने लगे, नहीं पापा आज मुझे आप सुलाओगे...। कल से स्कूल से जब में घर पर आऊंगा, तब मम्मा हमें सुलाएगी। आज मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, आप मुझे सुला दो। इन्होंने बच्चों की बात मान ली और उन्हें सुलाने लगे। मैं नींद की झपकी मार मारकर सब देख रही थी। अभी वो, बच्चों को सुलाकर कुछ देर नींद की झपकी ली ही थी कि, तब जोरों से बारिश शुरू होने लगी। मैंने इन्हें उठाया, और कहा- कपड़े छत पर हैं, और बारिश में भींग जाएंगे। इन्हें तो बहुत जोरों से गुस्सा आ रहा था मेरी बातें सुनकर, लेकिन ये करते क्या क्यूंकि घर तो इन्हें संभालना था। मैं तबीयत का बहाना करके जो बैठी थी। ये जल्दी से कपड़े छत से लाए, और घर के ही आंगन में उसे सूखने दिए। और आराम करने के लिए लेट गए।

शाम भी हो रही थी और सूरज भी ढल चुका था। रोज की तरह आज भी इन्हें चाय पीने का मन हुआ, और इन्होंने कहा मुझसे एक कप चाय बना दो। मैंने कहा- मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप खुद ही चाय बनाके पी लो। ये मेरी बातें सुनकर गुस्से से आग बबूला हो गए, और मुझ पर बरस पड़े। तुम्हें शर्म नहीं आती है, ये बोलते हुए कि मैं खुद ही चाय बनाकर पी लूं। जबकि तुम देख रही हो। सारा दिन घर पर काम करता रहा। दस मिनट का भी आराम नहीं कर पाया। तभी मैं बोली- बात समझ में आई, घर पर कितना काम रहता है। रोज मुझसे आप सवाल करते हो कि सारा दिन घर पर करती क्या हो? समझ में आया घर पर कितना काम रहता है। आप सुबह 9 बजे ऑफिस जाते हो, ओर शाम को 6 बजे घर चले आते हो। ओर उसके बाद मैं आपके लिए चाय-नाश्ता बनाती हूं। आप आराम से चाय पीते हो नाश्ता करते हो, टीवी देखते हो, और फिर सोने जाते हो। पर मैं कब आराम करती हूं, सुबह 6 बजे उठती हूं, और सारा दिन घर का काम करती रहती हूं। और रात के 11 बजे सोने जाती हूं। आपकी संडे छुट्टी भी रहती है, लेकिन मेरी कब छुट्टी होती है घर पर। बल्कि और ज्यादा काम रहता है। आप तो हर त्यौहार पर छुट्टी मनाते हो। पर मेरी कौनसी त्यौहार पर छुट्टी रहती है। त्यौहार पर तो मुझे ओर ज्यादा काम रहता है। क्योंकि उस दिन घर मेहमान से भरा रहता है। और आप कहते हो कि सारा दिन घर पर करती क्या हो?

ये मेरी बातें ध्यान से सुन रहे थे। ओर इन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो रहा था, और इनके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था। इसलिए मैंने बातों की चुटकी ली ओर बोली मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और मुझे कोई कमर दर्द नहीं है, बल्कि ये तो एक बहाना था, और काम का नमूना दिखाना था। इतना बोलकर अभी मैं भाग ही रही थी, इन्होंने मुझे कसकर पकड़ लिया, ओर अपनी बाहों में जकड़ लिया। और मुझसे बोले, मैडम जी, तुम बहुत होशियार निकली, मैं बोली- हां, अब से कोई सवाल नहीं करना, नहीं तो इससे ज्यादा काम करवाऊंगी। ये बोले- कोई सवाल नहीं करूंगा आपसे, बल्कि सलाम करता हूं, आपको भी, और आपके काम को भी, और उन गृहिणियों को भी जिनसे घर चलता है।

● **रीना सोनालिका**

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

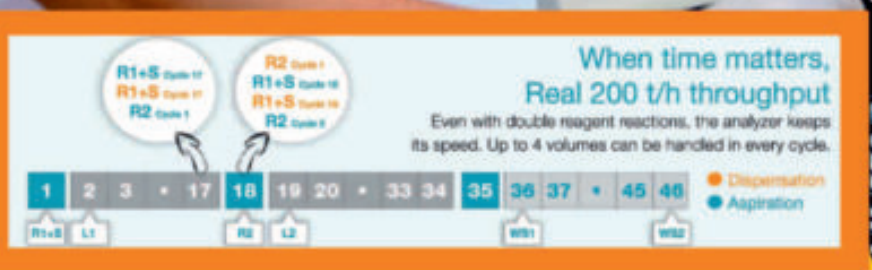

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

उन्नति और खुशहाली की ओर
निरंतर बढ़ते कदम

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

सुशासन से समृद्धि

कमजोर वर्ग के साथ प्रदेश सरकार

सशक्त बनती नारी शक्ति

अन्नदाता के जीवन में आयी खुशहाली

युवा कल्याण के सतत् प्रयास

समावेशी शिक्षा से संवरता कल

औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन

स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार

तेज गति से अधोसंरचना विकास

आर्थिक समृद्धि की ओर बढ़ता मध्यप्रदेश

सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक अभ्युदय

गौ-संरक्षण एवं संवर्धन

स्वच्छ भारत अभियान में मध्यप्रदेश बना सिरमौर

अन्य उपलब्धियां

मध्यप्रदेश शासन